साइरस मिस्त्रीः टाटा कहने का समय

जलवायु संकट पर जॉन केरी से बातचीत

मुलायम परिवारः गहरी होती दरार

OC

9 770971 372703

28 अप्रैल, 2021 40 रुपए

इंडिया टुडे

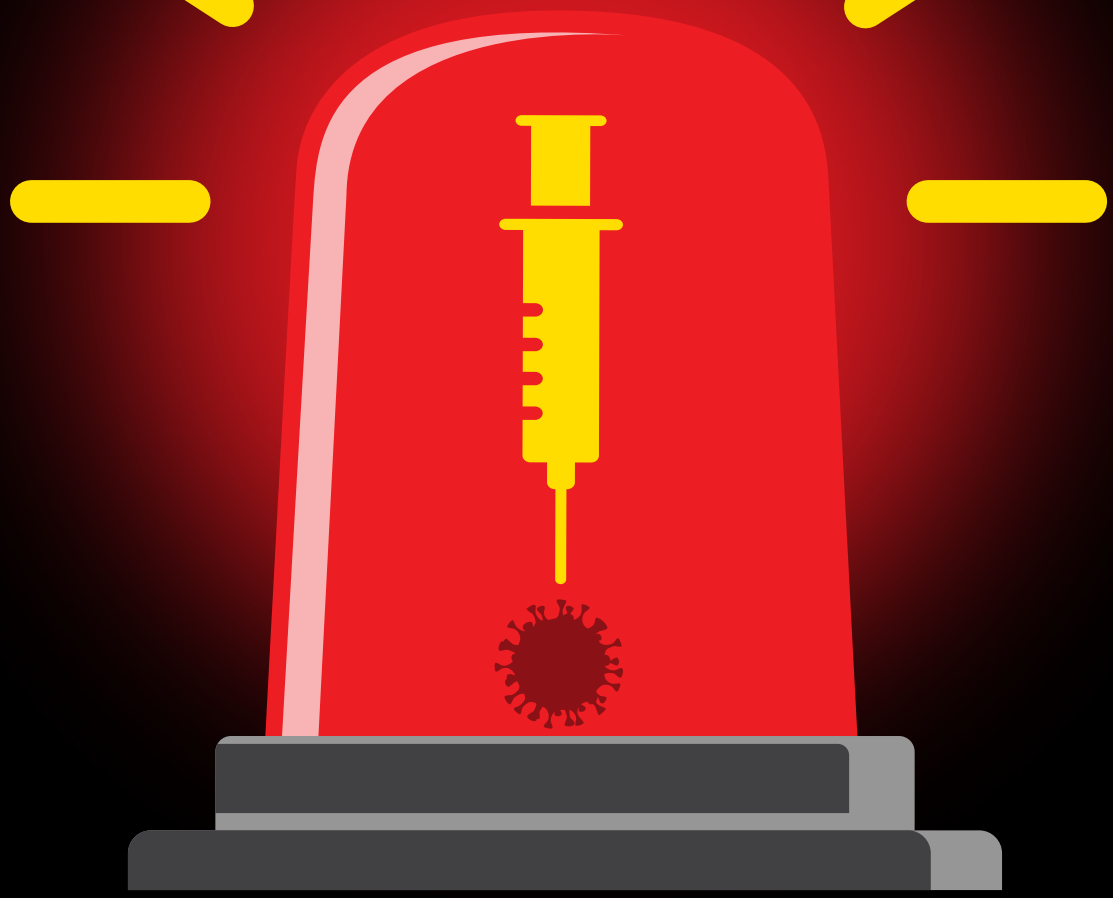

कोविड-19

टीके का आपातकाल

भारत की टीकाकरण की रणनीति में आखिर दिक्कत कहां है और किस तरह उसे पटरी पर लाया जाए

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

www.indiatodayhindi.in

VISIT…

INDIA TODAY

We tell the story

Not the moral of the story

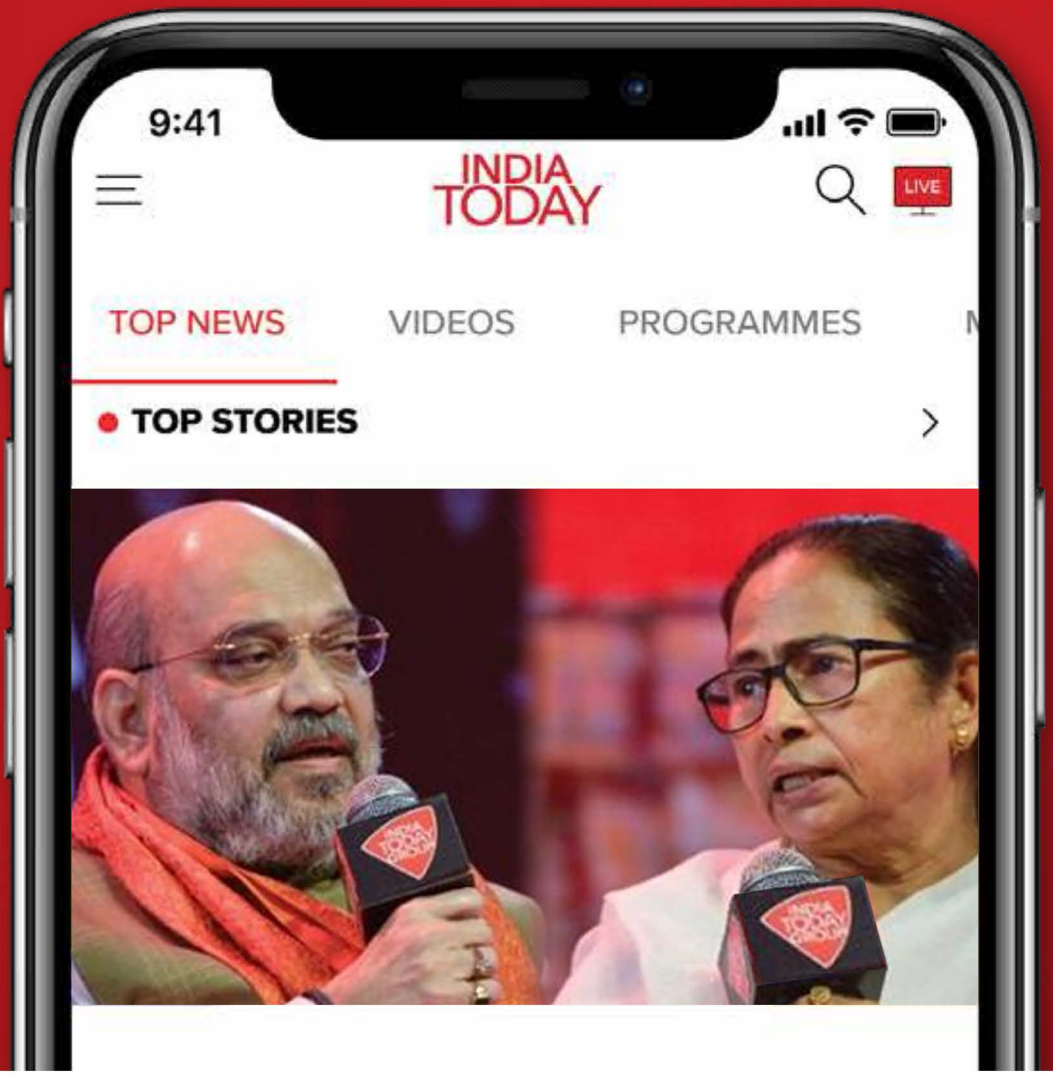

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

प्रधान संपादक की कलम से

भारत ने अक्सर जीत के जबड़े से हार खींच लाने का रुझान दिखाया है. कोविड-19 महामारी से निबटने के तरीके में भी यही मालूम देता है. 1 फरवरी को भारत में 8,500 नए मामले थे, जो 8 जून 2020 के बाद सबसे कम थे. 13 अप्रैल को ये चढ़कर एक दिन में 1,80,000 नए मामलों पर जा पहुंचे, जो महामारी की शुरुआत के बाद सबसे ऊंचा स्तर था. बदकिस्मती से यह ऐसा करतब है जो देश 6 अप्रैल से रोज कर रहा है. कोविड-19 वायरस का पिछले हफ्ते आया उभार अब सुनामी में बदल गया है. 13 अप्रैल की गिनती के बाद हमारे कुल सक्रिय मामले 12 लाख के पार पहुंच गए. हमारे कुल कोविड मामले भी 1.37 करोड़ पर जा पहुंचे, जो दुनिया भर में अमेरिका के 3.13 करोड़ मामलों के बाद दूसरे सबसे ज्यादा हैं.

तूफान से पहले की शांति को हमने गलती से उसका गुजर जाना मान लिया और रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हो गए—धार्मिक जमावड़ों और राजनैतिक रैलियों की तो बात ही छोड़ दें. उससे भी हमारे राजनैतिक तबके के दोहरे मानदंड उजागर होते हैं. संक्रमण आसमान छू रहे थे और देश के कुछ हिस्सों में नागरिक कर्फ्यू झेल रहे थे, वहीं इन विशाल जमावड़ों पर कोई रोक-टोक नहीं थी और उनमें कोविड के नियमों का पालन भी बमुश्किल किया जा रहा था. यही ढिलाई और लापरवाही अब भारी कीमत वसूल रही है. हर दिन मनहूस खबरें लेकर आता है और भारत की चीखें खुद वायरस की तरह कई गुना बढ़ती जाती हैं. ज्यादा बड़ी फिक्र है कि तमाम शहरों को बेध रही यह लहर उस आबादी को संक्रमित कर रही है जो पहली लहर में अछूती रह गई मालूम देती थी—यानी 15 से 44 की उम्र के लोग.

22 जुलाई, 2020 का आवरण

मुंबई के एक अव्वल अस्पताल में लिफ्ट के आसपास की जगह मरीजों के वार्ड में बदलनी पड़ी. दुनिया के सबसे कठोर लॉकडाउन के 68 दिनों में मेहनत से तैयार भारत का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द चरमरा सकता है. भारत के आर्थिक शक्तिकेंद्र महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगा दिया है. पिछले साल हमने देखा कि लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं, पर शायद यह सिर्फ समय की ही बात हो जब वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यही अकेला विकल्प बचे. भारत यह विकल्प गवारा नहीं कर सकता. इससे लाखों लोग अकथ मुसीबतों से घिर जाएंगे.

समाधान बेशक यही है कि बड़ी आबादी को तेजी से टीके लगाएं. वायरस के धक्के को धीमा तथा संक्रमण, गंभीर बीमारी और मौत के जोखिम को कम करने के लिए टीका अकेला अचूक उपाय है. हर्ड इम्यूनिटी पर पहुंचने के लिए भारत को 75 फीसद आबादी या 99 करोड़ लोगों को टीके लगाने होंगे. यानी हमें 1.98 अरब खुराकों (वैक्सीन की दो खुराक के लिए) की जरूरत है. फिलहाल रोज 40 लाख लोगों को टीके लग रहे हैं. हमें टीकाकरण की रफ्तार 2 करोड़ रोजाना तक बढ़ाना और हर महीने 60 करोड़ टीकों की नियमित सप्लाई बनाए रखना होगा, जबकि हमारी मौजूदा क्षमता 8-10 करोड़ प्रति माह है. काम दुष्कर है और सरकार को तैयार रहना ही होगा. टीकाकरण बढ़ाने को हमारे पास न पर्याप्त खुराकें हैं, न ही भविष्य का रास्ता साफ है. समझ नहीं आता दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश इस हालत में क्यों है. यह वैसा ही है जैसे सऊदी अरब अपने लोगों से कहे कि उसके पास उनके लिए तेल नहीं.

भारत की दिग्गज फार्मा कंपनियां वैक्सीन की सालाना 3 अरब खुराकें बना सकती हैं. दूरदृष्टि की कमी, निर्यात के वादों, देरी से मिले ऑर्डरों, बेहद केंद्रीकृत तरीके और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन के अभाव के चलते तीन महीनों में महज 11 करोड़ खुराकें मिल पाईं. सरकार ने 12 करोड़ और वैक्सीन का ऑर्डर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के दो महीने बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में दिया. महामारी के प्रति अपने सारे सिनिसिज्म के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने फाइजर को 10 करोड़ खुराक के लिए 2 अरब डॉलर दे दिए थे और वैक्सीन कामयाब होने पर 50 करोड़ खुराकें और लेने का विकल्प रखा था. अमेरिका के पास इतनी खुराकें है कि अपनी पूरी आबादी को दो बार टीके लगा सकता है.

हमारे टीका अभियान के शुरुआती दौर में वैक्सीन की हिचक से उबरने को लेकर संवाद की भीषण कमी के चलते कुछ राज्यों में 8-9 फीसद टीके बर्बाद हुए. यह साफ था कि अर्थव्यवस्था के फिर शुरू होते ही संक्रमण बढ़ेंगे, जैसा दुनिया के कई हिस्सों में हुआ. हमें पता है कि हम दुनिया के शायद सबसे कम अनुशासित राष्ट्र हैं और नियम तोड़ या उन्हें चकमा देकर खुश होते हैं. फिर जिस तरह हर देश आपातस्थिति के लिए तेल या कोयले सरीखे ऊर्जा स्रोतों का भंडार रखता है, उसी तरह जब मांग कम थी, हम वैक्सीन का रिजर्व स्टॉक रख सकते थे. भारत की वैक्सीन के लिए बस रेफ्रिजरेटर चाहिए और सरकार आसानी से छह माह का भंडार रख सकती थी. इसके बजाय हमने 6 करोड़ वैक्सीन निर्यात कीं जबकि हमारे अपने लोगों को केवल 7 करोड़ खुराकें दी गईं.

हमारी वैक्सीन रणनीति से आत्मसंतोष और बहुत ज्यादा सरकारी नियम-कायदों की बू आती है. वैक्सीन की कमी के चलते भारत को टीकाकरण सबके लिए खोल देने की बजाय टुकड़ा-टुकड़ा रणनीति अपनानी पड़ी. निजी क्षेत्र को वितरण में शामिल न करने से भी रुकावटें आईं. दिसंबर में 16 वैक्सीन क्लिनिकल और प्री-क्लिनिकल परीक्षणों के दौर में थीं, फिर भी भारत के दवा नियंत्रक को परीक्षण तेज करने के नियम संशोधित करने में चार माह लगे. विकसित देशों में कई वैक्सीन व्यापक परीक्षणों से गुजरीं और उनके दवा नियंत्रकों से मंजूर हुईं, जिनके इस्तेमाल को भारत में फास्ट-ट्रैक किया जा सकता है. रोज 40 लाख लोगों को टीका लगाने की मौजूदा रफ्तार से 30 करोड़ लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य मध्य जुलाई तक पूरा होगा और 75 फीसद आबादी को टीके लगाने में डेढ़ साल लगेंगे. तब तक पूर्ण टीकाकृत लोगों की सुरक्षा अवधि खत्म होने लगेगी, उन्हें फिर टीके लगाने होंगे.

एसोसिएट एडिटर सोनाली आचार्जी की लिखी इस बार की हमारी आवरण कथा 'टीके का आपातकाल' बताती है कि भारत में मौजूदा संकट कैसे उपजा, तमाम पहलुओं ने टीका रणनीति को कैसे बेपटरी किया, वैक्सीन के पात्रों की संख्या में बढ़ोतरी और मामलों के उभार ने कैसे मांग बढ़ाई, उत्पादन क्षमता को पछाड़ा और वैक्सीन का भंडार खत्म कर दिया.

सरकार अब जागी दिखती है और टीकों का निर्यात कर रही है. पर हमने अहम वक्त गंवा दिया. इन उपायों का असर आने में 3-4 महीने लगेंगे. सरकार को वैक्सीन उत्पादन के लिए सब्सिडी देकर, धन खर्च करके और क्षमता बढ़ाकर टीकाकरण तेज करने की जरूरत है. उसे चाहिए कि तेजी से टीके लगाने को दूसरी फार्मा कंपनियों को जोड़े, सरकारी संसाधन लगाए, निजी क्षेत्र को तैनात करे. वह भी तीसरी लहर आने से पहले.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरु)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 22; 22-28 अप्रैल, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

सुर्खियां

डीबीटी: किसानों के फायदे का सौदा
पेज 05

अर्थात्: घुटती सांसों का 'उत्सव'
पेज 13

भीतर

फुरसत

पत्रिका: वैचारिक परिवार गढ़ा था *पहल* ने
पेज 46

सवाल-जवाब/कौशिकी चक्रवर्ती: बेचैनी और बैंड
पेज 50

इलस्ट्रेशन: नीलांजन दास

आवरण कथा

अब टीके का संकट

कोविड की दूसरी जानलेवा लहर ने भारत की आशावादी टीकाकरण रणनीति की पोल खोलकर रख दी है. आखिर गड़बड़ कहां हुई और अब इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है?

जलवायु परिवर्तन

30 बातचीत: जॉन केली

जलवायु संबंधी मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत से संवाद

पनडुब्बी

40 भारत की एटमी शार्क

लंबे अरसे बाद एटमी क्षमता वाली हमलावर पनडुब्बियों का रास्ता हुआ साफ

मुलायम परिवार

37 गहरी होती दरार

पार्टी के शीर्ष नेता के अशक्त पड़ने से कुटुंब में सियासी तकरार बढ़ने लगी

बंगाल की जंग

08 किस पथ वामपंथ

कांग्रेस के साथ वामपंथियों के संयुक्त मोर्चे को सत्ता के खेल में निर्णायक माना जा रहा

सिनेमा

48 महागाथाओं का नया उभार

हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रति भारतीय फिल्म उद्योग का प्रेम अपने उफान पर

आवरण: नीलांजन दास

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

बंगाल की जंग:
किस पथ वामपंथ
पेज 8

सुर्खियां

उत्तराखंड:
उलटे फैसले
पेज 11

मुद्रा मंत्र:
दुबला होता रुपया
पेज 12

खरीद सीजन
कोविड लॉकडाउन के दौरान मई, 2020 में अमृतसर की मंडी में गेहूं ट्रक पर लादे जाने का दृश्य

प्रभजोत गिल

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

किसानों के फायदे का सौदा

अनिलेश एस. महाजन

शायद पंजाब सरकार केंद्र सरकार की ओर से डाले जा रहे दबाव में आ गई और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था. ऐसे में अब वह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की तरफ मुड़ गई है जिसके जरिए वह इस सीजन में किसानों से अनाज की खरीद करेगी. केंद्रीय एजेंसियों के लिए अनाज और कृषि उपजें खरीदने वाले पंद्रह और राज्यों ने भी किसानों को सीधे नकद भुगतान शुरू किया है या फिर कम से कम वे सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत हैं. इससे आढ़तियों के जरिए किसानों को भुगतान करने वाली बरसों पुरानी परंपरा खत्म हो रही है.

कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) मंडियों में आढ़तिए कारोबार में मदद करते हैं और इसके बदले में शुल्क लेते हैं. पंजाब में कृषि उपज पर कुल मार्केट चार्ज फसल के मूल्य का 9.5 फीसद है, जिसमें 2.5 फीसद कमीशन आढ़तियों को दिया जाता है. राज्य के किसान संगठन जो नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस आढ़तिया व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं.

केंद्र से दबाव के बीच हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने 1 अप्रैल को डीबीटी व्यवस्था की शुरुआत की, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार इसे किसान संगठनों के बिफरने के डर से टाल रही थी. 8 अप्रैल को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब के खाद्य मंत्री भारत भूषण आशु और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के साथ बैठक में राज्य को डीबीटी मॉडल अपनाने का दबाव डालते हुए कहा कि ऐसा न होने पर आगे कोई आवंटन नहीं किया जाएगा. पंजाब के आढ़तिया एसोसिएशन

ने तुरंत रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं खरीद का बहिष्कार करने की चेतावनी दी, जिसकी शुरुआत 10 अप्रैल से हो रही है. हालांकि, कई एजेंटो ने अमरिंदर से आश्वासन मिलने के बाद अपना विरोध वापस ले लिया.

हरियाणा में स्थिति उतनी जटिल नहीं है. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) अब तक राज्य के किसानों के बैंक खातों में भुगतान सीधे ट्रांसफर करता आया है. अपने गोदामों के लिए सरसों, बाजरा और अन्य फसलों की खरीद के लिए हरियाणा की एजेंसियों ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को थोड़ा सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किया है और कुछ हिस्सा आढ़तियों के जरिए.

पंजाब के अफसरों का कहना है कि पिछले सीजन के 12 लाख किसानों का डेटाबेस पंजाब के अनाज खरीद पोर्टल पर है जिसका इस्तेमाल डीबीटी ट्रांसफर के लिए किया जाएगा. पंजाब और हरियाणा को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) मिलती है जिससे वह केंद्र की तरफ से भुगतान करती है. इसमें आढ़तियों को दिया जाने वाला कमीशन भी शामिल होता है. 6 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने मौजूदा सीजन में गेहूं की खरीद के लिए पंजाब को सीसीएल की मद में 21,658 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए. केंद्र का लक्ष्य इस बार 1.25 करोड़ टन गेहूं की खरीद का है जिसके लिए एमएसपी 1,975 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है और जो पिछले साल से 50 रु. अधिक है.

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की ओर से स्टॉक की खरीद होती है तो इस मूल्य श्रृंखला में राज्य की एजेंसियां भी तकनीकी रूप से शामिल हो जाती हैं और उन्हें उस श्रृंखला में शामिल सभी हितधारकों को सीधे भुगतान करना चाहिए, जिसमें किसान और आढ़तिए दोनों शामिल हैं. कुछ केंद्रीय मंत्रियों का मानना है कि अधिकतर किसान संगठनों की फंडिंग धनी आढ़तिए कर रहे हैं, जिन्हें डर है कि नए कृषि कानूनों से निजी पूंजी आएगी और कृषि उपजों पर उनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा. दिल्ली में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का तर्क है कि कई किसान संगठन लंबे समय से डीबीटी की मांग कर रहे थे और हरियाणा तथा पंजाब के छोटे और सीमांत किसान इसका स्वागत करेंगे.

तजामुल हक जैसे कृषि अर्थशास्त्री कहते हैं कि एपीएमसी एकाधिकार की वजह से दोनों राज्यों में किसानों को प्रतियोगिता के फायदे नहीं मिल रहे हैं, जिससे उन्हें पैदावार की बेहतर कीमत मिल सकती थी. किसान कार्यकर्ता और खेती विरासत मिशन (केवीएम), पंजाब के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र दत्त जोड़ते हैं कि इन वजहों से किसान एमएसपी वाली फसलों मसलन धान और गेहूं पर अटके रहते हैं.

नए कृषि कानूनों में कृषि व्यापार से सभी अतिरिक्त शुल्कों को हटाने का प्रावधान है ताकि उपज की बेहतर कीमत मिल सके. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनकारी किसानों को लिखित में आश्वासन देते हुए इन शुल्कों को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया था लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया. विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने अमरिंदर सरकार पर डीबीटी के मसले पर किसानों और आढ़तियों को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है, लेकिन राज्य के आला मंत्री ने आढ़तियों को पूरी तरह खत्म करने की किसी भी कोशिश से इनकार किया है.

2.5%
कमीशन उपज के मूल्य का पंजाब में आढ़तियों के हिस्से में जाता है

12 लाख
ऐसे किसानों को डीबीटी का फायदा होगा जो पंजाब अनाज खरीद पोर्टल से जुड़े हैं

15-24%
ब्याज सालाना आढ़तिये वसूलते हैं किसानों को दिए कर्ज की रकम पर

2012 से लेकर केंद्र सरकार किसानों को सीधे नकद भुगतान की कोशिशें कर रही थी. हालांकि, अधिकतर राज्य इस पर राजी थे लेकिन प्रदर्शन कर रहे आढ़तियों ने पंजाब और हरियाणा को सतर्कता भरा रुख अपनाने को बाध्य किया. पिछले सीजन में हरियाणा के आढ़तिए हड़ताल पर चले गए थे और उन्होंने अस्थायी तौर पर ही सही, सरकार को मजबूर कर दिया कि वह अस्थायी तौर पर डीबीटी भुगतान रोके जबकि पंजाब ने महामारी की जटिलताओं का हवाला देकर डीबीटी भुगतान रोके रखा.

असल में, डीबीटी से आढ़तियों और किसानों के बीच का बरसों पुराना रिश्ता टूट जाएगा. पंजाब में कोटकपुरा के आप विधायक कुलतार सिंह संधवान कहते हैं, ''पूंजी की कमी होने पर आढ़तिए किसानों को कम ब्याज पर कर्ज देते हैं और ऐसा करना बैंकों के लिए नामुमिकन होगा.'' पारंपरिक तौर पर राज्य आढ़तियों को ही एमएसपी और कमीशन का भुगतान करता है जो अपने एडवांस की रकम काट कर बाकी की रकम किसानों को दे देते हैं. आढ़तियों को भुगतान पाने के 48 घंटों के भीतर किसानों को रकम देनी होती है. हालांकि, आढ़तिए खुद महाजनों में बदल गए थे और बैंकों, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के उलट उनका नियमन नहीं था. वे कर्जों पर 15 से 24 फीसद तक सालाना ब्याज वसूलते हैं जबकि वित्तीय संस्थाएं 8 फीसद तक ब्याज लेती हैं.

2011 में आइआइएम अहमदाबाद के प्रोफेसर सुखपाल सिंह और पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के अकादमिशियन तेजिंदर धालीवाल के एक अध्ययन में पाया गया कि कुछ आढ़तिए खुद ही पंसारी, चावल गोदामों के मालिक, बीज, कीटनाशक और उर्वरक विक्रेता सबकी भूमिका में हैं और इस तरह किसानों पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है. आरोप यह भी हैं कि आढ़तिए और कुछ बड़े किसान मिलकर गेहूं और धान दूसरे राज्यों से सस्ता खरीदकर लाते हैं और उन्हें पंजाब और हरियाणा में मुनाफे में बेच देते हैं.

यही वजह है कि डीबीटी के मुद्दे पर प्रदर्शनकारी किसान भी बंटे हुए हैं. किसान नेता दर्शनपाल ग्रेवाल और जोगिंदर सिंह उग्रहान डीबीटी के समर्थन में हैं लेकिन वे टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं. कृषि कानूनों के खिलाफ बने संयुक्त किसान मोर्चा ने गोयल के मंत्रालय को डीबीटी जल्दबाजी में लागू करने पर चेतावनी दी है. मंत्रालय ने पंजाब सरकार को खरीद की रसीदों समेत जमीन के मालिकाना हक, किराया या बटाईदारी से जुड़े दस्तावेज समेत भू अभिलेखों को लिंक करने के लिए छह महीने का वक्त दिया है.

पंजाब ऐंड सिंध बैंक के चेयरमैन चरण सिंह कहते हैं, आसान कर्जों के लिए किसान आढ़तियों के पास जाते हैं लेकिन 'संसाधनों की कमी' वजह नहीं होती. अभी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड और ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक जैसे विकल्प हैं. अनुमान के मुताबिक, पंजाब के बैंकविहीन गांवों में आढ़तिए 65 फीसद तक कर्ज देते हैं जबकि एक या अधिक बैंक वाले गांवों में 55 फीसद तक कर्ज आढ़तिए ही बांटते हैं. सिंह कहते हैं, ''कोऑपरेटिव बैंकों के नेटवर्क को सुधारने की सख्त जरूरत है.'' केंद्र को उम्मीद है कि डीबीटी किसानों को आढ़तियों के शिकंजे से बाहर निकालेगी. इसके लिए वित्तीय संस्थानों तक किसानों की आसान पहुंच बनाने की जरूरत है पर यह एकाएक होने से रहा.■

राजस्थान उपचुनाव

अभी टला नहीं संकट

रोहित परिहार

राजस्थान में अपनी ही पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में विद्रोह कर दिया था. उसमें पायलट को भाजपा का समर्थन प्राप्त था. इसके मद्देनजर राज्य में 17 अप्रैल को राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में होने वाले तीन उपचुनाव गहलोत के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. राज्य की विधानसभा में 200 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास 104 और भाजपा के पास 71 सीटें हैं. कांग्रेस के छह विधायक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से टूटकर आए हैं. कांग्रेस में उनके शामिल होने के निर्णय को चुनौती दी गई और यह मामला अदालत में विचाराधीन है. इससे सदन में कांग्रेस की स्पष्ट ताकत 98 रह जाती है, जो आधे से दो कम है.

गहलोत कोई कोताही नहीं कर रहे. वे फरवरी से ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इन तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में 158 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू कर चुके हैं. 7 अप्रैल को उन्होंने सरकारी सेवाओं की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी. पुरुषों को पांच साल और महिलाओं को 10 साल की छूट प्रदान की गई और इस तरह उन्हें अन्य आरक्षित श्रेणियों के बराबर लाया गया.

वहीं, राज्य कांग्रेस पूरी एकजुटता दर्शाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए गहलोत तथा पायलट दोनों का एक-साथ प्रचार अभियान सुनिश्चित कराया जा रहा है. पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं और कांटे की चुनावी टक्कर में जाति आधारित मतदान निर्णायक साबित हो सकता है. पर कांग्रेस में विभाजन दिख जाता है. पायलट के वफादारों को इसलिए नाराज बताया जाता है कि अपना विद्रोह खत्म करने के बावजूद उन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया. उदाहरण के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिए गए रमेश मीणा ने धमकी दी है कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्हें मुलाकात का समय नहीं देते तो वे पार्टी छोड़ देंगे. गांधी ने बगावत पर अपनी नाराजगी जताई थी और पायलट या उनके किसी भी वफादार से मिलने से इनकार कर दिया. उन्होंने फरवरी में राजस्थान में किसानों की रैलियों में पायलट के अनुयायियों पर उनके नेता के लिए नारे लगाने पर भी नाराजगी जताई थी. वैसे, इसने पायलट समर्थकों को मुखर होने से नहीं रोका है और कुछ ने तो यह कहते हुए मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पर भी सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस में विभाजन साफ दिख रहा है. पायलट के वफादारों को पार्टी में इसलिए नाराज बताया जा रहा है कि अपना विद्रोह खत्म करने के बावजूद उन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया.

विधायकों के निधन के कारण इन सीटों पर हो रहे उपचुनावों में अधिकांश सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस-भाजपा दोनों ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही मैदान में उतारा है. राजसमंद से भाजपा की किरण माहेश्वरी विधायक थीं. भगवा पार्टी ने वहां से उनकी बेटी दीप्ति को खड़ा किया है. उनका मुकाबला एक समृद्ध संगमरमर व्यवसायी और कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा से होगा. सुजानगढ़ में कांग्रेस ने दिवंगत भंवर लाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा है. उनका सामना भाजपा के पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल से होगा. सहाड़ा में कांग्रेस ने पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को मैदान में उतारा है. उनका मुकाबला भाजपा के पूर्व मंत्री रतन लाल जाट से होगा.

भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कंधों पर डाल दी है. अपने परिवार में चिकित्सा आपातकाल का हवाला देकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस अभियान से दूरी बना रखी है. कांग्रेस का कहना है कि यह स्पष्ट संकेत है कि वे चुनाव से दूर रहना चाहती हैं. राजे की अनुपस्थिति की भरपाई के लिए भाजपा ने उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा, जिनके भाजपा में जाने के कारण बीते साल मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई थी. अगर भाजपा को बेहतर नतीजे मिलते हैं तो पूनिया के कद और राज्य इकाई में राजे-विरोधी गुट को मजबूती मिलेगी. अगर प्रदर्शन खराब होता है तो इससे संभवत: पूनिया की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को मौका मिलेगा जिसे राजे खेमे का समर्थन हासिल हो.

हो सकता है कि इन चुनावों से राज्य सरकार की सेहत पर कोई प्रभाव न पड़े, लेकिन ये कांग्रेस और भाजपा, दोनों में कई नेताओं के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं. ■

हार्दिक छाबड़ा

आमने-सामने
पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत (दाएं) के खिलाफ बिगुल फूंका था

सुबीर हल्दर

बंगाल की जंग

किस पथ वामपंथ

ममता की तृणमूल और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होने के बावजूद वामपंथी दलों और कांग्रेस के तीसरे मोर्चे को सत्ता हासिल करने के खेल में निर्णायक माना जा रहा

सुजीत ठाकुर

फरवरी महीने की 28 तारीख को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में संयुक्त मोर्चा की सभा में भारी भीड़ की मौजूदगी की जबरदस्त चर्चा हुई. 8 फेज वाले चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में 2019 के बाद पहली बार लेफ्ट-कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट (आइएसएफ) गठबंधन मुकाबले को त्रिकोणीय बनाता दिखने लगा. लेकिन दिन बीतने के साथ ही संयुक्त मोर्चा चर्चा से बाहर होता गया. अब मुकाबले में तृणमूल कांग्रस और भाजपा ही आमने-सामने दिखने लगी हैं. अब ममता के सामने कुर्सी बचाने और भाजपा के सामने तृणमूल का किला ढहाने की चुनौती बचती दिख रही है.. इस खेल में संयुक्त मोर्चा न तो भाजपा की धार कुंद करता दिख रहा है न ही भाजपा से मुकाबले में तृणमूल से ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है.

पर ऐसा नहीं कि मोर्चा रिंग से बाहर है. उसमें अभी इतनी सियासी ताकत है कि वह सायास-अनायास चुनाव के बीच और चुनाव के बाद सियासत का गुणा-भाग वैसे ही बदल सकता है, जैसा कि बीते लोकसभा चुनाव में बदला था. तब उसके वोटर रणनीतिक रूप से भाजपा के पाले में गए और भगवा ब्रिगेड ने 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीत लीं. वही जीत 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए ऐसी लॉचिंग पैड बनी, जिसने ममता के सामने संयुक्त मोर्चा के मुख्य विपक्षी दल बनने की संभावना को ही समाप्त कर दिया.

तो फिर संयुक्त मोर्चा मुकाबले से बाहर होकर कहां है? माकपा नेता वृंदा करात कहती हैं, ''हम जमीन पर हैं, मीडिया में नहीं. हम लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं और एक तीसरे विकल्प के रूप में वोटरों के सामने हैं. भाजपा और तृणमूल सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद की बात कर रही हैं और हम आम लोगों से जुड़े मुद्दों की.'' करात के दावे में दम हो या नहीं पर सियासी रूप से यह अजीब लगता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में मुख्य विपक्ष की भूमिका में आज के संदर्भ में संयुक्त मोर्चा ही है. इसके दो घटक दलों कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर विधायकों की संख्या 71 है. इसमें कांग्रेस के 44, माकपा के 26 और सीपीआइ का 1 विधायक है. भाजपा के तो 3 ही विधायक हैं.

आंकड़ों की इस सचाई के बावजूद मुकाबला तृणमूल बनाम संयुक्त

तीसरा पत्ता
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर तीसरे मोर्चे के नेताओं की सभा

मोर्चा का न होकर तृणमूल बनाम भाजपा क्यों है? वाम मोर्चे के चेयरमैन विमान बोस जवाब हैं, ''मीडिया की वजह से. लोकसभा चुनाव में यह मुकाबला ममता-बनाम मोदी का जरूर रहा होगा लेकिन विधानसभा चुनाव में तो मुकाबला राज्य की सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल के बीच होता है.'' पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मामलों के जानकार शंखदीप दास कहते हैं, ''कांग्रेस और लेफ्ट की निष्क्रियता ने मुकाबले को ममता बनाम मोदी बनने दिया. 2019 के लोकसभा चुनाव में जो माहौल बना था, उसे भाजपा विधानसभा चुनाव तक खींचने में सफल रही. पिछले पांच साल में राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने ममता के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया. यह काम भाजपा करती रही और आज मुख्य मुकाबले में वही है.'' राजनीतिक विश्लेषक मणिकांत ठाकुर कहते हैं, ''जिन-जिन राज्यों में भाजपा विधानसभा में मामूली दखल रखती थी वहां की स्थानीय पार्टी (भले राष्ट्रीय पार्टी हों) लोकसभा चुनाव में हारने के बाद निष्क्रिय बनी रही और भाजपा जगह लेती गई.'' तर्क में दम है. 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भारी जीत के बावजूद भाजपा रुकी नहीं. वहां की मजबूत पार्टी बसपा, सपा, रालोद सिमटती चली गईं. लेकिन जहां स्थानीय दल सक्रिय रहे वहां अभी भी मुकाबला सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी दलों के बीच ही है, भाजपा या कांग्रेस जूनियर पार्टनर के रूप में ही हैं. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, झारखंड हो या बिहार, वहां अभी तक विधानसभा चुनावों में मुकाबला राज्य के सबसे बड़े विपक्षी दल और सत्ताधारी दलों के बीच ही होता आया है.

बहरहाल, पश्चिम बंगाल में यदि मुख्य विपक्षी मोर्चे ने खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया है तो वोटरों के सामने विकल्प नहीं है. बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी थी. भाजपा ने मिशन बंगाल शुरू भी कर दिया था, लेकिन 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस ने हाथ मिलाया और तृणमूल के विकल्प के रूप में मैदान में डटा. उस चुनाव में भले गठबंधन को जीत नहीं मिली लेकिन भाजपा महज 3 सीटों पर ही सिमट गई. इस बार भी लेफ्ट और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है और आइएसएफ को भी जोड़ा है. लेफ्ट इस बार 165, कांग्रेस 92 और आइएसएफ 37 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन 4 चरण के बाद भी यह मोर्चा तृणमूल के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर सका है.

तो क्या यह तीसरा विकल्प भाजपा की राह आसान करेगा या ममता के लिए वरदान साबित होगा? राजनीतिक टीकाकार जयंत घोषाल कहते हैं, ''तीसरा मोर्चा दोधारी तलवार है, यह दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है. और चूंकि भाजपा और तृणमूल ही मुख्य मुकाबले में हैं इसलिए जिसको ज्यादा नुकसान होगा, दूसरे को उतना ही फायदा.'' जयंत की इस बात को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो साफ होता है कि 30 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले बंगाल में लगभग 70 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान वोटर निर्णायक रहे हैं. अभी ज्यादातर मुसलमान ममता के साथ हैं. इन मुसलमानों में करीब 85 फीसदी बांग्लाभाषी हैं. 15 फीसदी ही ऊर्दूभाषी हैं जिन पर आइएसएफ के प्रमुख और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पकड़ है. वे मुसलमान वोट तीसरे मोर्चे की तरफ लाने में सफल रहे तो ममता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि भाजपा राज्य में हिंदू ध्रुवीकरण का पूरा माहौल बनाने में जुटी है. अगर अब्बास सिद्दीकी ऐसा नहीं कर पाते तो ममता को नुकसान का अंदेशा कम है.

तीसरा मोर्चा भाजपा की राह आसान करेगा या तृणमूल की? जानकारों की राय में वह दुधारी तलवार की तरह है.

तो क्या लेफ्ट के वोटर लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भाजपा की ओर नहीं जाएंगे? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि संयुक्त मोर्चा की तरफ से विशेषकर वामपंथी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पाई हैं कि उनका दुश्मन नंबर एक ममता है या भाजपा. प्रदेश कांग्रेस के एक नेता कहते हैं, ''लोकसभा चुनाव में लेफ्ट का नंबर एक दुश्मन ममता थी, इसलिए लेफ्ट कैडर का वोट शेयर 2016 में 19.75 फीसदी से घटकर 2019 में 6.34 रह गया. इसी तरह कांग्रेस का वोट शेयर 2016 में जो 12.25 फीसदी था वह 2019 में 5.67 रह गया. यानी कांग्रेस और लेफ्ट का करीब 20 फीसदी वोट भाजपा की ओर गया और वोट शेयर जो 2016 में 10.16 फीसदी था, 2019 में बढ़कर 40.64 हो गया. इस लिहाज से देखें तो लेफ्ट या कांग्रेस के पास अब ऐसा कोई कैडर वोटर नहीं जो विधानसभा में भी भाजपा की तरफ चला जाए.''

इसमें एक दिलचस्प बात है कि तृणमूल का जो वोट शेयर 2016 में 44.91 फीसदी था, 2019 में 43.69 फीसदी पर बचा रहा. ऐसे में तृणमूल को उजला पक्ष दिख रहा है कि इस चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, जबकि लोकसभा में दोनों ही अलग-अलग थे. अब चूंकि विधानसभा में ये साथ हैं इसलिए गठबंधन को लोकसभा के मुकाबले ज्यादा वोट शेयर मिलने की उम्मीद है. तृणमूल के एक नेता कहते हैं, ''लोकसभा और विधानसभा में मतदान का ट्रेंड अलग होता है. राज्य में स्थानीय मुद्दे काम करते हैं. इसलिए राज्य सरकार के खिलाफ सत्ताविरोधी रुझान वाले वोट भाजपा और संयुक्त मोर्चे के बीच बंट जाएंगे, जिसका लाभ तृणमूल को होगा. दूसरी बात, भाजपा और तृणमूल में मुकाबला बराबरी का होने और नतीजों में कुछ सीटों का अंतर होने पर चुनाव बाद समर्थन देने के मुद्दे पर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए पहला विकल्प तृणमूल होगी.'' यानी 2 मई को चुनाव नतीजों के दिन यह मोर्चा एक बार फिर चर्चा में आएगा: इसने किसको कितना नुकसान पहुंचाया और किसकी डूबती नैया पार कर दी. ■

मानव-पशु टकराव

शिवपुरी में सिरदर्द बने सूअर

राहुल नरोन्हा

अमानवीय समाधान
पुलिस की गाड़ी के ऊपर से शिवपुरी में आवारा पशुओं को गोली मारते नवाब शफात अली खान

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बहुत ही जल्द नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अफसर लंबे समय से शहर में सुलग रही सूअरों की समस्या से परेशान हैं और मुसीबत ये भी है आवारा सूअरों से उत्पन्न सुरक्षा अव्यवस्था से कैसे निबटा जाए क्योंकि इसके राजनीतिक पहलू भी हैं. दरअसल, पशु अधिकार आंदोलन से जुड़े एक कार्यकर्ता की तरफ से 19 मार्च को दायर एक याचिका पर मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने शिवपुरी नगर निगम यानी एसएमसी को फटकार लगाते हुए आदेश दिया था कि वह आवारा सूअरों को मारने के लिए शार्पशूटरों की सेवा लेने जैसे मौजूदा तरीके को छोड़े और कोई नया समाधान करे. इस आदेश से शिवपुरी में सूअर पालक 12,000 की आबादी वाले वाल्मीकि समुदाय में प्रसन्नता है.

वर्ष 2012 में शिवपुरी के रहने वाले डॉ. राजेंद्र गुप्ता ने शहर में आवारा सूअरों की विकट समस्या पर मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी. उन्होंने याचिका में कहा था कि सूअरों को स्थानीय स्तर पर पाला जा रहा है और कचरा हटाने के लिए उनका अनौपचारिक रूप से सफाई कार्यों में उपयोग किया जा रहा है. गुप्ता ने यह भी कहा था कि सूअरों की बढ़ती संख्या के चलते शिवपुरी के निवासियों को विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, इसलिए एसएमसी शहर से सूअरों को हटाने का निर्देश जारी करे. इसके कुछ समय बाद, 2014 को हाइ कोर्ट ने आदेश पारित कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सुअर पालन को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर नगरपालिका सीमा क्षेत्र से बाहर किया जाए. इसके बाद, एसएमसी ने सूअरों को मारने के लिए शार्पशूटर नवाब शफात अली खान के साथ एक समझौता किया. (शफात देशभर में ऐसे कई काम कर चुके हैं, जिसमें 2018 में महाराष्ट्र में बाघिन अवनी को मारने का विवादास्पद मामला भी शामिल है.) नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, उन्होंने शिवपुरी में 2014 से 2017 के बीच 4,559 सूअर मारे और उन्हें प्रति सूअर 240 रु. मेहनताना दिया गया. पिछले वर्ष 31 जुलाई को एसएमसी ने शूटर्स की भर्ती के लिए नया टेंडर जारी कर दिया. इस वर्ष 19 मार्च को पशु अधिकार कार्यकर्ता संगीता डोगरा ने इसे चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई के बाद ग्वालियर पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि सूअरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बंध्याकरण जैसे वैकल्पिक समाधान खोजे जाएं. डोगरा ने याचिका में यह भी सुझाया कि कचरा प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तरीकों जैसे कि बायो-मेथेनेशन, एरियल कंपोस्टिंग या इन्सिनरेशन का उपयोग किया जा सकता है.

> मध्यप्रदेश हाइ कोर्ट के एक फैसले के बाद शिवपुरी में आवारा सूअरों की आबादी पर अंकुश के लिए उन्हें मारने के एसएमसी के अभियान पर रोक लग सकी

शिवपुरी में वाल्मीकि समुदाय ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन डोगरा के सुझाव पर सहमत नहीं है क्योंकि जब बात कचरा प्रबंधन की आती है तो उन्हें अपनी आजीविका छिनने का डर सताने लगता है. सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कोडे कहते हैं, ''आधे शहर को साफ करने के लिए सूअरों का इस्तेमाल किया जाता है.'' विष्णु के अवतारों में एक वराह का जिक्र करते हुए वे बताते हैं, ''अगर सरकार हिंदुत्ववादी होने का दावा करती है, तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि सूअर भगवान का अवतार है.'' कोडे का यह भी कहना है कि अगर एसएमसी सूअर पालन को शहर की सीमा से बाहर ले जाने के प्रति इतना ही गंभीर था तो उसे वाल्मीकि समुदाय के लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी. वे कहते हैं, ''वाल्मीकि समुदाय को कुछ और व्यवसाय करना चाहिए, ये कहना ठीक है. लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी कायम है, हमारे समुदाय का कोई व्यक्ति अन्य व्यवसाय या रोजगार करता है तो कोई भी उनका सहयोग नहीं करता.'' ■

उत्तराखंड

उलटे फैसले

अखिलेश पांडेय

हरिद्वार के अखंड परम धाम आश्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में हाल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में शामिल 51 मंदिरों को बोर्ड से मुक्त किये जाने और बोर्ड पर पुनर्विचार करने की बात क्या कही, तीर्थ-पुरोहितों में खुशी की लहर दौड पड़ी. चारधाम तीर्थ क्षेत्र पंचायत ने तो इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया. रावत का कहना था कि देवस्थानम बोर्ड पर फिर से विचार करने को तीर्थ पुरोहित और हक-हुकूक धारियों को भी बुलाकर बात की जाएगी. उन्होंने कहा कि चारधामों पर शंकराचार्यों के समय से स्थापित व्यवस्थाओं-परंपराओं का पूरी तरह पालन किया जाएगा. किसी के भी अधिकार छिनने नहीं दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि चार धामों के कपाट फिर से प्राचीन प्रथा के अनुसार ही खोले जायेंगे. इस बयान को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले पलटने के एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है.

ऐसे में त्रिवेंद्र भी अपना पक्ष रखते नजर आए. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का देवस्थानम बोर्ड बनाने का उद्देश्य वहां आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था कायम करना भर था. खुद मंदिर समितियों ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर यहां भी बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था. यहां तक कि समितियां श्री पूर्णागिरि और श्री चितई के लिए भी ऐसी व्यवस्था चाहते रहे. पंडों और पुरोहितों के हक-हकूक से छेड़छाड़ करने की बात से इन्कार करते हुए उन्होंने कहा कि केवल यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंधन के वास्ते बोर्ड बनाया गया था. जाहिर है, त्रिवेंद्र की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री के बयान पर साफ असहमति थी.

त्रिवेंद्र सभी मुद्दों पर तुर्की-ब-तुर्की अपना पक्ष रखते हैं. मसलन, देवस्थानम बोर्ड पर उन्होंने स्पष्ट किया कि 45-48 मंदिर पहले से ही बद्री-केदार मंदिर समिति के अधीन थे. प्रस्ताव आने पर दो-तीन मंदिरों को और जोड़ा गया था; यह भी कि थोड़ा बहुत विरोध हर काम का होता है लेकिन कैबिनेट ने यह निर्णय व्यापक हित में और दूरदृष्टि के तहत लिया था; इन धामों के लिए हवाई सेवाएं बढ़ रही हैं. चारधाम ऑल वेदर रोड बनकर तैयार होने को है, जिससे तीर्थयात्रियों की आवक बढ़ना लाजिमी है; पिछली बार सामान्य हालात के दिनों में 36 लाख तीर्थयात्री आए थे; आने वाले समय में यह संख्या करोड़ों में जाएगी; हमे उसी हिसाब से तैयारी करने की जरूरत है.

तीरथ सिंह रावत पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र के धर्मक्षेत्र से जुड़े कई फैसले पलटकर अपने वोटबैंक को संदेश देना चाह रहे हैं

दरअसल त्रिवेंद्र सरकार के देवस्थानम बोर्ड बनाने के फैसले से तीर्थ पुरोहित और मंदिरों से जुड़े हक-हुकूकधारी लंबे समय से आंदोलनरत थे. चुनावी साल होने के कारण उनकी यह नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती थी. इसी वजह से इस फैसले पर पुनर्विचार हुआ है.

इस बारे में घोषणा के वक्त नए मुख्यमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की एक बैठक में उठी संतों की मांग को ध्यान में रखा. इससे तीरथ संदेश देना चाहते हैं कि वे उन्हीं निर्णयों को पलटेंग जिससे लोगों का एक बड़ा तबका नाराज है. तीरथ कई बार कह चुके हैं कि वे सरकार में लोगों के लिए हैं, लोगों ने ही उन्हें यहां बैठाया है इसलिए जनता जनार्दन है और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. विहिप और आरएसएस भी मंदिरों पर सरकारी अंकुश के खिलाफ बताए जा रहे थे पर बताते हैं त्रिवेंद्र ने इस बारे में फैसला लेते वक्त दोनों की नहीं सुनी.

इस तरह के निर्णयों से आलाकमान के सामने वे अपनी छवि एक कड़क प्रशासक की बनाना चाहते थे, लेकिन इस तरह के सख्त फैसलों ने ही उनके खिलाफ माहौल बनाया और अंतत: सत्ता से उनकी बेदखली का कारण बने. नए मुख्यमंत्री तीरथ अब पार्टी के खिलाफ इसी असंतोष को दूर कर कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच खुद को उनका पक्षकार और जनहितैषी साबित करने की कोशिश में यह सब कर रहे हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव तक वे लोगों के रोष को कम कर सकें. इसी क्रम में उन्होंने गैरसेण में कमिश्नरी बनाने की घोषणा को भी केबिनेट की बैठक करके स्थगित किया है. इस घोषणा से न केवल कुमाऊं और गढ़वाल के प्रभावित जिलों के आम लोग बैचैनी महसूस कार रहे थे बल्कि भाजपा के सांसद-विधायक भी भड़क गए थे.■

भक्ति भाव विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत

राज्य सरकार

मुद्रा मंत्र

दुबला होता रुपया

शुभम शंखधर

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

अभी इसी 13 अप्रैल को रुपया कमजोर होकर 75 के पार चला गया यानी एक डॉलर की कीमत 75 रुपए से ज्यादा हो गई. मुद्रा बाजार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के बीच यह राय आम बनती दिख रही है कि रुपए की यह कमजोरी और गहरा सकती है. इसके कई कारण उभरकर सामने आ रहे हैं. मसलन, वित्तीय बाजार में मुद्रा का अतिरिक्त प्रवाह (एक्सेस लिक्विडिटी), ब्याज दरों का निचले स्तर पर रहना, कोरोना की दूसरी लहर के कारण देशभर में लॉकडाउन लगने की स्थिति उत्पन्न होना वगैरह-वगैरह.

केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं, ''सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी भले ही बॉन्ड की यील्ड को नीचे रखने में मददगार हो सकती है, लेकिन रुपए के लिए यह अच्छी खबर नहीं है.'' भारतीय रिजर्व बैंक जीएसएपी (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम) के रास्ते बाजार में अतिरिक्त नकदी का प्रवाह करेगा. रिवर्स रेपो बास्केट में पहले से ही सात लाख करोड़ की तरलता मौजूद है. यह तरलता बॉन्ड की यील्ड को नीचे रखने में निश्चित तौर पर मददगार होगी लेकिन बाजार में रुपए की ज्यादा आपूर्ति रुपए को कमजोर करेगी.

दरअसल यही रिजर्व बैंक की दुविधा है. जहां एक ओर बॉन्ड की यील्ड को नीचे रखकर सरकार को सस्ता कर्ज मुहैया कराना है और दूसरी ओर कमजोर रुपया महंगाई को ईंधन न दे, इसकी भी फिक्र करनी है. सरकार का इस साल खर्च चलाने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने का अनुमान है. सिस्टम में अतिरिक्त तरलता के चलते ब्याज दरें निचले स्तर पर रहेंगी, जबकि अमेरिका में 10 साल अवधि के बॉन्ड की यील्ड मजबूत होकर 1.66 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है. यह समीकरण विदेशी निवेशकों के लिए भारत को कम आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं. यही वजह है कि विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्ड बाजार में बिकवाली कर रहे हैं.

केडिया कमोडिटीज के प्रबंध निदेशक अजय केडिया कहते हैं, ''देश में बढ़ता व्यापार घाटा भी रुपए में कमजोरी की वजह बनेगा.'' इसकी दो वजहें हैं. पहली, अर्थव्यवस्था में वापसी के साथ देश के आयात बढ़ेंगे और दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में कमोडिटी की बढ़ती कीमतें आयात के बिल में इजाफा करेंगी. निर्यात को बढ़ाकर घाटे को काबू किया जा सकता है. लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस अनुमान नहीं है. गौरतलब है कि फरवरी 2021 में देश का व्यापार घाटा 12.62 अरब डॉलर हो गया है, जो फरवरी 2020 में 10.16 अरब डॉलर पर था.

केयर रेटिंग्स की 12 अप्रैल को जारी रिपोर्ट कहती है कि तेजी से बढ़ती कोरोना की दूसरी लहर को थामने के लिए दोबारा लॉकडाउन लगाने की तैयारी, वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच अर्थव्यवस्था में उतनी तेज वापसी की उम्मीद नहीं दिख रही जितनी पहले अपेक्षित थी. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से लगाए गए अनुमान कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 12.5 फीसदी रहेगी, इस पर गहरे संशय हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वित्त वर्ष का पहला महीना ही कमजोर आर्थिक गतिविधियों वाला रहा है. अर्थव्यवस्था में कमजोर वापसी रुपए की कमजोरी का एक बड़ा और अहम कारण बन सकता है.

इंडेक्स जीनियस इंवेस्टमेंट एडवायजर्स के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट अमित हारचेकर चार्ट पर रुपए की एक डराने वाली संरचना उभरती देख रहे हैं. उनके मुताबिक रुपए के लिए 73.85 का स्तर एक अहम बाधा (रजिस्टेंस) थी. इसे पार करके के बाद रुपया अगर इसके ऊपर टिकता है तो प्रति डॉलर 80.40 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं. यह लक्ष्य अगले तीन से छह महीनों के बीच पूरा होने की संभावना है.

घरेलू स्तर पर रुपए की कमजोरी के विभिन्न कारणों के जानने के बाद डॉलर की मजबूती को भी ध्यान में रखना जरूरी है. अमेरिका में वैक्सीन का तेज वितरण और अर्थव्यवस्था में वापसी की बेहतर उम्मीदें डॉलर में दम भर रही हैं, जो निश्चित तौर पर दुनिया की अन्य मुद्राओं के लिए अच्छी खबर नहीं है. यानी हम अपनी कमजोरी से तो कमजोर हो ही रहे हैं डॉलर की ताकत भी हमें दुबला कर सकती है. ■

रुपयाः एक साल का सफर

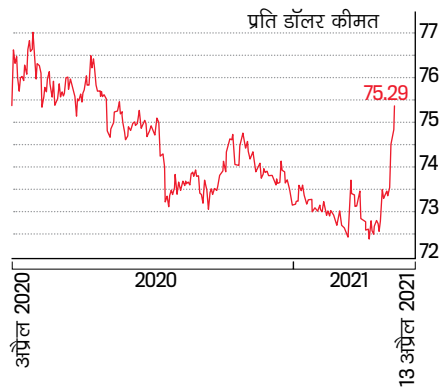

अर्थात्

घुटती सांसों का 'उत्सव'

अंशुमान तिवारी

भारत के लिए चुनाव, कुंभ और महामारी में क्या अंतर या समानता है? बात इन आयोजनों के सुपर स्प्रेडर बनने के खतरे की नहीं है. हमें तो इस बात पर अचरज होना चाहिए कि जो मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा चुनाव करा लेता है, भरपूर कोविड के बीच कुंभ जैसे मेले और आइपीएल जैसे भव्य महंगे तमाशे जुटा लेता है वह महामारी की नसीहतों के बावजूद अपने थोड़े से लोगों को अस्पताल, दवाएं और ऑक्सीजन नहीं दे पाता.

डारोन एसीमोग्लू और जेम्स जे राबिंसन ने दुनिया के इतिहास, राजनीति और सरकारों के फैसले खंगालकर अपनी मशहूर किताब *व्हाइ नेशंस फेल* में बताया है कि दुनिया के कुछ देशों में लोग हमेशा इसलिए गरीब और बदहाल रहते हैं क्योंकि वहां की राजनैतिक और आर्थिक संस्थाएं बुनियादी तौर पर शोषक हैं, इन्हें लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के मूल्यों पर बनाया ही नहीं जाता, इसलिए संकटों में व्यवस्थाएं ही सबसे बड़ी शोषक बन जाती हैं.

कोविड की दूसरी लहर ने हमें बताया कि एसीमोग्लू और राबिंसन क्यों सही हैं? क्या हमारे पास क्षमताएं नहीं थीं? क्या संसाधनों का टोटा था? नहीं. शायद हमारा दुर्भाग्य हमारी संवेदनहीन सियासत और उसकी संस्थाएं लिख रही हैं.

कोविड की पहली लहर के वक्त स्वास्थ्य क्षमताओं की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी. अप्रैल 2020 में 15,000 करोड़ रु. का पैकेज आया. दावे हुए कि बहुत तेजी से विराट हेल्थ ढांचा बना लिया गया है तो फिर कहां गया वह सब?

बहुत-से सवाल हमें मथ रहे हैं जैसे कि

● अप्रैल से अक्तूबर तक ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की संख्या 58,000 से बढ़ाकर 2.65 लाख करने और आइसीयू और वेंटीलेटर बेड की संख्या तीन गुना करने का दावा हुआ था. कहा गया था कि ऑक्सीजन, बडे अस्थायी अस्पताल, पर्याप्त जांच क्षमताएं, क्वारंटीन सेंटर और कोविड सहायता केंद्र हमेशा तैयार हैं. लेकिन एक बार फिर अप्रैल में जांच में वही लंबा समय, बेड, ऑक्सीजन, दवा की कमी पहले से ज्यादा और ज्यादा बदहवास और भयावह!!

● कोविड के बाद बाजार में नौ नई वेंटीलेटर कंपनियां आईं. उत्पादन क्षमता 4 लाख वेंटीलेटर तक बढ़ी लेकिन पता चला कि मांग तैयारी सब खो गई है. उद्योग बीमार हो गया.

● भारत में स्वास्थ्य क्षमताएं बनी भी थीं या सब कुछ कागजी था अथवा कुंभ के मेले की तरह तंबू उखड़ गए? सनद रहे कि दुनिया के सभी देशों ने कोविड के बाद स्वास्थ्य ढांचे को स्थानीय बना दिया क्योंकि खतरा गया नहीं है.

● स्वास्थ्यकर्मियों की कमी (1,400 लोगों पर एक डॉक्टर, 1,000 लोगों पर 1.7 नर्स) सबसे बड़ी चुनौती थी, यह जहां की तहां रही और एक साल बाद पूरा तंत्र थक कर बैठ गया.

क्षमताओं का दूसरा पहलू और ज्यादा व्याकुल करने वाला है.

● बीते अगस्त तक डॉ. रेड्डीज, साइजीन और जायडस कैडिला के बाजार में आने के बाद (कुल सात उत्पादक) प्रमुख दवा रेमिडिसविर की कमी खत्म हो चुकी थी. अप्रैले में फैवीफ्लू की कालाबाजारी होने लगी. इंजेक्शन न मिलने से लोग मरने लगे.

● दुनिया की वैक्सीन फार्मेसी में किल्लत हो गई क्योंकि अन्य देशों की सरकारों ने जरूरतों का आकलन कर दवा, वैक्सीन की क्षमताएं देश के लिए सुरक्षित कर लीं. कंपनियों से अनुबंध कर लिए. और हमने वैक्सीन राष्ट्रवाद का प्रचार किया?

इतना तो अब सब जानते हैं कि कोविड को रोकने के लिए एजेंसियों के बीच संवाद, संक्रमितों की जांच और उनके जरिए प्रसार (कांटैक्ट ट्रेसिंग) को परखने का मजबूत और निरंतर चलने वाला तंत्र चाहिए लेकिन बकौल प्रधानमंत्री सरकारें जांच घटाकर और जीत दिखाने की होड़ में लापरवाह हो गईं. यह आपराधिक है कि करीब 1.7 लाख मौतों के बावजूद संक्रमण जांच, कांटैक्ट ट्रेसिंग और सूचनाओं के आदान-प्रदान का कोई राष्ट्रव्यापी ढांचा या तंत्र नहीं बन सका.

दवा, ऑक्सीजन, बेड के लिए तड़पते लोग, गर्वीले शहरों में शवदाह गृहों पर कतारें...विश्व गुरु, महाशक्ति, डिजिटल सुपरपावर या दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का यह चेहरा खौफनाक है. यदि हम ऐसे निर्मम उत्सवप्रिय देश में बदल रहे हैं जहां सरकारें एक के बाद एक भव्य महाकुंभ, महाचुनाव और आइपीएल करा लेती हैं लेकिन महामारी के बीच भी अपने लोगों को अस्पताल, दवाएं, आक्सीजन यहां तक कि शांति से अंतिम यात्रा के लिए श्मशान भी नहीं दिला पातीं तो हमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है.

भारत में किसी भी वक्त अधिकतम दो फीसदी (बीमार, स्वस्थ) से ज्यादा आबादी संक्रमण की चपेट में नहीं थी लेकिन एक साल गुजारने और भारी खर्च के बाद 28 राज्यों और विशाल केंद्र सरकार की अगुआई में कुछ नहीं बदला. भरपूर टैक्स चुकाने और हर नियम पालन के बावजूद यदि हम यह मानने पर मजबूर किए जा रहे हैं कि खोट हमारी किस्मत में नहीं, हम ही गए गुजरे हैं (*जूलियस सीजर*-शेक्सपियर) तो अब हमें अपने सवाल, निष्कर्ष और आकलन बदलने होंगे क्योंकि अब व्यवस्था ही जानलेवा बन गई है. @anshuman1tiwari

दवा, ऑक्सीजन, बेड के लिए तड़पते लोगों को देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का यह बदनुमा चेहरा हमें बुरी तरह परेशान कर रहा है

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

टीका संकट

कोविड की घातक दूसरी लहर ने लगता है भारत की उत्साही वैक्सीन रणनीति की पोल खोलकर रख दी है. आखिर कमी कहां रह गई और इसे वापस पटरी पर कैसे लाया जाए

सोनाली आचार्जी,
साथ में पी.बी. जयकुमार

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर देश में एक भीषण ज्वार की तरह उभरी है. दो हफ्तों के भीतर प्रतिदिन के संक्रमण के मामले एक लाख के आंकड़े को पार कर गए जो पहली लहर की तुलना में लगभग पांच गुना तेज गति है. एक अन्य डरावनी चीज प्रमुख महानगरों के अस्पतालों में दिख रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 50 अस्पतालों में आइसीयू और वेंटिलेटर बेड पिछले सप्ताह ही भर गए थे. नए मामलों में 40 फीसदी से ज्यादा का योगदान करने वाले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लोगों के घूमने-फिरने और आर्थिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए 'जनता लॉकडाउन' लगाना पड़ा. इस बीच नौ अन्य प्रमुख राज्यों में संक्रमण में खतरनाक वृद्धि दिखी है और देश भर में मिनी लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है. इससे नाजुक स्थिति से गुजरने के बाद हाल के महीनों में कुछ सुधार की ओर बढ़ी देश की आर्थिक गतिविधियों पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की सह-संयोजक मालिनी ऐसोला कहती हैं, ''यह लहर शहरों में दौड़ रही है. अफरातफरी मची है और दहशत का माहौल है.'' इस हालत के लिए पूरी तरह भारत ही जिम्मेदार है. 2020 के अंत तक संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट के कारण, केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी निगरानी कम कर दी और

फोटो इलस्ट्रेशन: बंदीप सिंह
मूल फोटो : चंद्रदीप कुमार

जनता भी लापरवाह हो गई. हरिद्वार में कुंभ जैसे बड़े स्तर के सार्वजनिक समारोहों और चुनावी राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियों को अनुमति देने के अलावा, पहली लहर के सुस्त पड़ने के संकेत मिलने के बाद प्रतिबंधों में दी गई ढील के बाद कोविड-सतर्क व्यवहार को लेकर लोगों में बहुत लापरवाही दिखने लगी. महामारी को लेकर लोगों की लापरवाही का आलम यह था कि मास्क उतार फेंकने समेत सारी सावधानियों को हवा में इस तरह उड़ा दिया मानों महामारी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो. यह सब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की दूसरी और यहां तक कि तीसरी लहरों के प्रत्यक्ष प्रमाणों, जो पहले की तुलना में अधिक घातक थे, के बावजूद हो रहा था. लगता है कि मौजूदा उछाल के दौरान भारत में वायरस मजबूत और ज्यादा घातक स्ट्रेन में बदल गया है. उदाहरण के लिए, पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआइवी) की ओर से जनवरी से मार्च तक महाराष्ट्र से लिए गए 361 नमूनों में से 61 प्रतिशत में डबल म्यूटेंट (B.1.617) स्ट्रेन पाया गया. दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया बताते हैं, ''ये नए स्ट्रेन पिछले साल के मुकाबले कहीं संक्रामक हैं.''

संक्रमण के विस्फोट के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने अल्पकालिक उपाय शुरू किए, जिसमें मरीजों के उपचार के अलावा वायरस के लिए ट्रैकिंग और परीक्षण शामिल हैं. लेकिन दूसरी लहर ने इस बात की पोल खोल दी कि टीके के विकास और उत्पादन में अच्छी शुरुआत के बावजूद अपनी टीकाकरण रणनीति को लेकर देश ने भारी अदूरदर्शिता का परिचय दिया है. कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण एक व्यक्ति को संक्रमित होने से रोक सकता हो या नहीं, लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि यह वायरस के हमले की तीव्रता को कम कर देता है जिससे अस्पतालों में भर्ती होने की नौबत और मृत्यु की आशंका कम हो सकती है. टीके संक्रमण की लहरों को धीमा करने के लिए आबादी के बीच हर्ड इम्यूनिटी (सामूहिक रोग प्रतिरोधक शक्ति) बनाने में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये लहरें लौट सकती हैं.

केंद्र सरकार का दावा है कि 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन तथ्य यह भी है हमारी आबादी के 7.9 प्रतिशत से कम का टीकाकरण किया गया है जबकि अमेरिका में यह औसत 57 प्रतिशत और ब्रिटेन में 60 प्रतिशत है. इससे भी बुरी बात यह है कि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने टीकों की कमी की शिकायत की, केंद्र ने भी आंकड़े दिए कि स्टॉक में 3 करोड़ से अधिक खुराक थी और राज्यों को ही उनकी खराब योजना और वितरण के लिए दोषी ठहराया.

एक दूसरे पर दोषारोपण को अगर परे कर दें तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक टीका आपातकाल का सामना कर रहा है. देश को हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 75 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करना होगा. टीकाकरण की वर्तमान दर को देखते हुए यह लक्ष्य 2022 की गर्मियों तक ही पूरा हो पाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि आदर्श स्थिति के लिए अगले तीन महीनों में ऐसा कर दिखाना होगा. इसका मतलब है कि भारत को प्रतिदिन 40 लाख लोगों के टीकाकरण की मौजूदा क्षमता को बढ़ाकर 2 करोड़ प्रतिदिन करना होगा, यानी पांच गुणा वृद्धि की जरूरत है. अगर हम ऐसा करने में विफल रहते हैं तो निश्चित रूप से मौजूदा लहर के बाद एक तीसरी लहर आएगी.

कुछ महीने पहले की आरामदेह स्थिति से हम इस भयावह स्थिति तक

फ्रांसिस मैस्करेन्हास/रॉयटर

मुंबई की मुश्किल मुंबई के बीकेसी (बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स) स्थित टीकाकरण केंद्र के बाहर जुटी भीड़ (बाएं); और शहर के माहिम इलाके में एक केंद्र के बाहर लगा टीका खत्म होने का निराशाजनक नोटिस

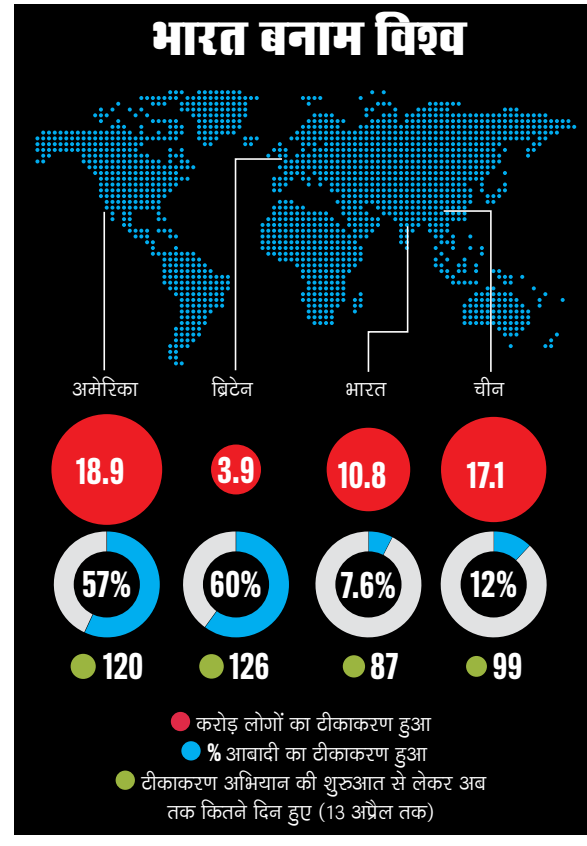

स्रोत: Ourworldindata.org

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

सतीश बाटे / गेटी इमेजेज

भारत : टीका लगाने में अपेक्षित तेजी नहीं दिखी

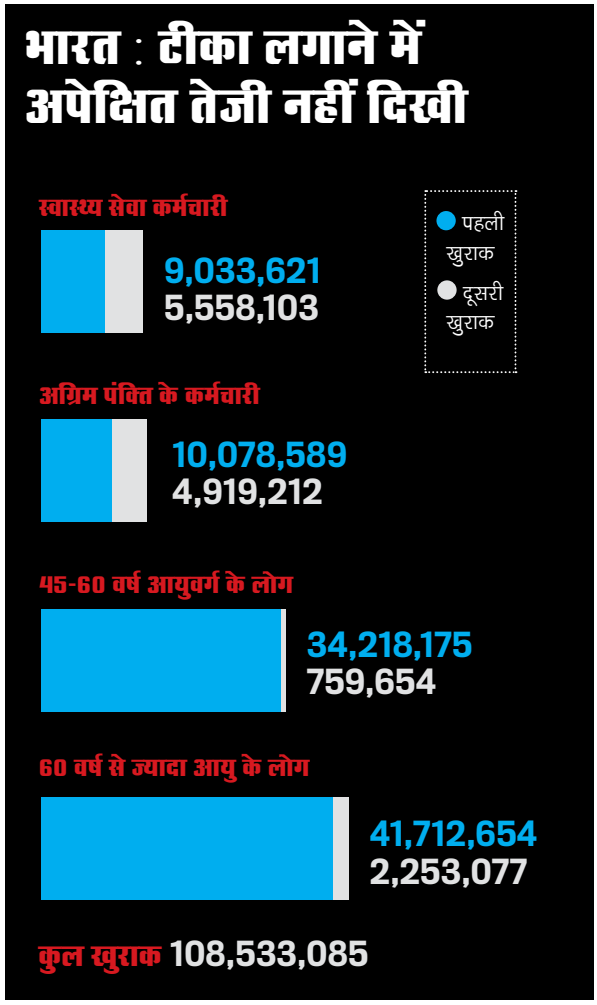

स्रोत: परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय

चूंकि कोवैक्सीन को सार्वजनिक क्षेत्र की लैब के साथ साझेदारी में विकसित किया गया इसलिए सरकार सप्लाइ बढ़ाने के लिए इसके उत्पादन का लाइसेंस दूसरी निजी फर्मों को दे सकती थी

कैसे पहुंच गए? टीकाकरण की गति बढ़ाने और वायरस का प्रसार रोकने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है?

हम कहां चूके?

एक ऐसे देश के लिए, जिसके पास विश्वस्तर पर टीके बनाने की सबसे बड़ी क्षमता के अलावा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम को चलाने का अनुभव है, उसे कोविड टीके के उत्पादन और इसे लोगों को लगाने के बड़े कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रबंधन के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की जरूरत थी. हमारे पास एक अतिरिक्त फायदा भी था. पिछले साल के अंत तक जब दुनिया भर में लगभग एक दर्जन टीकों के लिए अंतिम चरण का नैदानिक परीक्षण अभी चल ही रहा था, भारत के पास पहले से ही कोविड के दो टीके—कोविशील्ड और कोवैक्सीन—निर्माण की प्रक्रिया में पहुंच चुके थे. भारत सरकार को इस का श्रेय जाता है कि एनआइवी ने एक निजी फार्मा दिग्गज भारत बायोटेक के सहयोग से कोवैक्सीन को विकसित किया. दूसरी ओर कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी ने फार्मा की दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया था और उन्होंने भारत सहित दुनियाभर के देशों में आपूर्ति के लिए विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट

राज्यों का हाल

सप्लाई की कमी के कारण कोविड संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या वाले शीर्ष 10 राज्य अपना टीकाकरण का लक्ष्य पाने में नाकाम रहे

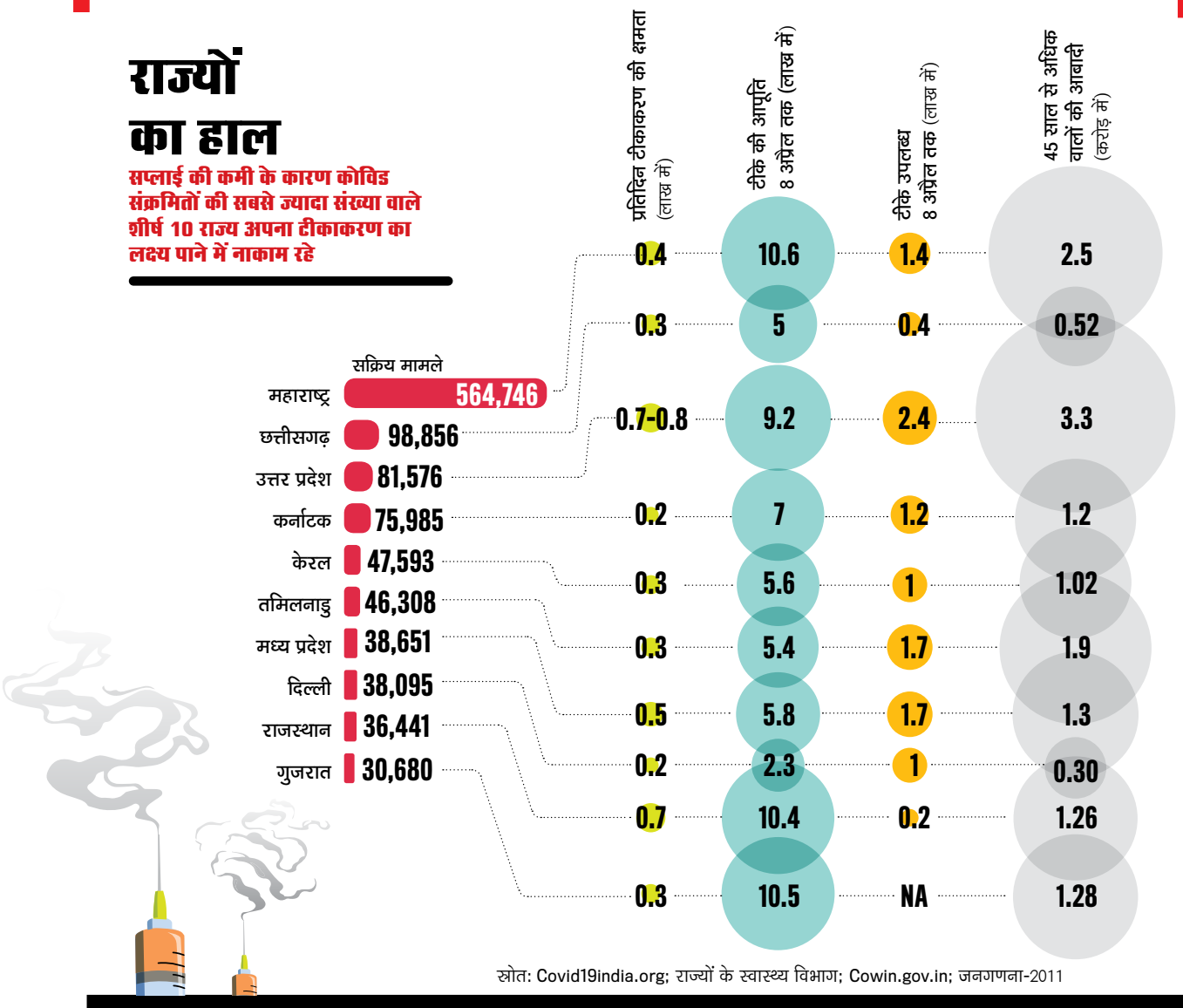

स्रोत: Covid19india.org; राज्यों के स्वास्थ्य विभाग; Cowin.gov.in; जनगणना-2011

ऑफ इंडिया (एसआइआइ) के साथ शुरुआत में एक अरब खुराक के निर्माण के लिए करार किया.

यहीं पर भारतीय स्वास्थ्य रणनीतिकार गच्चा खा गए. 50 संगठनों के गठबंधन पीपुल्स वैक्सीन एलायंस के अनुसार, दुनिया की आबादी के सिर्फ 14 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमीर देशों ने कोविशील्ड सहित सभी सबसे अच्छे टीकों की आधे से अधिक (53 प्रतिशत) खुराक खरीद ली. फाइजर के बायोएनटेक के साथ साझेदारी करने के बाद ट्रंप प्रशासन ने 10 करोड़ खुराकों के लिए लगभग 2 अरब डॉलर का भुगतान किया और उन्हें एक विकल्प यह भी दिया यदि यह टीका सफल रहा तो 50 करोड़ और खुराक देनी होगी. आज, अमेरिका के पास अपनी पूरी आबादी के दो बार टीकाकरण लायक पर्याप्त खुराक है. इजराइल ने अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त खुराक मुहैया कराने के एवज में अपने नागरिकों के मेडिकल रिकॉर्ड तक फाइजर को पहुंच देने की पेशकश करने जैसा कदम उठाया. इजरायल अपनी 75 प्रतिशत आबादी को टीका देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के काफी करीब पहुंच चुका है.

दूसरी ओर, भारत सरकार ने शुरुआती चरण में दोनों वैक्सीन निर्माताओं, एसआइआइ और भारत बायोटेक को केवल 11 करोड़ टीकों का एक सीमित ऑर्डर दिया. नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 के लिए टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) के सह-अध्यक्ष डॉ. वी.के. पॉल, कहते हैं, ''हमारी प्राथमिकता अति संवेदनशील समूहों के टीकाकरण की थी. स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 65 साल से ऊपर के लोगों और पूर्व में रोगों से ग्रस्त 30 करोड़ लोगों के जुलाई तक टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इस समूह को कोविड-19 से सबसे अधिक खतरा है इसलिए उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण था. निजी बिक्री की इजाजत इसलिए नहीं दी गई ताकि प्राथमिकता वाले समूहों के लिए पर्याप्त टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.'' सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आश्वस्त थी इसलिए उसने मिशन मैत्री के हिस्से के रूप में दुनिया भर के जरूरतमंद देशों को 6.5 करोड़ खुराक का निर्यात किया. इस बीच, भ्रामक चर्चा से वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचकिचाहट पैदा हो गई और शुरुआती छह हफ्तों में लक्ष्य समूह के

धीमी गति

कोविड के लिहाज से अति संवेदनशील जिले अपनी आबादी के 75 प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य से बहुत पीछे हैं. इनकी तुलना में जहां केस कम हैं वे लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं

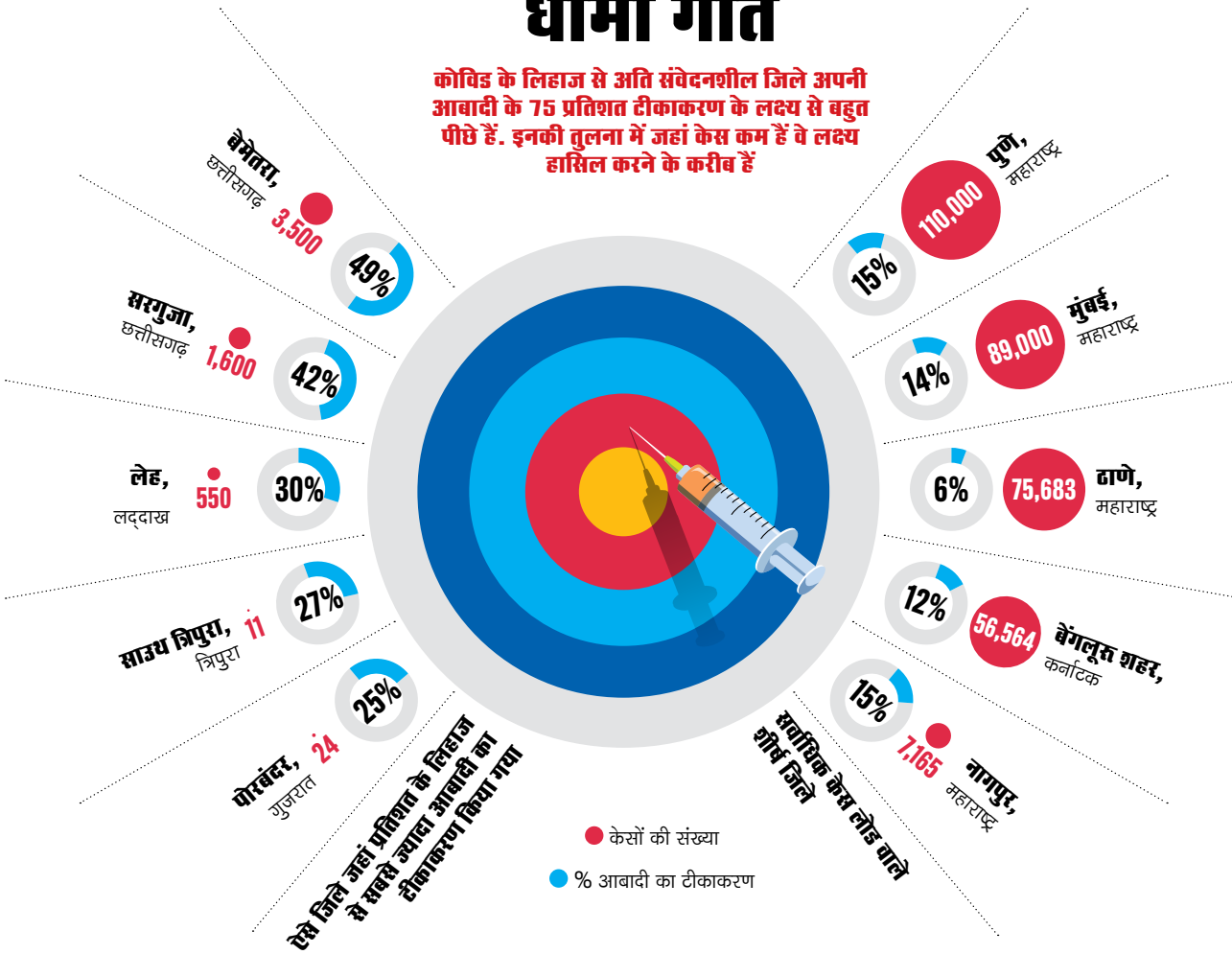
बैमेतरा, छत्तीसगढ़ 3,500 49%
सरगुजा, छत्तीसगढ़ 1,600 42%
लेह, लद्दाख 550 30%
साउथ त्रिपुरा, त्रिपुरा 11 27%
पोरबंदर, गुजरात 24 25%
ऐसे जिले जहां प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा आबादी का टीकाकरण किया गया
सर्वाधिक केस लोड वाले शीर्ष जिले
15% 7,165 नागपुर, महाराष्ट्र
12% 56,564 बेंगलूरु शहर, कर्नाटक
6% 75,683 ठाणे, महाराष्ट्र
14% 89,000 मुंबई, महाराष्ट्र
15% 110,000 पुणे, महाराष्ट्र
केसों की संख्या
% आबादी का टीकाकरण

स्रोत: Covid19india.org; Cowin.gov.in; जनगणना-2011

भारत ने भी टीका विकसित करने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा पर 12 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं जो कि अमेरिका के ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत 18 अरब डॉलर खर्च के सामने तुच्छ रकम है

केवल 40 प्रतिशत ने ही अपने टीके लगवाए और टीके की शीशियों के बेकार होने की खबरें भी आईं. कुछ विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि सरकार का लक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण, जिसे कुछ लोग भारत के मौजूदा संकट का कारण मानते हैं, अभियान की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा तरीका था. मेडिसिन सैंन्ज फ्रंटियर्स की भारत की डायरेक्टर लीना मेंघाने कहती हैं, ''जहां तक मांग-आपूर्ति का प्रश्न है, भारत में सफल होने के लिए किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को लक्ष्य-आधारित रखा जाना जरूरी था. आप एक बार में इतने बड़े देश का टीकाकरण नहीं कर सकते.'' लेकिन वे यह भी कहती हैं, ''भारत ने उतना निवेश नहीं किया जितना कि उसे अनुसंधान में या विनिर्माण में या देश के भीतर लक्षित लक्ष्यों के लिए टीका सुनिश्चित कराने के लिए करना चाहिए.'' योजनाकार इस बात का भी अनुमान नहीं लगा सके कि कोरोना की दूसरी लहर भी जल्द ही आने वाली है जो युवाओं के बड़े वर्ग को निशाना बनाएगी इसलिए टीकाकरण की रणनीति में तेजी से बदलाव करते हुए सभी आयु समूहों को शामिल करने की आवश्यकता होगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पूर्व नौकरशाह, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, के अनुसार सबसे बड़ी चूक कोवैक्सीन के लिए विनिर्माण प्रबंधों में हुई और सरकार इसके उत्पादन के स्तर को बढ़ाने में विफल रही. भारत बायोटेक की हैदराबाद में तीन

और बेंगलूरू में एक विनिर्माण सुविधा है. राज्यसभा की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी एक महीने में 1.25 करोड़ तक खुराक का उत्पादन कर सकती है. हालांकि वर्तमान में यह एक महीने में 40-50 लाख खुराक का उत्पादन कर रही है और पिछले नवंबर से इसने लगभग 2.5 करोड़ खुराक का उत्पादन किया. चूंकि इसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की साझेदारी में विकसित किया गया इसलिए केंद्र सरकार अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन के निर्माण का लाइसेंस दे सकती थी और उत्पादन बढ़ाया जा सकता था.

कोवैक्सीन की सीमित आपूर्ति का मतलब है कि एसआइआइ पर उत्पादन दबाव बढ़ेगा जो एस्ट्राजेनेका के साथ अपने समझौते में दुनिया के लिए अन्य कोविड टीकों के निर्माण के लिए भी वचनबद्ध है. भारत में अभी तक के टीकाकरण में बड़ा हिस्सा—लगभग 9 करोड़ खुराक—कोविशील्ड का रहा है जबकि कोवैक्सीन की 96 लाख खुराक का उपयोग किया गया है. एसआइआइ पहले ही सरकार को 10 करोड़ खुराक दे चुकी है और मार्च के अंत में 10 करोड़ और खुराक के लिए एक नया ऑर्डर मिला है. इसके विपरीत, भारत बायोटेक ने 1 करोड़ खुराक वितरित की हैं और उसे 2 करोड़ खुराक के लिए नया ऑर्डर मिला है.

इसकी तुलना में रूस की ओर से विकसित स्पुतनिक-V (स्पुतनिक फाइव) जिसे भारत में उपयोग के लिए अभी-अभी मंजूरी मिली है, ने टीके के उत्पादन के लिए छह भारतीय निर्माताओं के साथ करार कर लिया है और इसके बहुत जल्द एक महीने में 85-95 करोड़ खुराक की उत्पादन दर हासिल करने की उम्मीद है. ऐसोला कहती हैं, ''इस स्तर की आपूर्ति से ही हमें सामूहिक टीकाकरण में मदद मिलेगी. हम भारत में सालाना 2 अरब से अधिक खुराक का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं. हम उस क्षमता का लाभ क्यों नहीं लेते? हमने कोवैक्सीन के निर्माण के लिए इकाइयों की क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई?''

अपर्याप्त वित्त पोषण

भारत ने टीकों के विकास के लिए वित्त पोषण तो किया है लेकिन शिकायत

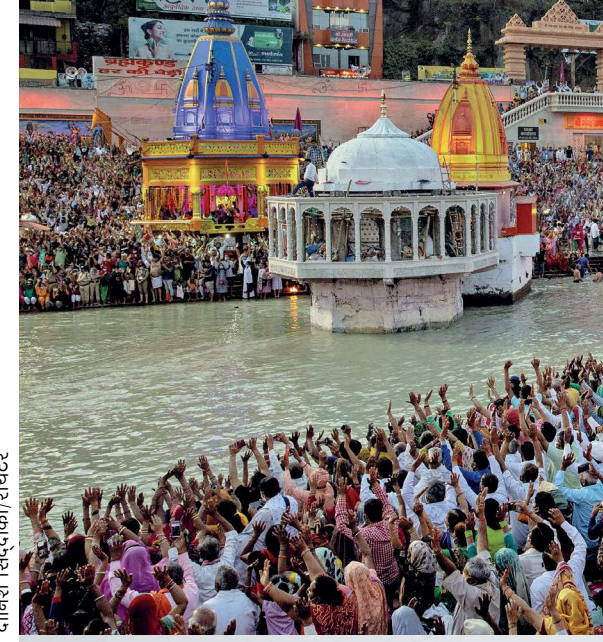

दानिश सिद्दीकी/रॉयटर

देवज्योति चक्रवर्ती

टीके की आपूर्ति में कमी

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को मिलाकर भारत के पास एक साल में किसी भी तरह के टीकों की 3 अरब खुराक बनाने की क्षमता है. लेकिन निर्यात प्रतिबद्धताओं, देर से मंजूरी और धीमे विनिर्माण के कारण देश को 3 महीनों में केवल 11 करोड़ खुराक मिल सकी हैं

कोविशील्ड

निर्माता
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

निर्माण क्षमता
कोविशील्ड की 7-10 करोड़ खुराक प्रतिमाह; अन्य टीकों की 1.3-1.5 अरब खुराक सालाना

वाएल्स (शीशियां)भारत को मिलीं
10 करोड़; 10 करोड़ अतिरिक्त का ऑर्डर मार्च के अंत में प्राप्त हुआ

प्रत्येक वाएल्स के लिए चुकाई कीमत
210 रुपये; नए ऑर्डर की कीमत 150 रुपये

राजस्व अर्जित
अपने कोविड टीकों से दो वर्षों में 4 अरब डॉलर (लगभग 30,052 करोड़ रुपये) का राजस्व अनुमानित है; कंपनी ने 80 से अधिक देशों को 7 करोड़ खुराक की आपूर्ति करके पिछले तीन महीनों में 25 करोड़ डॉलर (लगभग 1,878 करोड़ रुपये) की बिक्री दर्ज की.

निर्यात प्रतिबद्धताएं
↘ एआइआइ ने गावी वैक्सीन अलायंस और बिल ऐंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 250 रुपये प्रति खुराक की दर से 20 करोड़ टीके की खुराक की आपूर्ति का वादा किया है.

↘ कम और मध्यम आय वाले देशों को एक अरब खुराक की आपूर्ति का एस्ट्राजेनेका का एसआइआइ के साथ सब-लाइसेंसिंग करार है.

विनिर्माण योजनाएं
चेयरमैन आदर पूनावाला ने हाल ही में कहा कि भारत में उत्पादन क्षमता ''अत्यधिक दबाव'' में है और उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए 3000 करोड़ रु. की जरूरत होगी.

प्रभावकारिता
59.9% (खुराक देने के अंतराल पर निर्भर)

भारत में दी गई खुराक
9,73,18,156

आस्था और राजनीति हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान एक शाम पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़; और (नीचे) 24 मार्च को पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए चुनावी रैली में लगा भाजपा समर्थकों का जमघट

है कि इसके लिए रखी गई रकम विशाल लक्ष्य को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है. नवंबर में सरकार ने 5-6 टीकों के विकास में तेजी लाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक कोविड-19 टीका विकास मिशन के लिए 900 करोड़ (12.0 करोड़ डॉलर) के मिशन कोविड सुरक्षा की घोषणा की. कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने भी हैदराबाद और बेंगलूरू के अपने केंद्रों के विकास के लिए क्रमश: 150 करोड़ रुपये और 75 करोड़ रुपये की मांग की है. एसआइआइ ने इस साल मई तक प्रतिदिन मौजूदा 6 करोड़ खुराक निर्माण क्षमता को बढ़ाकर 10 करोड़ तक करने के लिए इस फंड से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है और बैंकों से भी कर्ज मांगा है. एसआइआइ के सीईओ आदर पूनावाला कहते हैं, ''हमें मोटे तौर पर 3,000 करोड़ रुपये चाहिए जो छोटी रकम नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि हमने पहले ही हजारों करोड़ रुपये इसके लिए खर्च किए हैं.'' पूनावाला का यह भी कहना है कि वे मुनाफे को पूरी तरह से त्यागने और अत्यधिक रियायती मूल्य पर खुराक देने के लिए सहमत हो गए थे. कोविशील्ड, जिसकी कीमत प्रति खुराक 210 रुपये थी अब भारत को 150 रुपये प्रति खुराक की नई दर पर दी जा रही है.

अमेरिका से तुलना करें तो सरकार के एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम ऑपरेशन वार्प स्पीड (ओडब्ल्यूएस) के तहत कोविड-19 टीकों के विकास, निर्माण और वितरण में तेजी लाने के लिए अमेरिकी सरकार अक्तूबर तक के लिए 18 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता दे रही है. यूएस बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एस्ट्राजेनेका को टीका विकसित करने के लिए 1 अरब डॉलर से अधिक दिए. जर्मन सरकार ने बायोएनटेक को अपने टीके को नैदानिक चरण में ले जाने के लिए सहयोग के लिए 44.5 करोड़ डॉलर दिए. बाद में फाइजर ने एक टीके के विकास के लिए इसके साथ समझौता भी किया. ब्रिटेन की सरकार ने कोविड-19 टीकों पर लगभग 1.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जिसमें टीका विकसित करने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों के लिए 82.6 करोड़ डॉलर तक का योगदान और एक नई वैश्विक टीका-साझाकरण योजना में 69.0 करोड़ डॉलर का योगदान शामिल है.

विशेषज्ञों का कहना है कि मामूली निवेश, मुनाफे के लिए निजी बाजार में

कोवैक्सीन

निर्माता
भारत बायोटेक

निर्माण क्षमता 1.25 करोड़ खुराक प्रतिमाह

वाएल्स भारत को मिले
1 करोड़; 2 करोड़ का नया ऑर्डर मार्च के अंत में मिला.

प्रत्येक वाएल्स के लिए चुकाई कीमत
295 रुपये; नए ऑर्डर के लिए 150 रुपये

राजस्व अर्जित
लागू नहीं

निर्यात प्रतिबद्धता
↘ कंपनी 40 अन्य देशों में मंजूरी की कोशिशों में जुटी है, जल्द ही कुछ टीकों का निर्यात शुरू होने की उम्मीद

↘ ब्राजील को कोवैक्सीन सप्लाइ के लिए इसने एक फर्म प्रेसिसा मेडिकेमेंटोस से करार किया है

विनिर्माण योजनाएं
बेंगलूरू और गुजरात के अपने प्लांट का उपयोग करते हुए इसने 7 करोड़ खुराक प्रतिमाह के उत्पादन की योजना बनाई है.

प्रभावकारिता
81% चरण 3 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार

भारत में लगाए गए टीके की संख्या

91,48,337

स्पुतनिक V

निर्माता

डॉ. रेड्डीज, हेट्रो बायोफार्मा ग्लैंड फार्मा, स्टेलिस बायोफार्मा, पेनेशिया बायोटेक और विरको बायोटेक

निर्माण क्षमता सालाना 85 करोड़ खुराक

वाएल्स भारत को मिले
ऑर्डर के मूल्य का निर्धारण बाकी है और टीके मई से मिलने शुरू हो जाएंगे.

प्रत्येक वाएल्स के लिए चुकाई कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 750 रुपये; भारत में अभी मूल्य निर्धारण होना बाकी है.

निर्यात प्रतिबद्धताएं
↘ 60 देशों में आपात उपयोग के लिए मंजूरी प्राप्त

↘ भारत में निर्मित टीकों का निर्यात होगा जो कि कंपनियों की ओर से अपने स्तर पर किए करार पर निर्भर होगा.

प्रभावकारिता
91.6%अगर 21 दिनों के अंतराल पर दो खुराक ली जाए.

स्रोत: राज्य सभा कमेटी रिपोर्ट; Cowin.gov.in

वैक्सीन पाइपलाइन

राष्ट्रीय
कोविड-19 के लिए टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) टीके से संबंधित सभी अनुमोदन, वितरण, खरीद, वित्तपोषण, आपूर्ति, सुरक्षा और संचार का मार्गदर्शन करता है

राज्य
राज्य स्तर पर गठित एक संचालन समिति और टास्क फोर्स प्राप्त टीकों का वितरण आयु, जनसांख्यिकी और संक्रमण के मामले के आधार पर विभिन्न जिलों को करती हैं

जिले
जिला समितियां राज्य से मिले टीके की खुराक की संख्या, टीका लगाने वालों को भुगतान और विभिन्न केंद्रों पर वैक्सीन पहुंचाने के कार्य की निगरानी करती हैं. समितियों ने भी 24/7 हेल्पलाइन शुरू की है

नियंत्रण शृंखला

मंजूरी
एनईजीवीएसी और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) विभिन्न निर्माताओं की ओर से पेश डेटा के आधार पर टीके को मंजूरी देते हैं और 13 अप्रैल तक भारत में एक ब्रिजिंग स्टडी करने की भी अनिवार्यता हुआ करती थी.

राज्यों को वितरण
भारत में लागत को 35,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से प्रबंधित किया जाता है और एनईजीवीएसी इसका कॉर्डिनेशन करता है; आपूर्ति शृंखला की ट्रैकिंग और नियंत्रण CoWin के माध्यम से होता है

जिलों को बंटवारे का फॉर्मूला
स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार जो फॉर्मूला बना है वह इस प्रकार है: एक महीने के लिए टीके की आवश्यकता = (कवर की जाने वाली कुल आबादी × कवर की जाने वाली आबादी का प्रतिशत/ अभियान के महीनों की संख्या) × 2 खुराकें×अनुमानित टीका क्षति

कोल्ड चेन
राज्यों को कोल्ड चेन स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा गया है; कोविशील्ड और कोवैक्सीन को छह महीने तक रखा जा सकता है, पर अभी सरकार भंडारण को हतोत्साहित कर रही है

टीकाकरण केंद्र
अभी 67,893 केंद्रों (61,090 सरकारी, 6,803 निजी) से टीकाकरण हो रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हर केंद्र पर टीका लगाने वालों की पांच-सदस्यीय टीम की जरूरत होती है और प्रति सत्र, प्रतिदिन 100 टीके लगाने की उम्मीद होती है. 41 लाख प्रतिदिन की दर पर, प्रत्येक केंद्र अनुशंसित टीकाकरणों का आधा ही कर रहा है

बेचने का कोई लाइसेंस नहीं होना और सरकार के कम कीमत पर खरीदने के कारण, एसआइआइ और अन्य भारतीय निजी फार्मा कंपनियां विनिर्माण में अधिक पैसा लगाने के लिए अनिच्छुक दिखती हैं और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं. निजी उद्योग से भारी आपूर्ति प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देने की जरूरत थी. वर्तमान में, निर्माताओं ने खुद बड़े निवेश किए हैं. एसआइआइ ने अपने 3,000 करोड़ रु. और भारत बायोटेक ने 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. मेंघाने कहती हैं, ''कोविशील्ड भारत में बना हो सकता है, लेकिन भारत का इस पर कोई अधिकार नहीं है. इसके विकास के लिए 92 अन्य देशों ने वित्त पोषण किया था. भारत ने विकास के स्तर पर अधिक निवेश क्यों नहीं किया?''

बदतर तो यह है जो लोग भारत में बेचने या निर्माण करने के इच्छुक थे, वे हाल तक धीमी और बोझिल प्रक्रिया के शिकार थे और इससे बाजार में टीका देर से आया. कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जनवरी के अंत में मंजूरी मिली थी. डेवलपर के दो राउंड डेटा जमा करने और तीसरे चरण के परिणामों का इंतजार होने के बावजूद, तीसरे टीके-रूस के स्पुतनिक V- को मंजूरी देने में तीन माह लग गए. देश में अध्ययन के लिए निर्धारित जरूरतों से भी कई खिलाड़ी यहां आने से बचते रहे—एस्ट्राजेनेका और जॉनसन ऐंड जॉनसन सहमत हुए, लेकिन फाइज़र ने अपनी बोली वापस ले ली.

हम यहां से कहां जाएंगे?

भारतीय स्वास्थ्य योजनाकारों को संदेश मिल गया है और वे अपने तरीके बदल रहे हैं. भारत में कोविड की सकारात्मकता दर 5.4 प्रतिशत हो गई है जो डब्ल्यूएचओ की अनुशंसित 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक है. इसलिए हमें सभी दिशाओं में प्रयास करने की जरूरत है और विशेष रूप से टीकाकरण को लेकर. नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद, सरकार ने 13 अप्रैल को विदेशी टीकों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया तेज की है. ब्रिजिंग स्टडी की आवश्यकता से भी छूट दे दी गई. हालांकि यह स्वागत योग्य कदम है लेकिन विशेषज्ञों को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है. असोला का कहना है, ''हां, हम अधिक टीकों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं. लेकिन क्या कंपनियां अभी भी रुचि रखती हैं? मुझे लगता है कि फिलहाल हमारे सामने मुख्य सवाल है कि निर्माताओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और साथ ही टीके का समान वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाए.''

अधिकांश दांव हाल ही में अनुमोदित स्पुतनिक-V पर लगाए जा रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सभी टीकों को मुफ्त रखने की जरूरत नहीं है; यदि समाज का कोई वर्ग भुगतान करने को तैयार है तो उसे बाजार के लिए खोलने में कोई बुराई नहीं है. दरअसल, पूनावाला खुद साल की शुरुआत में अपने टीके को 1,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार थे. लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है. भारत में, निजी अस्पतालों के माध्यम से केवल 27 प्रतिशत खुराक दी की गई है; शेष—लगभग 7 करोड़ खुराक- मुफ्त दी गई है. विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी का अनुमान था कि अगर सरकार निजी क्षेत्र को भी टीके के काम में लगाती है तो भारत दो महीने में 50 करोड़ लोगों का

धीरज सिंह/गेट्टी इमेजेज

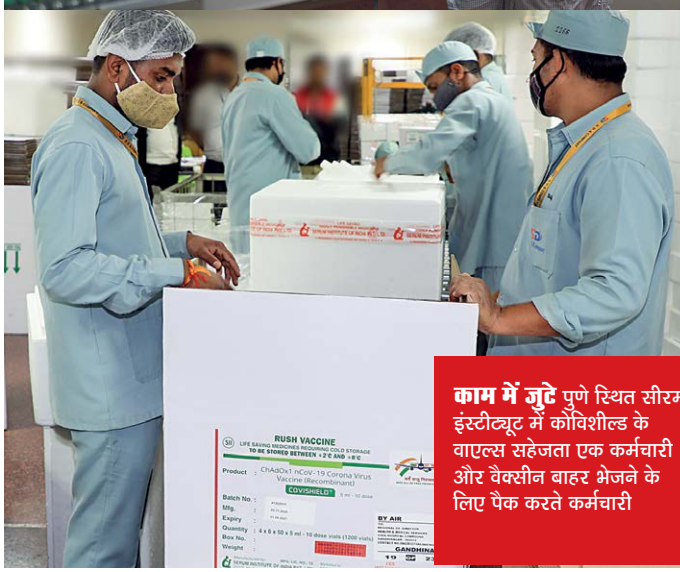

काम में जुटे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड के वाएल्स सहेजता एक कर्मचारी और वैक्सीन बाहर भेजने के लिए पैक करते कर्मचारी

टीकाकरण कर सकता है. निजी खिलाड़ियों को सूचीबद्ध करने से न केवल एक व्यापक पहुंच तय होगी, बल्कि टीका लगाने वालों का भी हित होगा, भंडारण और वितरण क्षमताओं में सुधार होगा, अधिक केंद्र इस प्रणाली से जुड़ेंगे.

इसी तरह, टीका वितरण को भी सुव्यवस्थित किया जा सकता है. खरीद और वितरण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली ईविन सिस्टम और टीके को ट्रैक करने और आवंटित करने के लिए कॉविन ऐप पर निर्भर करती है. लेकिन इस बात का अब तक कोई उचित कारण नहीं दिया गया है कि टीकाकरण के लिए कम पात्र आबादी वाले राज्यों को, अधिक योग्य आबादी वाले राज्यों की तुलना में ज्यादा खुराक क्यों मिली. इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे कोरोना के उच्च सक्रिय मामलों वाले राज्यों को कम मामले वाले राज्यों की तुलना में कम खुराक मिली. टीका विशेषज्ञ गगनदीप कंग की सलाह है कि वायरस फैलने से रोकने के लिए उच्च मामलों या अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में टीकाकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए. राज्य स्तर पर भी ऐसा नहीं हो रहा है. उदाहरण के लिए, जिन जिलों ने अपनी आबादी के उच्चतम प्रतिशत का टीकाकरण किया है, वहां भारत के बहुत कम ही मामले थे. जिन जिलों में मामले बढ़ रहे हैं वे आबादी का टीकाकरण कराने में बहुत पीछे हैं.

अच्छी खबर यह है कि हमें अक्तूबर से पहले कम से कम तीन और टीके मिलने की संभावना है. अहमदाबाद स्थित जाएडस कैडिला के कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट जायकोव-डी का तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है जिसके मई में पूरा हो जाने की संभावना है. फाइजर-बायोएनटेक और मॉडर्ना जैसी कंपनियों की वैक्सीन भी मई-जून में आने की उम्मीद है. जायडस ने सालाना 10 करोड़ खुराक की इन-हाउस विनिर्माण क्षमता बनाई है और प्रति वर्ष लगभग 15 करोड़ खुराक की अतिरिक्त क्षमता के लिए कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं को भी काम पर लगाया है. एसआइआइ और अमेरिकी टीका विकासकर्ता कंपनी नोवावैक्स मिलकर कोवावैक्स विकसित कर रहे हैं, जिसके सितंबर तक आने की संभावना है. दावा है कि कोवावैक्स का कोविड-19 के अफ्रीकी और यूके वेरिएंट पर परीक्षण किया गया है और यह 89 प्रतिशत प्रभावी है. हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल-ई का जॉनसन ऐंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन की सालाना 60 लाख खुराक बनाने का एक अनुबंध-निर्माण सौदा है. अमेरिका में एक शॉट वाले टीके को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और कंपनी भारत में 1,000 वॉलेंटियर्स पर ब्रिजिंग ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रही है. इस बीच, यूएस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने टीकाकरण के कुछ मामलों में रक्त के थक्के जमने की घटनाओं की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए जेएंडजे की वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाई है.

भारत बायोटेक भी नाक से दिए जाने वाले कोविड-19 के अपने टीका का परीक्षण कर रहा है. इसके अध्यक्ष कृष्णा एला ने पहले कहा था कि यदि सरकार नैदानिक परीक्षणों के सभी चरणों के लिए प्रोटोकॉल विकसित कर सकी, तो कंपनी जून 2021 तक टीका बाजार में ला सकती है. वे कहते हैं, ''उत्पादन बहुत आसान है. सुविधा पहले से ही मौजूद है. यह वेक्टर-आधारित टीका है. सफल होने पर मैं 1 अरब से अधिक खुराक बना सकता हूं.''

हालांकि, किसी को पता नहीं है कि टीकों से मिली प्रतिरक्षा कितने समय तक टिकेगी. वर्तमान अनुमान 8-12 महीने का है. वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. स्पष्ट है कि टीका अनुसंधान को जारी रखना होगा और भारत सहित सभी देशों को लगातार टीकाकरण रणनीतियां मजबूत करनी होंगी. लोगों को नियमित फ्लू शॉट की तरह हर साल कोविड के बूस्टर शॉट्स लेने के लिए भी वापस आना होगा.

वायरोलॉजिस्ट टी. जैकब जॉन कहते हैं, ''कोविड खत्म नहीं होने जा रहा. हो सकता है कि समय के साथ यह मंद पड़ जाए. कुछ महीनों में, दूसरे महीनों की तुलना में अधिक मामले देखने को मिल सकते हैं.'' ऐसे में लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने वाले टीकों को ही कोविड-19 के खिलाफ हमारे शस्त्रागार का हिस्सा बनाना होगा. वैक्सीन 2.0 के लिए काम पहले से ही शुरू हो चुका है. इस दौड़ में सीरम की अपनी कोविवैक्स, युनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का एसआइआइ-कोवैक्स, कोडाजेनिक्स के कोवी-वैक के साथ और नोवियोवैक्स के साथ कोवैक्स हैं; जाएड्स की डीएनए वैक्सीन जायकोव-डी, वाशिंगटन युनिवर्सिटी के साथ भारत बायोटेक का इंट्रा-नेजल वैक्सीन और जेननोवा की एमआरएनए वैक्सीन और रिलयांस लाइफ साइंस की पुन:संयोजक वैक्सीन शमिल है. बस, भारतीय स्वास्थ्य योजनाकारों को अतीत से सबक लेते हुए अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचने की जरूरत है.

—साथ में **राहुल नरोन्हा, किरण डी. तारे, रोहित परिहार, आशीष मिश्र, जीमोन जैकब** और **अरविंद गौड़ा**

किस्सा कहने वालों की कहानी

इंडिया टुडे में काम करने वाले कुछ योद्धा जिन्होंने कोविड को मात दी; संक्रमण होने और उससे लड़कर उबरने तथा उसके बाद के अपने अनुभवों को साझा करते हुए

डर, थकान और अकेलापन

सुहानी सिंह
सीनियर एडिटर

करीब ग्यारह महीने तक मैंने खुद को कोविड-19 से बचाकर रखा था. फिर एक दिन यह एक धमाके की तरह आया. मैं हाइपरटेंशन की मरीज अपनी 64 वर्षीय कोविड-संक्रमित मां की देखभाल के लिए अपने माता-पिता के घर दो हफ्ते के लिए चली गई थी. मेरी मां आइसोलेशन में रहीं और ठीक हो गईं. मेरी तीन बार जांच हुई और तीनों बार मैं संक्रमणमुक्त पाई गई थी. पर एक हफ्ते बाद जांच में मैं संक्रमित पाई गई. तो बीमारी की शुरुआत मां को यह आश्वस्त करने की जिम्मेदारी से हुई कि मेरे संक्रमित होने के लिए वे खुद को दोषी न मानें क्योंकि मैंने ऑफिस के बाहर निकलना शुरू कर दिया था. उसके बाद उन लोगों तक पहुंचने की चुनौती थी, जिन्हें मैंने अनजाने में वायरस पहुंचाया हो सकता है. मेरे संपर्क में आई एक महिला के 90 वर्षीय पिता थे; एक की मधुमेह पीड़ित मां. हालांकि बुखार और शरीर में दर्द से मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन उस अपराध बोध ने मेरी तकलीफ बढ़ा दी.

अपराधबोध विशेषाधिकार का

चंद्रदीप कुमार

● कोविड पॉजिटिव: 10 अक्तूबर ● स्थिति: 24 अक्तूबर को निगेटिव
📍 जगह: दिल्ली

सोनाली आचार्जी, एसोसिएट एडिटर

यादें भी कैसे अजीब ढंग से बर्ताव करती हैं! जब कोरोना का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो मैंने सोचा कि महामारी के दौरान डॉक्टरों ने मुझे जो सुझाव दिए थे वे सब याद आ जाएंगे. लेकिन इसकी जगह मुझे उन लोगों की आंखें याद आने लगीं जो बहुत निराश और हताश थे—कोविड वार्ड में एक बूढ़ी महिला, जिसे जीवन में पहली बार उसके परिवार से अलग कर दिया गया था; एक युवक जो ऑक्सीजन न मिल पाने से अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करने के लिए वहां के गार्ड से विनती कर रहा था; एक पुलिस अधिकारी जो मुझसे पानी मांग रहा था क्योंकि प्रवासी मजदूरों को हाइवे से हटाने में व्यस्त होने के कारण उसके पास पानी की बोतल भरने तक का समय नहीं था. मेरे संक्रमित होने से पहले नौ महीने से भी ज्यादा समय के दौरान मैंने इस तरह की अनगिनत आंखों में झांका था. लेकिन 14 दिनों के अपने आइसोलेशन के दौरान वे आंखें वापस मुझे देख रही थीं. 20 जुलाई, 2020 तक कोविड के औसत मरीज को अस्पताल में अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होता था जहां एक ही कमरे में खांस रहे 15-20 अजनबी मरीज मौजूद होते थे. जब मैं संक्रमित हुई तो मैंने खुद को अपने दो बेडरूम के मकान में आराम से अलग-थलग कर लिया. बाकियों की तरह मुझे इस बात का डर नहीं था कि मेरी वजह से अपना कोई संक्रमित हो सकता है. मेडिकल सहायता के तौर पर देखें तो महामारी के दौरान जिन डॉक्टरों का मैंने इंटरव्यू किया था, उन सभी से लगातार मेरा संपर्क बना रहा. वे सभी मुझे जरूरी दवाइयों की सूची भेज रहे थे और खाने-पीने तथा अन्य सावधानियों के बारे में जानकारियां दे रहे थे. मेरी लड़ाई अकेलेपन या

● कोविड पॉजिटिवः 22 मार्च ● स्थितिः 7 अप्रैल को जांच में निगेटिव 📍 जगहः मुंबई

फिर वायरस को लेकर भी कभी नहीं थी, बल्कि मेरी लड़ाई मुझे मिल रही इन विशेष सुविधाओं को लेकर एक प्रकार के अपराधबोध से थी.

महामारी के बेहद कठिन महीनों के दौरान मैं जब कोविड पर रिपोर्टिंग कर रही थी तो मैं कल्पना करती थी कि ये सारे लक्षण मेरे अंदर जाएंगे. मुझे पक्का यकीन था कि कोविड के वार्डों में लगातार संपर्क बने रहने से मैं जब वायरस की गिरफ्त में आऊंगी तो मुझे सीधा आइसीयू में ही जाना पड़ेगा. एक सुबह जब मैं उठी तो किचेन में खाना बनाने वाली कुक के काम करने की आवाज सुनाई दी लेकिन मुझे खाना पकने की कोई गंध नहीं आ रही थी. मैं घबरा गई. कुछ मिनट बात पता चला कि उसने वास्तव में अभी तक कुछ पकाना नहीं शुरू किया था. और जब वास्तव में मुझे कोविड हुआ तो केवल पेट थोड़ा खराब होने और महीने भर की थकान के सिवा और कोई परेशानी नहीं हुई. मेरा काम, मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन कभी बाधित नहीं हुआ, पर समानता को लेकर मेरे विश्वास को जरूर आघात लगा.

बहरहाल, मैंने जो पाया, वह यह था कि भारत में समाज के विभिन्न वर्गों को संकट के समय किस कदर कीमत चुकानी पड़ती है. जिन दिनों मुझे खाना पकाने में बहुत ज्यादा थकान होती थी, तब अच्छे पड़ोसी, मित्र, यहां तक कि पुराने सहकर्मी मेरे लिए आगे बढ़कर खाना पहुंचा दिया करते थे. अगर मंगाई गई दवाइयां समय पर घर नहीं पहुंच पाती थीं तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड खुद दवाई लाने के लिए कहता और लाकर मुझे दे देता था. एक बार मैं रात में दो बजे जाग गई और रोने लगी क्योंकि मैंने एक डरावना सपना देखा था. मैंने देखा कि मैं किसी कोविड वार्ड में खो गई थी. तब मेरे एक मित्र ने फोन पर मुझे ढांढस बंधाकर शांत किया. एक बार कोविड को हरा चुके 92 साल के एक व्यक्ति ने फोन पर मुझे बताया था, ''मैं दयालुता के बल पर बच सका.'' आखिरकार जब मैं कोविड से मुक्त हो गई तो मैंने भी ऐसा ही महसूस किया.

एक साल से अधिक समय तक कोविड से जुड़े लेखों की एक अच्छी खुराक मुझे मिली थी और डर झलक रहा था, खासकर शुरुआती दिनों में. मैं अपने एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में अकेली क्वारंटीन में थी और इस बात ने घबराहट और बढ़ाई थी. लोग दरवाजे के बाहर खाना रखकर चले जाते थे. 18 दिनों तक मैंने जिस एकमात्र इंसान को देखा वह लेबोरेट्री वाला लड़का साईंनाथ था जो आरटी-पीसीआर और खून की जांच के नमूने लेने के लिए आया था. मुझे पता है कि इस भीड़भाड़ वाले शहर में एक एकांत जगह उपलब्ध होना भी एक लग्जरी है, लेकिन अकेलेपन ने बीमारी से लड़ने की प्रक्रिया को थकाऊ बना दिया. मेरे अंदर किताबों या नेटफ्लिक्स में सुकून ढूंढ़ने की ऊर्जा नहीं है. इसके बजाय, अनुलोम विलोम और सांस के दूसरे व्यायामों में मुझे सुकून मिला. जब दवाओं की खुराक कम हो गई, मैंने कोरियाई क्राइम ड्रामे (*50 ऑवर्स ऑफ स्ट्रेंजर और सिग्नल*) देखना शुरू किया.

लेकिन जैसे-जैसे मेरी थकान कम होती गई, मेरी व्यग्रता बढ़ती जा रही थी. इसकी एक वजह वह जागरूकता थी कि वायरस म्यूटेट कर रहा है. मैं डर गई कि इस सूक्ष्म घुसपैठिए ने मेरे शरीर में क्या कर दिया है जो अभी भी अपने कोविड पूर्व स्थिति में लौटने की कोशिश कर रहा है. मैं बिना थकान महसूस किए अपने पालतू कुत्ते आइशा के साथ टहलने में सक्षम होना चाहती हूं. मैं आवारा कुत्तों को फिर से खिलाना और अपनी कथक क्लास में फिर से जाना शुरू करना चाहती हूं. मैं फिर से संक्रमित होने के बारे में चिंता किए बिना बाहर निकलना चाहती हूं, जो कि मेरे पड़ोस की लगभग हर इमारत के बाहर लटकती बीएमसी की नोटिस की तादाद को देखते हुए कठिन लगता है. मैं अपने मस्तिष्क को उतना रचनात्मक रखना चाहती हूं जिसे ऐसे पासवर्ड न सूझें जो महामारी से संबंधित हों.

एक वैश्विक आंकड़े का हिस्सा होना, एक 'सर्वाइवर' कहा जाना कुछ अजीब-सा लगता है. एक दशक से कुछ पहले पीलिया से जूझने का मेरा अनुभव बहुत खराब रहा था, लेकिन कोविड के साथ मेरा यह संघर्ष शारीरिक से अधिक भावनात्मक रहा है. एक दोस्त ने बताया कि उसकी मां वेंटिलेटर पर हैं; एक अन्य दोस्त जिसकी मां कैंसर से उबर कर आई हैं, को अपनी मां की जिंदगी की चिंता सता रही है; एक और सहेली जो अपने बीमार पति की तीमारदारी कर रही है, उसमें भी लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं. कोरोना वायरस ने भले ही मेरा शरीर छोड़ दिया हो, लेकिन असल में मेरे दिमाग पर अब भी उसका कब्जा है.

वायरस का 'मजाक'

● कोविड पॉजिटिवः 31 मार्च ● स्थितिः 14 अप्रैल को जांच में निगेटिव ● जगहः दिल्ली

काइ फ्रीजे, मैनेजिंग एडिटर

आपदाओं के भी अपने मजेदार पक्ष होते होंगे, लेकिन हमारे दौर की यह कयामत की सी रात इतनी लंबी हो गई है कि इसमें कोई ह्यूमर देख पाना मुश्किल है. हां, अगर आप बोझिल, सारगर्भित, विडंबनापूर्ण चीजों में भी विनोद खोज सकें तो अलग बात है. ऐसी हालत में तो लगता है कि आप क्वारंटीन की एक लंबी डरावनी यात्रा पर हैं और खुद अलानिस मॉरुशेट मक्खी की तरह भुनभुना रहे हैं. मैं सचमुच ऐसा आदमी हूं जो हवाई यात्रा से डरता था–और महामारी के बाद की अपनी पहली हवाई यात्रा से लौटने के अगले दिन मुझे कोविड होने का पता चला. मजे की बात देखिए कि उस दिन मैंने अपने कोविड के पहले टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. जाहिर है कि वह मौका बेकार गया–पर कितना विडंबनापूर्ण है! आपको नहीं लगता?

फिर सारी बातें व्यर्थ होने का बोध. दूसरों को संक्रमित करने के डर के अलावा–एक विडंबनापूर्ण विनोद यह भी था कि मैं 'लुटियंस का तब्लीगी' था–यह एक बहुत बड़ी बीमारी थी. मुझे पता है, मैं भाग्यशाली था और जब मेरा संक्रमण ठीक होने की ओर बढ़ रहा था, उस दौरान मेरे तीन दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक और भद्दा मजाक यह था कि इसे कोविड की 'सेलिब्रिटी लहर' बताया जा रहा था, जिसने सचिन तेंडुलकर, आलिया भट्ट, फारुक अब्दुल्ला समेत कई बड़ी हस्तियों को अपनी चपेट में लिया था. उससे उस लोकप्रिय अफवाह को बल मिलता है कि यह अमीरों की बीमारी है. यह अपने आप में कहीं अधिक विडंबनापूर्ण आक्षेप था. असल में, मैं घरेलू सहायक का काम करने वाली उस महिला की तीखी फटकार के निशाने पर था, जिसने मेरे बीमार होने से एक दिन पहले एक दोस्त के घर पर मुझे रात का खाना परोसा था. यह सुनने के बाद कि मैं कोविड संक्रमित पाया गया हूं, उसने काम पर आने से मना कर दिया और शिकायत की कि मैंने जांच कराके गलत किया है! यह कहते हुए कि जांच कराने से ही बीमारी होती है, उसने मेरे दोस्त को बताया कि बीते कुछ महीनों में उसमें कोविड के कई लक्षण दिखे थे, पर उसने कोविड की जांच कभी नहीं कराई और इसीलिए उसे कोविड नहीं हुआ!

मुझे यह काफी मजेदार लगा, बीमारी के लिए श्रोडिंजर के अनिश्चितता के सिद्धांत की तरह जो बिल्ली को एक ही समय जीवित भी मानता है और मृत भी. इस बीच, परिजनों-दोस्तों से मुझे तरह-तरह की सलाह मिलती रही जिसमें सभी ने ज्यादा भरोसा एक घरेलू उपाय पर जताया, ''अपने फेफड़ों को मजबूत करने'' के लिए भाप लेना. यह क्वारंटीन की ऊब से भन्नाए व्यक्ति के साथ क्रूर मजाक जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि क्या वाकई यह काम करेगा? उस पर प्रतिक्रिया देते समय मैंने डॉक्टर की आंखों को अपने फोन स्क्रीन पर आंखे नचाते किसी इमोजी की तरह पाया. उन्होंने शालीन लेकिन वास्तविक विडंबना के साथ कहा, ''जरूरी नहीं''.

करना पड़ता है भाई

● कोविड पॉजिटिवः 7 अप्रैल ● स्थितिः इलाजरत

जगहः पटना

अमिताभ श्रीवास्तव, सीनियर एसोसिएट एडिटर

अपने परिवार के लिए रोज तीन वक्त का खाना/नाश्ता बनाने की कोशिश में छीलते-काटते-छौंकते हुए पिछले हफ्ते मैंने कई जगह हाथ काट लिए और जल गया. मैंने कभी इस तरह खाना नहीं बनाया, पर क्या कीजिएगा! जरूरत पड़ने पर करना ही पड़ता है. 7 अप्रैल को हमारा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया. पत्नी सुनंदा और मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकला. शुक्र था कि 11 वर्षीया बेटी साइया बच निकली.

यह सब 5 अप्रैल की मायूस सुबह शुरू हुआ. मैंने देखा कि मेरी पत्नी तेज बुखार से कंपकंपा रही थीं. दो दिन बाद टेस्ट ने तस्दीक की कि हमें कोविड था. मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत से ही हम वायरस से बचने में कामयाब रहे थे. यहां तक कि तब भी जब मैं काम के सिलसिले में क्वारंटीन केंद्रों पर जाता और महामारी की खबरें करता. यह सब मास्क की अच्छी आदतों की बदौलत हुआ, पर ताजा उभार के वक्त में किसी न किसी तरह मास्क की अनदेखी करने लगा था.

हमारी बेटी को हमारे दो बेडरूम के अपार्टमेंट के एक कमरे में डाल दिया गया. वह ज्यादातर उसी में घिरकर रह गई है. पहली रात को मैंने उसे कमरे से बाहर कुछ खोजते देखा था. वह उसकी डॉल थी जिसे वह अपने साथ सुलाना चाहती थी.

दवाइयां लेने और अपने लक्षणों से निबटने की समूची उदासी के बीच मेरी पत्नी की स्थिति मुझसे बदतर है. मैं तो खुशी और मौज-मस्ती के कुछ लम्हे चुरा ही लेता हूं—सद्गुरु जग्गी वासुदेव के वीडियो से शांति और ज्ञान हासिल करके, अपनी बेटी (जिसे सेलफोन पर मुझे कॉल करके 'रूम सर्विस' का ऑर्डर देना अच्छा लगने लगा है) के लिए हॉर्लिक्स बनाकर और अपने भीतर के पत्रकार को कुछ वक्त के लिए छुट्टी देकर.

हम यह पक्का पता नहीं लगा पाए हैं कि वायरस हमारे घर में घुसा कैसे (यह 31 मार्च को मेरे सरकारी सचिवालय जाने से आया या शायद एसी सर्विस के लिए आए तकनीशियनों से). पर अब मेरे लिए इसका मतलब नहीं रहा. अलग-थलग रहते हुए अब मेरा मकसद अगली बार पहले से बेहतर सब्जी बनाना होता है, वह इसलिए कि बेटी को पिता की खराब कुकिंग की वजह से तकलीफ उठाते न देखना पड़े.

बेटी की बदौलत

● कोविड पॉजिटिवः 8 अप्रैल ● स्थितिः इलाजरत जगहः मुंबई

किरण डी. तारे, सीनियर एसोसिएट एडिटर

दरअसल, रिपोर्टर होने के नाते मैंने हमेशा बाहर फील्ड में होना और दफ्तर में बैठकर भी लोगों से बातचीत करना पसंद किया है. अप्रैल और जुलाई 2020 के दौरान जब मुंबई हॉटस्पॉट था, मैं महामारी की खबरों के लिए अक्सर धारावी और अस्पतालों सरीखे शहर के बुरी तरह प्रभावित इलाकों में जाया करता था. बीते कुछ महीनों के दौरान मैंने काम के सिलसिले में महाराष्ट्र के विदर्भ (नया हॉटस्पॉट), गोवा और गुजरात की यात्राएं कीं. इन सभी यात्राओं के दौरान भी मैं खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा था.

अलबत्ता 5 अप्रैल को मुझे तेज बुखार हो गया. एक दिन

बाद सूखी खांसी होने लगी. 8 अप्रैल को आरटी-पीसीआर टेस्ट ने तस्दीक कर दी कि मुझे और मेरी पत्नी को कोविड है. हम फौरन अपने एक बेडरूम के अपार्टमेंट के हॉल में आ गए और हमारी बेटियां, 16 साल की रावी और 10 साल की सरयू, बेडरूम में बंद हो गईं. शुक्र है कि मैंने अपने सत्तर से ऊपर के पिता को पिछले साल महामारी की शुरुआत में अपने चाचा के घर जलगांव भेज दिया था.

अब घर में घिरकर मैं न तो अपनी स्पोर्ट्स साइकिल और न ही एक्टिवा स्कूटर चला पाता हूं. अखबार के बगैर सुबह बोझिल हो गई है. मेरी जानकारी और मेलजोल टीवी न्यूज और मोबाइल के मैसेज तक सीमित हैं. मैंने नितिन गोखले की किताब *मनोहर पर्रीकरः ब्रिलिएंट माइंड, सिंपल लाइफ* पढ़ना शुरू किया है.

इधर मेरी पत्नी और मैं बीमार पड़े थे, उधर रावी ही घर चला रही थी—थोड़ी-थोड़ी देर में हमें गर्म पानी से लेकर हमारे टिफिन बॉक्स देने, बर्तन मांजने और अपनी नटखट लेकिन संवेदनशील छोटी बहन की देखभाल करने तक. रावी यह सब अपनी 12वीं की, और सरयू की भी, पढ़ाई के साथ-साथ संभाल रही है. बीते कुछ दिनों के दौरान अपनी बड़ी बेटी को देखकर मेरा यह यकीन पुख्ता ही हुआ है कि बेटियां हमारी जिंदगी की सबसे बेशकीमती धरोहर हैं.

कोविड के काले बादलों में उम्मीद की दूसरी किरण वह लगाव है जो हमें अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और साथियों से मिला. शुरुआत में मैंने अपनी बीमारी के बारे में खामोश रहने का जतन किया, पर बात फैल गई और फिर मदद का तांता लग गया. उनकी दयालुता से मुझे ताकत मिली और पुख्ता यकीन हुआ कि मैं पहले से भी ज्यादा उत्साह और ऊर्जा के साथ जल्द काम पर लौटूंगा.

कुछ है अभी जो बाकी है

चंद्रदीप कुमार

● कोविड पॉजिटिवः 22 अगस्त, 2020 ● स्थितिः 5 अक्तूबर को निगेटिव

जगहः गाजियाबाद

शुभम शंखधर, एसोसिएट एडिटर

यह बीते साल अगस्त की बात है. मैं कोरोना की पहली ही लहर की चपेट में आ गया था. मार्च से अगस्त तक लगातार फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते हुए भी मैं एहतियात तो पूरी बरत रहा था. लेकिन अगस्त में एक रोज तेज बुखार ने जकड़ लिया. तीन दिन बाद डॉक्टर की सलाह पर टेस्ट करवाया तो पता चला कि कोविड देवता मुझे भी प्रसाद दे चुके हैं.

साथ रहने वाला छोटा भाई और बहन भी संक्रमित हो गए. पत्नी और दोनों नन्हीं बेटियों को पहले ही दिन दिल्ली में एक रिश्तेदार के यहां भेज दिया था. वायरस का लोड ज्यादा होने के कारण जब तबियत बिगड़ी तो मैं कौशांबी के एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया.

कोविड की इस जंग के दौरान सबसे भयावह दृश्य मैंने अस्पताल में ही देखा. मेरे बेड के सामने लेटे मरीज को खून की उल्टियां होती थीं, साथ वाले मरीज के फेफड़ों पर गहरा असर हुआ था और उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी. उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रखा गया था. एक मरीज की जान बचाने के लिए प्लाज्मा चढ़ाना पड़ा. निजी अस्पतालों में तेज भागते बिल और सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी की चल रही खबरों के तार अब मैं यहां जोड़ पा रहा था.

दरअसल कोरोना शरीर से ज्यादा मन के स्तर पर लड़ी जा रही लड़ाई थी. मम्मी-पापा और दूसरे परिजन चाहकर भी तीमारदारी के लिए नहीं आ सकते. यह अकेलापन मुझे इस दौरान बहुत खला. कोरोना के कारण कमजोरी इस कदर थी कि फोन उठाने या बात करने की इच्छा ही नहीं करती थी. कोरोना के कहर की खबरें मुझसे दूर मेरे परिवार वालों और शुभचिंतकों को बेहद परेशान कर रहीं थीं. इस मुश्किल समय में मेरे सहयोगी, मेरा संस्थान निश्चित तौर पर मेरे साथ खड़े थे. जिसने मुझे इस बीमारी से उबरने में बहुत मदद की.

स्थिति यह है कि कोरोना से उबर जाने के बावजूद बहुत-सी चीजें अब भी ऐसी हैं जो पहले जैसी सामान्य नहीं हो पा रहीं. एक तरह की चिंता/एन्जाइटी बार बार घेर लेती है.
पता नहीं क्या होगा? छोटी-सी भी तकलीफ का ज्यादा परेशान करना, कोविड से पहले अच्छी लगने वाली चीजों के प्रति उदासीन हो जाना, ऐसी कई समस्याओं से मैं करीब आठ महीने बीतने के बाद भी लड़ रहा हूं.

अलहदा नजरिया

● कोविड पॉजिटिवः 8 अप्रैल ● स्थितिः इलाजरत ● जगहः मुंबई

मंदार देवधर,
चीफ फोटोग्राफर

वर्ष 2020 के दौरान मुझे फोटो जर्नलिस्ट होने के नाते तकरीबन रोज बाहर जाना और महामारी को कैमरे में दर्ज करना होता था. इसी काम से मैं दिन भर बेहद एहतियात बरतते हुए घूमता और घर पहुंचते ही परिवार के किसी सदस्य के संपर्क में आए बगैर खुद को अच्छी तरह सैनिटाइज करता. अपने सामान और बैग को घर के एक कोने में रख देता और उन्हें भी सैनिटाइज करता. मेरी पत्नी गृहणी हैं और महामारी के प्रकोप के बाद मुश्किल से ही कभी घर से बाहर निकलीं. मेरा 17 साल का बेटा भी घर पर रहकर एचएससी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करता रहा जो 23 अप्रैल से शुरू होने वाली थी.

इस दौरान मैं वायरस से बचने में सफल रहा था. यहां तक कि मार्च 2021 में दो दिन की गोवा यात्रा के बाद भी. 20 मार्च को मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही मैंने आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जो निगेटिव आया. पर वापसी के नौ दिन बाद मुझे कुछ खटका. मैं कमजोर महसूस कर रहा था. 1 अप्रैल आते-आते मुझे थोड़ी खांसी और सर्दी-जुकाम हुआ. पारिवारिक डॉक्टर की सलाह से मैंने दवाई ली. अगले दिन मुझे बेहतर लगा, पर उस रात मेरी पत्नी को तेज बुखार और बदन दर्द होने लगा. 3 अप्रैल को मेरे बेटे को भी बुखार हो गया. वह एक दिन में ठीक हो गया, पर मेरी पत्नी और मैं 8 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव निकले. डॉक्टरों ने हम दोनों को होम क्वारंटीन की सलाह दी.

मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे मददगार पड़ोसी मिले, जिन्होंने व्यस्तताओं के बावजूद हमें सारे वक्त घर का बना ताजा खाना दिया और जरूरत पड़ने पर वे किराने की और अन्य चीजें भी लाए. मेरी हाउसिंग सोसाइटी के आधे बाशिंदे पत्रकार हैं, लिहाजा काफी जागरूकता और आपसी सहयोग है. असल में अप्रैल 2020 में हमारी बिल्डिंग शहर की उन पहली इमारतों में थी जिन्हें बीएमसी ने सील कर दिया था क्योंकि परिसर में पांच फोटो जर्नलिस्ट कोविड पॉजिटिव मिले. मैंने पूरे साल कोविड से जुड़ी तस्वीरों को कैमरे में कैद किया, पर कैमरे के पीछे से देखने के बजाय बीमारी को भीतर से अनुभव करना बहुत अलहदा है. इस बीमारी से बच निकलने के बाद मुझे लगता है कि मैं फिर काम पर लौटते वक्त कुछ बेहतर और अलग नजरिया ला सकता हूं.

“हमें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है. पर्यावरण संकट को समझते हुए हर राष्ट्र को इसके समाधान में भूमिका बढ़ानी होगी”

जो बाइडन प्रशासन ने इस साल जनवरी में पदभार संभालने के बाद सबसे पहले जो फैसले किए उनमें 2015 के पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने का निर्णय था. उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2020 के अमेरिकी चुनाव से महज छह महीने पहले इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था. बाइडन 22 अप्रैल को एक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं. उम्मीद है कि इसमें वे भारत सहित प्रमुख उत्सर्जक देशों के प्रमुखों को 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की प्रतिबद्धता जताने को राजी करेंगे. जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत **जॉन केरी** पिछले हफ्ते भारत में थे. उन्होंने ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) **राज चेंगप्पा** के साथ इस मुद्दे पर एक्सक्लूसिव बातचीत की. उसके अंश:

प्र. आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की और 2050 तक सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए तैयार करने के अपने मिशन पर चर्चा की. इसमें भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?

भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. सबसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक अग्रणी लोकतंत्र हैं; एक विशाल राष्ट्र जो इसके मानवतावादी मूल्यों और पृथ्वी के साथ इसके रिश्ते और उसके प्रति जिम्मेदारी के लिए भी जाना जाता है. भारत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है क्योंकि एक देश के रूप में यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है—हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा और चीन पहले नंबर पर है. इसलिए, हमारी विशेष जिम्मेदारी बनती है. हम तीनों दुनिया के उत्सर्जन के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं. इसलिए भले ही भारत का उत्सर्जन हमारे मुकाबले बहुत छोटा हो, आधे से भी कम, लेकिन हम सब को मिलकर काम करना होगा क्योंकि कोई भी राष्ट्र अकेला इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता. हर राष्ट्र को समाधान का हिस्सा बनना होगा. हम एक दूसरे पर निर्भर हैं.

इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारत नवाचार, उद्यमशीलता के प्रयासों, अनुसंधान और विकास और इस तरह की कई अन्य खूबियों वाला देश है. हम नई प्रौद्योगिकियों की खोज में तेजी लाने के लिए अमेरिका और भारत के बीच एक साझेदारी में विश्वास करते हैं जिसकी जरूरत हमें जलवायु संकट से निबटने और अगले दस वर्षों में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से 450 गीगावाट बिजली उत्पादन की प्रधानमंत्री मोदी की बहुत आक्रामक और महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, वित्त और अन्य चीजों के प्रबंध में होगी...हमें यही करने की आवश्यकता है.

● आपने नेट जीरो (वास्तव में शून्य) का प्रस्ताव पीएम मोदी के सामने रखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?

वे बहुत उत्साहित थे और उन्होंने इस पर भरपूर समर्थन जताया. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने साल 2030 के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है और वे समझते हैं कि उनका लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है और वे इसे प्राप्त भी करना चाहेंगे. वे काम करने वाले नेता हैं. वे परिणाम चाहते हैं, बयानबाजी नहीं. इसलिए, हम इस साझेदारी को मजबूत करने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद है कि यह दुनिया के अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बन सकता है.

डेनियल पॉकेट/गेट्टी इमेजेज

ड्रयू एंगरर/गेट्टी इमेजेज

● अमेरिका अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों से जुड़ता और फिर उन्हें छोड़ता रहा है...
ज्यादातर शामिल ही रहा है...

● हमें खुशी है कि कुछ समय के लिए पेरिस समझौते से बाहर रहने के बाद आप वापस आ गए हैं. यह अच्छा है कि बाइडन प्रशासन इसको लेकर सक्रिय रहा है, लेकिन आप अन्य राष्ट्रों को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आपका प्रशासन केवल बातों तक सिमटा नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वास्तव में काम करेगा और अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटेगा?
हमें ठीक वही करने की जरूरत है जो राष्ट्रपति बाइडन कर रहे हैं. उन्होंने शपथ ग्रहण करने के कुछ घंटों के भीतर पेरिस समझौते के साथ फिर जुड़ने की घोषणा कर दी. राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश जारी किए, जिसमें कहा गया कि उनकी सरकार के हर फैसले में जलवायु के प्रति सुसंगति होनी चाहिए. राष्ट्रपति ने बहुत आक्रामक और महत्वपूर्ण कानून बनाया है और अमेरिका के बुनियादी ढांचे, हमारी ऊर्जा ग्रिड का निर्माण करने, गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने और देश में 5,00,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर का आवंटन किया है. कई अलग-अलग काम करने के लिए राष्ट्रपति दृढ़ हैं क्योंकि इनसे नौकरियां पैदा होंगी और इसका लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, प्रदूषण को कम करने और जलवायु संकट को दूर करने पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है.

इसलिए, राष्ट्रपति बाइडन के नेतृत्व वाला संयुक्त राज्य अमेरिका इसको लेकर एकदम स्पष्ट है कि हमें केवल बातें नहीं करनीं बल्कि काम करके दिखाने की जरूरत है. हम काम करके दिखाएंगे. वे 22 अप्रैल को शिखर सम्मेलन में उत्सर्जन में कटौती के हमारे लक्ष्यों की घोषणा करेंगे और हम अपने प्रयासों में बहुत आक्रामक होंगे. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते से भले ही हाथ खींचे थे लेकिन अमेरिका के अधिकांश गवर्नर इसके साथ बने रहे थे. अमेरिका के अधिकांश मेयरों ने भी समझौते के को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी थी. भले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना किसी विज्ञान के, बिना किसी वास्तविक तर्क के यह फैसला कर लिया कि हम पेरिस समझौते से बाहर निकल जाएं लेकिन अमेरिकियों का विशाल बहुमत इस समझौते के पक्ष में बना रहा. तो, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. बेशक उतना अच्छा नहीं जितना हम कर सकते थे और हमने निश्चित रूप से इन पिछले चार वर्षों में एक खराब संदेश भेजा है. राष्ट्रपति बाइडन ने फैसला किया है कि ओबामा-बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिका ने जैसे प्रतिबद्धताओं को निभाया था, बाइडन-हैरिस प्रशासन भी उसी तरह काम करेगा. और पिछले चार वर्षों में हुए नुकसान की हम भरपाई करने जा रहे हैं.

> “प्रधानमंत्री मोदी काम करने वाले नेता हैं. वे परिणाम चाहते हैं, बयानबाजी नहीं. जलवायु पर अमेरिका-भारत की साझेदारी दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक मिसाल होगी”

● कई भारतीय पर्यावरण एजेंसियों ने कहा है कि भारत के लिए 2050 के अपने लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा जब तक कि प्रमुख उद्योगों, विशेष रूप से इस्पात और सीमेंट में बड़े तकनीकी परिवर्तन नहीं होते. ये तकनीक बहुत महंगी हैं. हमें पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी (ग्रीन टेक्नॉलोजी) या वित्त देने के संदर्भ में अमेरिका कितनी मदद कर सकता है जो हमें उस दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम करेगा?
आपने जो कहा वह सच है. हम प्रौद्योगिकी के मौजूदा स्तर के साथ अपने सभी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते और हम जानते हैं कि हमें इसके बारे में ईमानदार रहना होगा. लेकिन हम नई तकनीकों को भी आज की तुलना में कहीं अधिक तेजी से अपना सकते हैं. हमारे पास इन नई तकनीकों को अपनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है. हम उसे बदलने की कोशिश करने जा रहे हैं. हमारे पास पर्याप्त संयुक्त प्रयास नहीं हैं, एक साथ मिलकर काम करने वाले देश नहीं हैं. यही वजह है कि मैं यहां आया हूं, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडन चाहते हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर अनुसंधान करें और उम्मीद है कि कुछ क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी की खोज कर लें.

हम साथ मिलकर करेंगे. मुझे लगता है कि हमें सहयोग के दृष्टिकोण की आवश्यकता है और अधिक से अधिक लोगों को साथ लाया जाए. उदाहरण के लिए, यूएई ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग, बैटरी पावर की स्टोरेज क्षमताओं को बढ़ाने और अन्य प्रयासों में हमारे साथ काम करने में रुचि रखता है. मुझे यकीन है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे. हमारे लिए चुनौती यह है कि क्या हम समय

पर वहां पहुंच पाएंगे? क्या हम काम का ग्राफ आगे बढ़ाएंगे?

● आपने अच्छा सवाल उठाया. मिसाल के तौर पर चीन का कहना है कि वह 2050 तक अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करेगा, वह उसे 2060 तक करना चाहता है. इस समय चीन के साथ आपके संबंध कुछ टकरावपूर्ण नजर आते हैं और भारत के भी. ऐसे में चीन भी साथ आएगा, इसको लेकर आप कितने आश्वस्त हैं?

मैं इस पर आश्वस्त तो नहीं हूं लेकिन आशान्वित जरूर हूं क्योंकि चीन इसमें बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. चीन की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है. यह एक विशाल, शक्तिशाली राष्ट्र है और हमें उम्मीद है कि वह इस अभियान में साथ आएगा और नेतृत्व करेगा. राष्ट्रपति शी ने इसमें चीन की नेतृत्व वाली भूमिका के बारे में बात की है. हम इसके लिए चीन के साथ काम करने को इच्छुक हैं. राष्ट्रपति बाइडन ने स्पष्ट कहा है कि कुछ मुद्दों पर हमारा मतभेद होगा. यह छुपा नहीं है और भारत के संबंध भी चीन के साथ तनावपूर्ण हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने सामने खड़े ऐसे संकट को नजरअंदाज कर दें, जिसका समाधान हम सब मिलकर ही निकाल सकते हैं और वह है जलवायु संकट. इसलिए, हमें जलवायु के मुद्दों को अन्य चीजों से अलग करना होगा. हम दूसरे विवादों के कारण इसकी अनदेखी नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि यह संभव है. चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2013, 2014 में सहयोग किया और हम अपने साझा प्रयासों की घोषणा कर सके थे. मुझे लगता है कि उस साझीदारी से पेरिस समझौते के निर्माण में काफी मदद मिली थी. अब, हमें ग्लासगो (नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन) के निर्माण के लिए काम करने की आवश्यकता है.

● मैं फिर से पेरिस समझौते की बात करना चाहता हूं क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रतिबद्धताएं जताई गई थीं, खासकर फंडिंग को लेकर. विकसित देशों की 2020 के बाद से 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता थी. वह लक्ष्य से काफी पीछे रह गया. यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं कि वह धन उपलब्ध हो? और क्या आप उन देशों को दंडित करना शुरू करेंगे जो उस कोष में योगदान नहीं करते हैं?

मुझे लगता है कि हमें सभी देशों को योगदान के लिए तैयार करने की जरूरत है. राष्ट्रपति बाइडन उस राशि का भुगतान करने जा रहे हैं जिसका वादा राष्ट्रपति ओबामा ने किया था लेकिन जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने रोक दिया था. इसलिए हम बकाया का भुगतान करेंगे लेकिन हम...राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करेंगे कि कुछ अतिरिक्त राशि का योगदान करें. इसलिए, यह इसमें बाइडन का योगदान होगा और यह हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के आकार के अनुरूप होगा.

मुझे विश्वास है कि 100 अरब डॉलर तक का योगदान मिल जाएगा. अभी हम 80 या उसके आसपास हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें केवल 100 अरब डॉलर पर नहीं रुकना चाहिए. यह पर्याप्त पैसा नहीं है. हमें खरबों डॉलर की जरूरत है और केवल निजी क्षेत्र ही ऐसा कर सकते हैं. इसलिए हम सबसे बड़े एसेट मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं. हम सबसे बड़े बैंकों के साथ काम कर रहे हैं. और सिर्फ बड़े नहीं. हम शुरुआत बड़े से कर रहे हैं और हमें निवेश के लिए सबको लेकर आना होगा. यह खैरात नहीं, बल्कि निवेश होगा. नई ऊर्जा के उपयोग को संभव करने के लिए पैसा चाहिए और हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, अधिक रोजगार सृजित करने, बेहतर स्वास्थ्य रखने, बेहतर सुरक्षा प्रदान करने जैसे बहुत से काम कर सकते हैं. हम यह सब तभी कर सकते हैं अगर इस नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ें और मुझे लगता है कि यह बहुत ही रोमांचक है.

> “कोई भी राष्ट्र अकेले ही जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान नहीं कर सकता. हर देश को समाधान का हिस्सा बनना होगा. हम एक दूसरे पर निर्भर हैं.”

22 अप्रैल का राष्ट्रपति बाइडेन का शिखर सम्मेलन इसी के लिए है. उसमें राष्ट्राध्यक्ष होंगे और हम अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रखेंगे. हम चाहते हैं कि दुनिया यह देखे कि हर देश क्या करने का संकल्प लेता है. और क्यों? क्योंकि ये 20 देश, 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो 81 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि यह न्यायोचित हो. हम उन छोटे राष्ट्रों के बारे में और विचारशील होना चाहते हैं जो 150 साल या उससे अधिक समय से दूसरों की करनी का दंड भोग रहे हैं. हमें पिछली गलतियां सुधारने के लिए बहुत तेज गति से काम करना होगा. हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं. तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ हमें ही करना होगा? नहीं, हम यह सब अपने आप नहीं कर सकते. हर देश को समाधान का हिस्सा बनना होगा. उदाहरण के लिए, छोटे देश जो अपनी ऊर्जा क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं, वे ऊर्जा के लिए कोयले पर आश्रित न हों. वे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाएं. नई ऊर्जा पर जाएं. गैस के लिए साझेदारी करें या अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन आपसी सहयोग की आवश्यकता है.

● जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के संदर्भ में भारत और दुनिया के लिए आप क्या बड़ा संदेश देंगे?

मेरा बड़ा संदेश यह है कि भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. यह विशाल बौद्धिक संसाधन, महान विचारों और आध्यात्मिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र है. यदि भारत के लोग, इसके साथ खुद को जोड़ लें तो यह संभव हो जाएगा. हम सभी के लिए चुनौती समय की है. हमारे पास बहुत समय नहीं है, यह शीघ्र करना होगा. और भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और बड़े उत्सर्जकों के साथ एक महत्वपूर्ण भागीदार है. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आना होगा कि हमारे बच्चे और नाती-पोते और उसके बाद की पीढ़ियों को ऐसी धरती मिले जो आज की तुलना में बेहतर हो. ■

एपी

खास रपट **साइरस मिस्त्री**

टाटा कहने का समय?

साइरस मिस्त्री 2016 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से हटाए जाने को लेकर कानूनी लड़ाई भी हारे. अब सबकी नजरें 153 साल पुरानी दिग्गज कंपनी से मिस्त्री परिवार की सम्मानजनक विदाई पर

एम.जी. अरुण

टा संस के पूर्व चेयरमैन और शापूरजी पलोनजी (एसपी) ग्रुप के चेयरमैन शापूरजी पलोनजी ग्रुप के वारिस 52 वर्षीय साइरस पलोनजी मिस्त्री के लिए कुछ भी सही होता नहीं जान पड़ता. इस साल 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर 2016 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से उन्हें हटाए जाने को सही ठहराया. भारत की निजी क्षेत्र की सबसे विशालकाय कंपनियों में से एक के शिखर पर रतन टाटा की जगह लेने के बाद वे महज तीन साल ही रह पाए थे. इस फैसले के बाद टाटा ग्रुप से मिस्त्री परिवार की विदाई का रास्ता साफ होने के साथ 84 साल का रिश्ता खत्म हो सकता है. यह रिश्ता 1936 में शापूरजी पलोनजी के टाटा संस में फाइनेंसर एफ.ई. दिनशॉ के वारिसों से 12.5 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के साथ शुरू हुआ था. यहां अहमियत केवल रुपए-पैसे की नहीं; दोनों घराने कभी इतने करीब थे कि साइरस के पिता पलोनजी मिस्त्री को टाटा साम्राज्य पर अपने जबरदस्त असर की वजह से टाटा समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस का फैंटम कहा जाता था. शीर्ष अदालत के फैसले से साइरस और टाटा संस के बीच तीन साल से चल रही लड़ाई का नया अध्याय शुरू हुआ है. साइरस का परिवार टाटा संस में 18.4 फीसद हिस्सेदारी के साथ टाटा ट्रस्ट्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है. 24 अक्तूबर 2016 को टाटा संस के बोर्ड से हटाए जाने के बाद साइरस को दूसरी कंपनियों के बोर्ड से भी हटा दिया गया. इस प्रक्रिया में वाडिया ग्रुप के चेयरमैन नुस्ली वाडिया सरीखे उनके समर्थकों को भी टाटा ग्रुप की कंपनियों से विदा होना पड़ा. अब जब कोर्ट का अंतिम फैसला टाटा के हक में हो चुका है, फोकस आगे की राह पर है.

टाटा ग्रुप के खिलाफ साइरस मिस्त्री की लड़ाई भारतीय कारोबार के इतिहास की सबसे तीखी लड़ाइयों में से एक के तौर पर जानी जाएगी. उन्होंने अपने हटाए जाने को कंपनी लॉ बोर्ड में चुनौती दी थी. जब वहां से राहत नहीं मिली तो उन्होंने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में दस्तक दी, जिसने दिसंबर 2019 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर उनकी बहाली का फरमान सुनाया. मगर टाटा ग्रुप मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गया, जिसने साल भर की

एसपी समूह

कुल राजस्व
₹51,100 करोड़

मुख्य कंपनियां

शापूरजी पलोनजी ऐंड कंपनी (एसपीसी)
यह एसपी समूह की प्रमुख कंपनी है. इसकी उपस्थिति कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में है.
परिचालन आय
₹13,474 करोड़
कर अदायगी के बाद मुनाफा
₹368 करोड़

एसपी इंजीनियरिंग ऐंड कंस्ट्रक्शन*
भारत के इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र में शुरू से आखिर तक समग्र समाधानों में महारत

एसपी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट ऐंड कंस्ट्रक्शन*
बिजली, धातु और खनिज, औद्योगिक समाधान और भारत तथा वैश्विक बाजारों में प्रतिरक्षा और रासायनिक संयंत्रों सरीखी विशेष परियोजनाओं के क्षेत्रों में तैयारशुदा इंजीनियरिंग, प्रबंध और निर्माण समाधान देती है

शापूरजी पलोनजी फाइनेंस
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
राजस्व (2019-20)
₹183 करोड़
कर अदायगी के बाद मुनाफा
₹22 करोड़

एसपी इंटरनेशनल*
एसपी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट ऐंड कंस्ट्रक्शन की अंतरराष्ट्रीय शाखा

एसपी इंवेस्टमेंट एडवाइजर्स*
शापूरजी पलोनजी ऐंड कंपनी की 100 फीसदी आनुषंगिक कंपनी

एसपी ऑइल ऐंड गैस*
हाइड्रोकार्बन सेवा और समाधान प्रदाता

एसपी रियल एस्टेट*
1.3 करोड़ वर्ग फुट आवासीय और 60 लाख फुट व्यावसायिक संपत्तियां विकसित कर चुकी है

अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर
एक्सट्रीम इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं में महारत
राजस्व (2018-19)
₹8,876 करोड़
कर अदायगी के बाद मुनाफा
₹234 करोड़

यूरेका फोर्ब्स
वाटर प्यूरिफायर और वैक्यूम क्लीनर सरीखे उत्पादों के साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता पर फोकस
राजस्व (2019-20)
₹3,110 करोड़

स्टर्लिंग ऐंड विल्सन सोलर
इंजीनियरिंग,प्रोक्योरमेंट और निर्माण कंपनी
राजस्व (2019-20)
₹453.5 करोड़
कर अदायगी के बाद मुनाफा
₹31.1 करोड़

ओमान शापूरजी*
ओमान में निर्माण गतिविधियों पर फोकस

*वित्तीय आंकड़े उपलब्ध नहीं. स्रोत कंपनी की वेबसाइट, मीडिया रिपोर्ट

किस्मत का खेल

दिसंबर 2013
साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा से टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला

अक्तूबर 2016
टाटा संस ने मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया और रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया

दिसंबर 2016
छोटे निवेशकों को दबाने और कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए मिस्त्री नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) गए

जनवरी 2017
टाटा संस ने एन. चंद्रशेखरन को अंतरिम चेयरमैन बनाया

फरवरी 2017
मिस्त्री को टाटा संस बोर्ड में डायरेक्टर पद से हटाया गया

सितंबर 2017
टाटा संस के बोर्ड ने पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनने की योजना पर मुहर लगाई

जुलाई 2018
चेयरमैन पद से हटाने को चुनौती देने वाली मिस्त्री की याचिका एनसीएलटी ने खारिज की

दिसंबर 2019
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने मिस्त्री की चेयरमैन पद पर बहाली का आदेश देते हुए टाटा संस के प्राइवेट कंपनी वाले प्लान को अवैध बताया

मार्च 2021
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी का आदेश पलटा, मिस्त्री को हटाने का फैसला सही बताया

सुनवाई के बाद टाटा के हक में फैसला दिया. यह तो पूरी तरह साफ है कि टाटा और मिस्त्री परिवारों के बीच रिश्ता रसातल में पहुंच गया है, लिहाजा दोनों का जुदा होना महज वक्त की ही बात है. संभावना यही है कि मिस्त्री टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी टाटा परिवार को बेच देंगे, जिन्हें खरीद से पहले इनकार का अधिकार हासिल है. यह कदम उठाना जरूरी हो सकता है क्योंकि महामारी की तीखी मार इंजीनियरिंग, निर्माण और रियल एस्टेट के एसपी ग्रुप के मूल कारोबार पर पड़ी है और ग्रुप कर्जों के भारी बोझ से जूझ रहा है. उसने एकबारगी कर्जों को नए सिरे से पुनर्गठित करने के लिए कर्जदाताओं का दरवाजा खटखटाया है. रेटिंग एजेंसी आइसीआरए के मुताबिक, 150 साल पुराने एसपी ग्रुप की नियंत्रक कंपनी शापूरजी पलोनजी ऐंड कंपनी (एसपीसी) का कुल कर्ज अलग-थलग करीब 5,320 करोड़ रुपए और सब मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए है. एसपी ग्रुप का समेकित कर्ज वित्त वर्ष 2017 में 19,981 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 31,035 करोड़ रुपए हो गया (दोनों समूहों एसपी और एसपीसी ग्रुप के चेयरमैन साइरस के भाई शापूरजी पलोनजी हैं).

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले भी मिस्त्री परिवार ने शिकायत की थी कि उन्हें पूंजी उगाहने के लिए अपने शेयर वित्तीय फर्मों को गिरवी नहीं रखने दिया जा रहा है. एसपी ग्रुप ने टाटा संस में अपनी 18.4 फीसद में से आधी हिस्सेदारी 5.074 करोड़ रुपए के लिए एक्सिस बैंक और आइडीबीआइ बैंक को गिरवी रख दी है. मगर जब एसपी ग्रुप 3,750 करोड़ रुपए जुटाने के लिए टोरंटो स्थित ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के साथ बातचीत करता बताया गया, तो टाटा संस ने उसे और ज्यादा हिस्सेदारी गिरवी रखने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखना मिस्त्री परिवार के लिए कभी पहला विकल्प नहीं रहा. बीते दो सालों के दौरान एसपीसी ने फोर्ब्स ऐंड कंपनी, स्टर्लिंग ऐंड विल्सन, एफकॉन्स और स्टर्लिंग ऐंड विल्सन सोलर सरीखी ऑ

परेटिंग फर्म के अपने शेयर गिरवी रखे हैं. रिपोर्टों के मुताबिक कर्ज के संकट का पहला संकेत उस वक्त मिला जब पिछले साल जून में प्रोमोटर ग्रुप कंपनी स्टर्लिंग ऐंड विल्सन सोलर की बकाया रकम चुकाने से चूक गए.

हालांकि प्रोमोटर्स ने वित्त वर्ष 2020 में एसपीसी में 3,875 करोड़ रुपए का निवेश किया जिसमें स्टर्लिंग विल्सन सोलर लि. के पब्लिक ऑफर से मिले 1,900 करोड़ रु. भी शामिल हैं. यह धन ग्रुप की कई कंपनियों की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए लगाया गया. आइसीआरए का एक नोट कहता है, 'एसपी ग्रुप ने टीएसपीएल (टाटा संस प्राइवेट लि.) में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है और टाटा समूह ने भी इस हिस्सेदारी को खरीदने में अपनी रजामंदी जाहिर की है जो कि लंबी अवधि के लिहाज से एसपी ग्रुप के लिए सकारात्मक है पर अभी तक इस सौदे के लिए मूल्यांकन और समयावधि तय नहीं की गई है.'

तो टाटा संस में एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी का सही-सही मूल्य निर्धारण कितना होगा? सितंबर 2020 में जब उसने टाटा संस से अलग होने का फैसला किया था, एसपी ग्रुप ने 1.78 लाख करोड़ रुपए के मूल्य निर्धारण की बात कही थी. अलबत्ता टाटा ने उनकी हिस्सेदारी इससे आधी ही आंकी और कहा, चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाइ.एच. मालेगाम ने 2016 में टाटा संस का मूल्य निर्धारण 3.8-4.3 लाख करोड़ रुपए के बीच किया था, लिहाजा एसपी ग्रुप की 18.6 फीसद हिस्सेदारी का मूल्य करीब 70,000-80,000 करोड़ रुपए है. टाटा परिवार एसपी ग्रुप को टाटा संस की हिस्सेदारी बेचने से रोकने में भले कामयाब रहा हो, मगर मिस्त्री परिवार से शेयरों की वापस खरीद में कई पेचीदगियां हैं. दोनों पक्षों को मूल्य निर्धारण पर राजी होना होगा और यह भी साफ नहीं है कि टाटा इस खरीद के लिए पैसा कहां से लाएंगे. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को छोड़कर टाटा के कारोबार भी भारी कर्ज के बोझ से दबे हैं. नियंत्रक कंपनी होने के नाते टाटा संस की आमदनी टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स सहित अपनी मुख्य आनुषंगिक कंपनियों से मिले लाभांश से होती है. वित्त वर्ष 2020 में इसने तमाम ग्रुप कंपनियों से अंशपूंजी लाभांश के तौर पर कुल 24,000 करोड़ रुपए की कमाई बताई. इसका करीब 90 फीसद अकेले टाटा कंसल्टेंसी से आया. लेकिन यह मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए काफी नहीं होगा. टाटा को समूह कंपनियों में अपने कुछ शेयर बेचने पड़ सकते हैं. मसलन, टीसीएस में टाटा संस की हिस्सेदारी 72 फीसद है, जिसमें से एक हिस्सा वह बेच सकती है. हालांकि बाजार के एक सूत्र का कहना है, ''इसकी कोई संभावना नहीं है कि टाटा इस मोड़ पर समूह कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहेंगे. टाटा संस मिस्त्री की हिस्सेदारी खरीदने के लिए लंबे वक्त के कर्ज से पूंजी जुटा सकते हैं.''

मिस्त्री के मामले में विशेषज्ञ कहते हैं कि एसपी ग्रुप को अपने शेयर टाटा को ही उचित मूल्य पर बेचकर सौहार्द्रपूर्ण तरीके से बाहर होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के वकील एच.पी. रनीना कहते हैं, ''मिस्त्री पर फैसले के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस को प्राइवेट कंपनी बनाने का फैसला भी बहाल रखा था. एसपी ग्रुप को टाटा संस जैसी कंपनी में निवेश से प्रबंधन में हिस्सेदारी या वोटिंग का अधिकार नहीं मिल जाएगा. वे सिर्फ सालाना डिविडेंड ही पा सकेंगे.'' रैना कहते हैं कि मूल्य निर्धारण के लिए कोर्ट जाने का बहुत मतलब नहीं है. जो मूल्य बताया जा रहा है, उसे स्वीकार करें. एसपी ग्रुप अपने शेयर न बेच सकता है और न ही गिरवी रख सकता है. लिहाजा यह उसके लिए सिरदर्द ही है. 70,000 से 80,000 करोड़ रु. जिसकी पेशकश टाटा कर सकते हैं, वाजिब दिखती है. मिस्त्री-टाटा विवाद का आर्थिक समाधान जो भी हो दोनों के रास्ते कानूनन अलग हो चुके हैं. ■

मनीष अग्निहोत्री

बिखराव के संकेत
मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या भाजपा के टिकट पर मैनपुरी जिला पंचायत सदस्य चुनाव का पर्चा भरते हुए

उत्तर प्रदेश **समाजवादी पार्टी**

मुलायम परिवार में गहरी होती दरार

प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे में आपसी कलह गहराती जा रही. भाजपा ने इसका फायदा उठाते हुए उसके प्रभाव वाले इलाकों में अपनी मोर्चेबंदी तेज की

आशीष मिश्र

कभी अपने राजनीतिक रंग के लिए देश भर में पहचानी जाने वाली सैफई की होली में इस बार 29 मार्च को दूसरे ही रंग दिखाई दे रहे थे. हर बार समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इटावा में अपने गांव सैफई में परिवार समेत होली खेलते आ रहे थे. होली का त्योहार ही एक ऐसा मौका होता था जब सैफई में मुलायम का पूरा परिवार रंग खेलने जुटता था. इस बार सेहत ठीक न होने की वजह से मुलायम सिंह यादव ने सैफई में होली से दूरी बनाए रखी थी. वे लखनऊ स्थित अपने आवास पर ही मौजूद थे. मुलायम की गैर मौजूदगी में सैफई की होली दो खेमों में बंट गई थी. एक खेमे में जहां उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव थे तो दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, भाई रामगोपाल यादव और परिवार के तमाम छोटे-बड़े राजनीतिक, गैर राजनीतिक सदस्य थे. सैफई में मुलायम की कोठी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने समर्थक परिवारिक सदस्यों और नेताओं के साथ होली का मंच सजाए हुए थे. तो यहां से कुछ ही दूरी पर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया का गठन कर चुके शिवपाल सिंह यादव पिता सुधर सिंह के नाम पर स्थापित किए एसएस मेमोरियल स्कूल में होली का जश्न मना रहे थे. मुलायम के आंगन में मन रहे होली के जश्न में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेजप्रताप यादव दिखाई दिए वहीं शिवपाल अपने बेटे आदित्य और समर्थकों के साथ एसएस मेमोरियल में ही रहे. इस तरह पहले जहां होली के मौके पर मुलायम कुनबा घर के आंगन में एक साथ जमा हुआ करता था, इस बार पूरी तरह से अलग-थलग नजर आया. होली के त्योहार ने यह संकेत कर दिया था कि चाचा और भतीजे के बीच दूरियां अब एक न मिटने वाली हकीकत बन गई हैं.

सैफई कुनबे के भीतर चल रही खींचतान उस वक्त और उजागर हुई जब मुलायम की भतीजी संध्या यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी घोषित कर दिया. संध्या मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई अभय राम यादव की बेटी और बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बड़ी बहन हैं. संध्या ने 7 अप्रैल को भाजपा नेताओं के साथ मैनपुरी जिला पंचायत के वार्ड संख्या 18 के जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया.

यह पहला मौका है जब मुलायम परिवार का कोई सदस्य भाजपा के टिकट पर चुनाव में उम्मीदवार बना है. संध्या ने 2015 में सपा के टिकट पर ही मैनपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था. इनके पति अनुजेश प्रताप यादव मैनपुरी जिले से सटी भारौल रियासत से संबंध रखते हैं. अनुजेश की मां उर्मिला यादव मैनपुरी की घिरौर सीट से सपा की पूर्व विधायक हैं. अनुजेश के परिवार के शिवपाल सिंह यादव से अच्छे रिश्ते हैं. इसी वजह से जुलाई, 2017 में सपा मैनपुरी की तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष संध्या यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी. नाम न छापने की शर्त पर मैनपुरी के एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य बताते हैं, ''संध्या यादव के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में कुल 32 जिला पंचायत सदस्यों में से 23 के हस्ताक्षर थे. चूंकि उस वक्त तक प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई थी. भाजपा ने संध्या की मदद की और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका. भाजपा की मदद से अपनी कुर्सी बचाने के बाद संध्या का परिवार भगवा खेमे के करीब आ गया.'' मार्च, 2019 में संध्या के पति अनुजेश भाजपा में शामिल हो गए. इसके बाद बदायूं के पूर्व सांसद और संध्या यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने एक पत्र जारी कर अनुजेश के परिवार से कोई भी रिश्ता न रखने का ऐलान किया था.

हालांकि संध्या का सैफई से पारिवारिक संबंध बना रहा. वे अपने पिता अभय राम यादव की सेहत का हालचाल लेने सैफई आती रहीं. अब भाजपा के टिकट पर संध्या के मैनपुरी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने पर धर्मेंद्र किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इंकार करते हैं. हालांकि धर्मेंद्र के नजदीकी लोग दो वर्ष पूर्व जारी की गई उस चिट्ठी का हवाला देते हैं जिसमें उन्होंने अनुजेश के परिवार से कोई भी रिश्ता न रखने का ऐलान किया था. अखिलेश के सबसे करीबी नेता और सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं, ''समाजवादी पार्टी से भाजपा डरी हुई है. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ऐसे कई काम करेगी. इससे सपा और मजबूत होगी.''

दरअसल, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम कुनबे में वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी. इसी के बाद अखिलेश ने सपा पर अपना एकछत्र राज कायम कर लिया था. इस घटना के बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच खाई और गहरी हो गई थी. विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल ने सपा से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) का गठन कर लिया था. शिवपाल के अलग पार्टी बनाने के बाद सपा ने नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी से चार सितंबर, 2019 को दल परिवर्तन के आधार पर शिवपाल यादव की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने की याचिका दायर करवाई. मुलायम के सीधे हस्तक्षेप के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव याचिका वापस लेने को राजी हुए. 23 मार्च, 2019 को नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के नेता रामगोविंद चौधरी ने यह कहते हुए शिवपाल की सदस्यता रद करने की याचिका वापस लेने की अर्जी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी कि पिछले वर्ष 4 सितंबर, 2019 को याचिका प्रस्तुत करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और अभिलेख संलग्न नहीं किए जा सके थे. इसी के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उसे स्वीकार करते हुए याचिका वापस कर दी थी. इससे शिवपाल की विधानसभा सदस्यता खत्म होने से बच गई थी. इसके बाद से अखिलेश और शिवपाल के बीच की तल्खी कुछ कम होती दिखी थी.

पिछले वर्ष लॉकडाउन लागू होने के बाद मुलायम की तबियत खराब होने के चलते उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. इस दौरान मुलायम के साथ अस्पताल में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मौजूद थे तो शिवपाल भी लगातार अस्पताल में मौजूद रहकर बड़े भाई के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे. स्वास्थ्य में लाभ होने के बाद भी मुलायम शिवपाल और अखिलेश के बीच पनपी खटास को कम करने की कोशिश में लगे रहे. इसका असर भी दिखा. विधानसभा सदस्यता रद करने की मांग करने वाली याचिका वापस लेने के बाद शिवपाल ने भी भतीजे अखिलेश को पत्र लिखकर उनकी तारीफ करते हुए आभार जताया था. लेकिन इस बार होली के त्योहार ने शिवपाल और अखिलेश के बीच सुलह की कोशिशों के परवान न चढ़ने का संकेत दिया.

मुलायम परिवार की भीतरी जंग ने भाजपा को यादव बेल्ट में पांव पसारने का मौका दिया है. यूपी की इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और कन्नौज लोकसभा सीटों पर मुलायम सिंह यादव परिवार का काफी प्रभाव रहा है. इन चार लोकसभा क्षेत्रों में कुल 20 विधानसभा सीटें आती हैं. 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए इन 20 सीटों में से 17 सीटें जीती थीं. भाजपा ने एक और बसपा ने दो सीटों पर कब्जा जमाया था. मैनपुरी के वरिष्ठ वकील अजय सिंह बताते हैं, ''2012 के विधानसभा चुनाव में एकजुट रहने वाला मुलायम परिवार पांच साल बाद 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल के खेमे में बंट गया था. इसका खमियाजा उसे 2017 के

मनीष अग्निहोत्री

कमजोर पड़ता मसीहा

बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के चलते मुलायम (बाएं) अब अखिलेश और शिवपाल में ज्यादा बीचबचाव भी नहीं कर पा रहे

''किसी घर का तब टुकड़ा होता है, जब उस घर में कोई न कोई शकुनि जैसे लोग होते हैं. हमारे घर में भी शकुनि जैसे लोग हैं.''

–शिवपाल सिंह यादव,
नेता, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)

''भाजपा अगर समझती है कि मुलायम परिवार में फूट डालकर समाजवादी आंदोलन को कमजोर कर सकती है, तो यह उसकी भूल है. इससे सपा और मजबूत होगी.''

–राजेंद्र चौधरी, सपा के मुख्य प्रवक्ता

विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा. 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली सपा 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें ही जीत सकी थी.'' 2017 के विधानसभा चुनाव में मुलायम के प्रभाव वाली चार लोकसभा सीटों की 20 विधानसभा सीटों में से सपा केवल छह ही जीत सकी. दूसरी ओर भाजपा ने कुल 14 सीटों पर कब्जा जमाया था. इसके बावजूद भाजपा मैनपुरी की पांच विधानसभा सीटों में से केवल एक ही जीत सकी जबकि सपा ने चार सीटों पर कब्जा जमाया था. 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा मुलायम परिवार के गढ़ मैनपुरी समेत आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ बनाने मे जुट गई थी. इसके लिए भाजपा ने मैनपुरी से सटे जिले एटा के वरिष्ठ नेता हरनाथ सिंह यादव को मार्च, 2018 में राज्यसभा चुनाव जितवाकर सांसद बनवाया था. भाजपा ने यादव बहुल इलाकों में सपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का एक अभियान भी शुरू किया था. 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखा था. 2014 में मैनपुरी लोकसभा सीट से साढ़े तीन लाख से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव जीतने वाले मुलायम 2019 में अब तक के सबसे कम मार्जिन यानी करीब 93,000 मतों से ही लोकसभा चुनाव जीत पाए थे. 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज और फिरोजाबाद लोकसभा सीट सपा के हाथ से निकल गई थी. इटावा के राजकीय डिग्री कालेज के पूर्व प्राचार्य आर.पी. सिंह बताते हैं, ''2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज और फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर सपा की हार अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच चल रहे द्वंद का ही नतीजा थी. भाजपा ने इसका पूरा फायदा उठाया था.''

भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से मुलायम के गढ़ मैनपुरी में पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है. भाजपा नेता मानते हैं कि बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते मुलायम शायद 2024 का लोकसभा का चुनाव न लड़ें और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वे पहले की तरह सक्रिय न रह पाएंगे. इसके लिए भगवा खेमे ने मैनपुरी में खुद को राजनीतिक विकल्प के रूप में तैयार करना शुरू किया है. पिछले लोकसभा चुनाव के बाद अगस्त 2019 में मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामनरेश अग्निहोत्री को योगी आदित्यनाथ सरकार में आबकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी गई. अक्तूबर, 2020 में मैनपुरी में सक्रिय नेता गीता शाक्य को भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया था. राज्यसभा सांसद बनने के बाद गीता लगातार मैनपुरी के शाक्य बहुल इलाकों में सक्रिय हैं.

संध्या यादव से पहले 2010 में मैनपुरी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाले आशु दिवाकर को भी पार्टी में शामिल कर भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को कड़ी चुनौती देने की तैयारी की है. कानपुर के क्राइस्ट चर्च कालेज में राजनीति शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर आशुतोष सक्सेना कहते हैं, ''मुलायम सिंह यादव का परिवार तीन राजनीतिक खेमों में बंट चुका है. सपा के पुराने नेता मुलायम खेमे के साथ हैं तो युवा नेता अखिलेश यादव के साथ. अखिलेश का विरोधी खेमा शिवपाल सिंह यादव के साथ है. मुलायम बढ़ती उम्र और खराब सेहत की वजह से राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं. इससे यादव मतदाता दुविधा में है. इसी का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भाजपा कर रही है.'' 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा कि मुलायम परिवार की भीतरी जंग से सपा अक्षुण्ण रह पाती है या फिर भाजपा को फायदा होता है. ■

भारत की एटमी शार्क

भारत की पनडुब्बी ताकत को पैना करने में काफी लंबा वक्त लग गया और एक बहुप्रतीक्षित परियोजना को अब जाकर कैबिनेट की सुरक्षा समिति की मंजूरी मिलने वाली है. एटमी क्षमता वाली हमलावर पनडुब्बी परियोजना में इतनी देरी क्यों हुई

संदीप उन्नीथन

इलस्ट्रेशन: **नीलांजन दास**

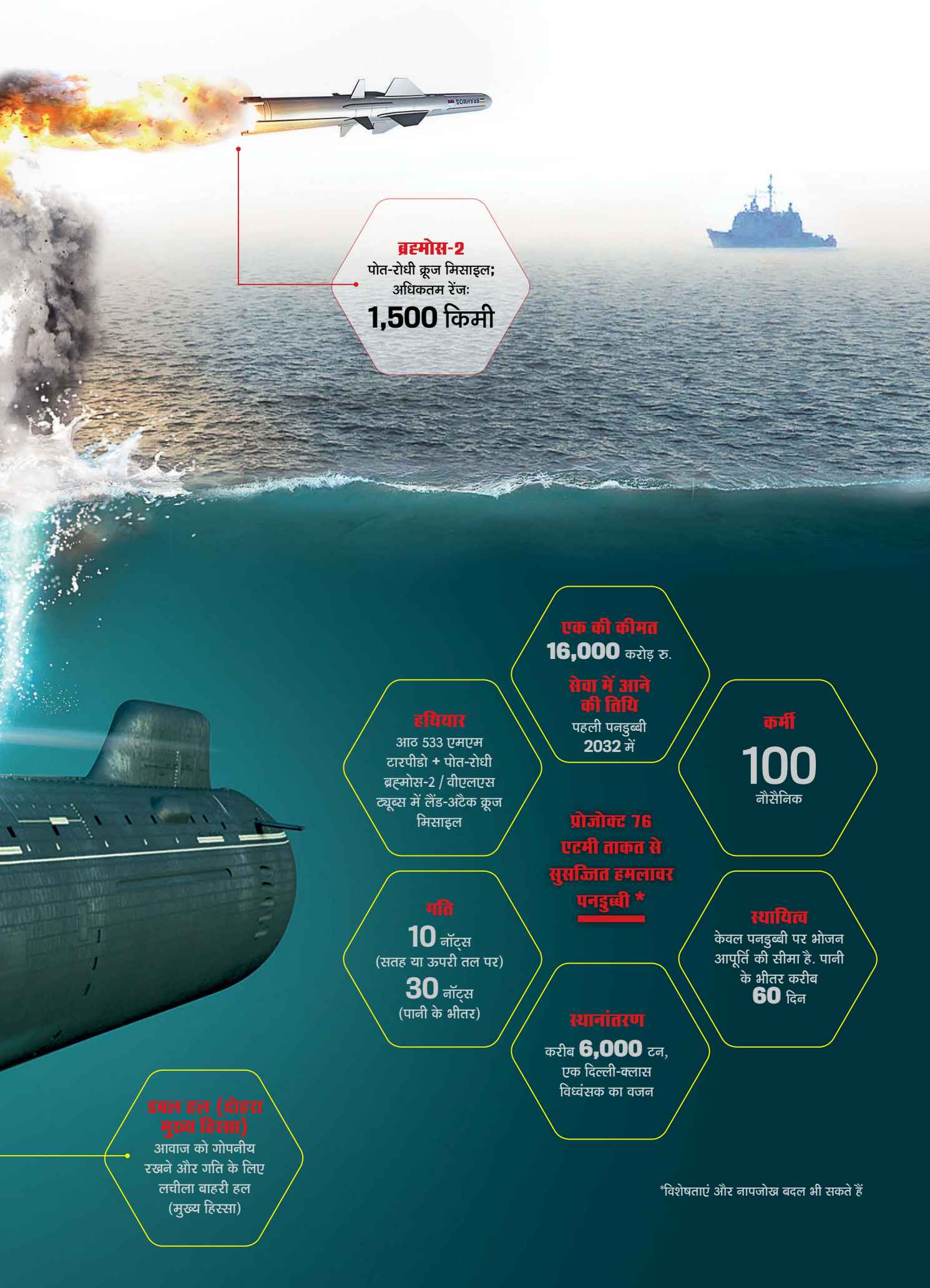
ब्रह्मोस-2
पोत-रोधी क्रूज मिसाइल;
अधिकतम रेंज:
1,500 किमी
एक की कीमत
16,000 करोड़ रु.
सेवा में आने की तिथि
पहली पनडुब्बी
2032 में
हथियार
आठ 533 एमएम टारपीडो + पोत-रोधी ब्रह्मोस-2 / वीएलएस ट्यूब्स में लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल
कर्मी
100
नौसैनिक
प्रोजोक्ट 76
एटमी ताकत से सुसज्जित हमलावर पनडुब्बी *
गति
10 नॉट्स
(सतह या ऊपरी तल पर)
30 नॉट्स
(पानी के भीतर)
स्थायित्व
केवल पनडुब्बी पर भोजन आपूर्ति की सीमा है. पानी के भीतर करीब
60 दिन
स्थानांतरण
करीब 6,000 टन,
एक दिल्ली-क्लास विध्वंसक का वजन
डबल हल (दोहरा मुख्य हिस्सा)
आवाज को गोपनीय रखने और गति के लिए लचीला बाहरी हल (मुख्य हिस्सा)
*विशेषताएं और नापजोख बदल भी सकते हैं

भा

रत के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने इस साल 4 मार्च को गुजरात के केवड़िया में हुए कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में एक पावरपॉइंट प्रजेंटेशन दिया, जिसे बनाने में कुछ महीने लगे थे. 96,000 करोड़ रुपए की लागत से एटमी शक्तिसंपन्न छह हमलावर पनडुब्बियां (एसएसएन) देश में ही बनाने का प्रस्ताव करीब 18 महीनों से मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति (सीसीएस) के पास अटका था, क्योंकि सरकारी अफसरों ने आर्थिक संकट के दौरान इन पनडुब्बियों की जरूरत पर सवाल उठा दिए थे. नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री पर जोर डाला और बताया कि समुद्र के भीतर भारत की लड़ाकू शक्ति का संकट दूर करने के लिए एसएसएन का जल्द निर्माण कितना जरूरी है. करीब 6,000 टन की हरेक पनडुब्बी पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा. 1980 के दशक में हासिल भारत की पारंपरिक पनडुब्बियों के बेड़े का बड़ा हिस्सा 30 साल का सेवा काल खत्म करने के करीब है. उनकी एवजी पनडुब्बियों को अफसरशाही लेट-लतीफी की मार झेलनी पड़ी है.

समुद्र में शक्ति घट रही है जब भारत के मुख्य शत्रु चीन ने शीत युद्ध के बाद सबसे बड़े नौसैन्य विस्तार का बीड़ा उठाया है. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की नौसेना जंगी जहाजों के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अगले दशक में इसका बढ़ना जारी रहेगा. वह न सिर्फ नए विमानवाहक पोत, एटमी पनडुब्बियां और सतहपोत जोड़ेगी, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुदूर तैनातियों से अपनी पहुंच का भी विस्तार करेगी.

एडमिरल करमबीर सिंह की आवाज काम कर गई. दो दशकों से रुकी हुई परियोजना के मामले में सीसीएस का शुरुआती गोली दागना अब तय है. सीसीएस की मंजूरी से सरकारी धन मिल जाएगा जिससे भौगोलिक तौर पर बिखरी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से चुनौतियों से भरी यह परियोजना शुरू हो सकेगी. परियोजना में गुरुग्राम में डिजाइन को अंतिम मंजूरी मिलना, कलपक्कम में एटमी रिएक्टर का निर्माण, हजीरा में ढांचा बनाना और पुर्जे जोड़ना तथा विशाखापत्तनम के पोत निर्माण केंद्र (एसबीसी) पर समुद्री परीक्षण शामिल हैं. पहली 6,000 टन की पनडुब्बी को पानी में उतारने में अभी एक दशक से ज्यादा लगेगा. माना जा रहा है कि एसएसएन परियोजना के लिए दूसरे स्वदेशी विमानवाहक पोत 65,000 टन वजनी आइएसी-2 के निर्माण की महत्वाकांक्षी नौसैन्य परियोजना को अब तिलांजलि दे दी गई है.

एसएसएन परियोजना भारत की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (एटीवी) की छाया में दब गई. एटीवी एटमी शक्ति संपन्न चार लड़ाकू मिसाइल पनडुब्बियों (एसएसबीएन) के निर्माण की टॉप सीक्रेट परियोजना है. आइएनएस अरिहंत 2016 में कमीशन किया गया और दूसरी इकाई एस3 इस साल कमीशन की जाएगी. दो और इकाइयां एस4 और एस4* 2025 में नौसेना में शामिल होंगी.

एसएसबीएन और एसएसएन दोनों एटमी विखंडन रिएक्टरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि संचालक दस्ते को चलाने के लिए जरूरी भाप उत्पन्न करने की खातिर भारी ताप पैदा कर सकें. एसएसबीएन सामरिक बमवर्षकों की तरह हैं, जो भयरोधक औजार के तौर पर अपनी नोक पर एटमी हथियार से लैस और दागी जाने को तैयार मिसाइलों के साथ समुद्र में चुपचाप मंडराते रहते हैं. एसएसएन समुद्र के भीतर वही हैं जो आसमान में लड़ाकू विमान हैं. डीजल-बिजली की पारंपरिक पनडुब्बियां असलियत में पानी में बस डूबी ही होती हैं. उन्हें अपने डीजल इंजनों को चलाने और अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने की खातिर नली के सहारे हवा खींचने के लिए पानी की सतह पर गोता लगाना होता है और इसी वक्त वे पता लगाए जाने के लिहाज से सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं. एसएसएन असल पनडुब्बियां हैं, इस लिहाज से कि वे लगभग अनिश्चित वक्त तक पानी के नीचे रहकर काम कर सकती हैं. उनकी यह क्षमता केवल क्रू के खाने की आपूर्ति से ही सीमित होती है. वे टारपीडो, ऐंटी-शिप क्रूज मिसाइलों और लैंड-अटैक क्रूज मिसाइलों जैसे विभिन्न सामरिक हथियारों से भी लैस होती हैं.

भारतीय नौसेना हिंद महासागर के अपने प्रभाव क्षेत्र में गश्त के लिए 1990 के दशक से ही कम से कम छह एसएसएन की जरूरत बताती आ रही है. फिलहाल उसके पास बस एक है—चक्र-2—जो 2012 में रूस से 10 साल की लीज पर ली गई है. चक्र-2 को समझौते की अवधि पूरी होने के साथ कुछ महीनों बाद लौटा दिया जाएगा. इसके कम से कम छह साल बाद इसकी उत्तराधिकारी, चक्र-3, नौसेना में शामिल होगी. इस पूर्व रूसी नौसैन्य एटमी शक्तिसंपन्न पनडुब्बी को मार्च 2019 में हुए 3 अरब डॉलर (21,000 करोड़ रुपए) के करार के तहत रूसी शिपयार्ड में भारतीय जरूरतों के मुताबिक ढाला जा रहा है.

चक्र-3 के आने से पहले नौसेना की समुद्रगत क्षमताओं में चार साल का अंतराल आ जाएगा. मगर यह बहुत बुरा खालीपन नहीं होगा. नौसेना उस 'गंवाए जा चुके दशक' को ताक रही है जिसमें 2020 के पूरे दशक में महज तीन पारंपरिक पनडुब्बियां हासिल करेगी, जबकि जरूरत उसे ऐसे कम से कम दर्जन भर जहाजों की है. नौसेना ने 1997 की पनडुब्बी निर्माण की अपनी 30 वर्षीय योजना में जो 24 पनडुब्बियों का अनुमान रखा था, उनमें से केवल छह हासिल की जा सकेंगी. स्वदेश निर्मित छह बड़ी पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 75आइ 15 साल से अटका है. ये पनडुब्बियां इंडोनेशियाई द्वीपों की समुद्री चौकियों के नजदीक काम कर सकती हैं. नौसेना की 15 पारंपरिक पनडुब्बियों के बेड़े का बड़ा हिस्सा 30 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है. इनमें से कुछ इनी-गिनी पनडुब्बियों का सेवा काल बढ़ाने के लिए उन्हें रूसी शिपयार्ड में अच्छा-खासा चुस्त-दुरुस्त किया गया है. अगले दशक में स्वदेशी एसएसएन का बेड़ा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वह मौजूदा संकट को हल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा.

गहराई में
आइएनएस चक्र की फाइल फोटो

भारत की रुक-रुककर चलती एसएसएन खोज

लड़ाकू विमानों की जगह पनडुब्बियों पर मोदी सरकार के विचार करने में लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकतकर के नेतृत्व वाली समिति की बड़ी भूमिका है. दिसंबर, 2016 में जब समिति ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसने तीसरे लड़ाकू विमान के प्रस्ताव को किनारे करते हुए और पनडुब्बियों को खरीदने की सिफारिश की. पर्रीकर ने भी खुलकर कहा था कि चीनी बेड़े का जवाब भारत केवल पनडुब्बियों को तैनात करके ही दे सकता है.

पर्रीकर शायद अमेरिकी खुफिया आकलनों की बार-बार दी गई चेतावनियां जानते थे. पीएलए नौसेना तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही उसकी दुखती रग यानी पनडुब्बी-विरोधी युद्ध क्षमताओं का अभाव भी बढ़ रहा था. इस कमजोरी का सबसे अच्छा फायदा एटमी शक्तिसंपन्न हमलावर पनडुब्बियों ने उठाया, जिन्हें एटमी रणनीतिकार रियर एडमिरल राजा मेनन (सेवानिवृत्त) ने ''समुद्री ताकत का निर्णायक पंच'' कहा था. एसएसएन समुद्र के भीतर 30 समुद्री मील प्रति घंटा (55 किलोमीटर प्रति घंटा) से ज्यादा रफ्तार से चलती है, जो नौसेना के सबसे ताकतवर सतह लड़ाकू पोत, दिल्ली-वर्ग के विध्वंसक पोत की शीर्ष रफ्तार है. समुद्र के नीचे बहुत तेजी से चलते हुए यह शत्रु युद्धपोतों का पीछा करके उन पर हमला बोल सकती है और भारी-भरकम मारक तारपीडो और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के अपने असलहे से निशानों को किनारे कर सकती है. उनकी मारकता और तकरीबन अभेद्यता से प्रेरित होकर यह लोकप्रिय मीम रचा गया है—'समुद्र में बस दो किस्म के पोत हैं, पनडुब्बियां और निशाने.' पनडुब्बी के ढांचे में बेहद क्षमतावान छोटा और सघन रिएक्टर फिट करने की प्रौद्योगिकीय जटिलता ने इस क्षमता को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों तक सीमित कर दिया है.

भारतीय नौसेना को एटमी क्षमता वाली छह हमलावर पनडुब्बियों की जरूरत है. पर इसके पास ऐसी एक ही पनडुब्बी है जिसका लीज भी खत्म होने वाला है

फिर आश्चर्य क्या कि खेल को बदल देने वाली इनकी उपयोगिता ने विशाल सत्ता स्वप्नों में डूबे सियासतदानों का ध्यान खींचा है. यहां तक कि उनका भी जिन्हें जमीन के पूर्वग्रहों से ग्रस्त माना जाता है. कभी गुरिल्ला बनकर पहाड़ी गुफाओं से काम कर चुके माओ जेदांग ने 1959 में कहा था कि भले ही '10,000 साल' लगें लेकिन चीन एटमी पनडुब्बियां बनाएगा. पहली चीनी एसएसएन 1974 में सेवा में शामिल हुई और इसका नाम चेयरमैन की जिंदगी की निश्चित घटना के आधार पर 'लॉन्ग मार्च-1' रखा गया. यह बहुत शोर और रेडियोधर्मिता पैदा करती थी, पर चीन ने कुलीन क्लब के आखिरी सदस्य के तौर पर इस पर जोर दिया.

यह घटना भारतीय योजनाकारों की नजरों से छिप नहीं पाई, जो अपने अप्रत्याशित उत्तरी पड़ोसी की तरफ से लहराए जा रहे एटमी हथियारों की आशंका से परेशान थे, खासकर जब उसके साथ वे 1962 में सरहद पर युद्ध लड़ चुके थे. 1974-79 में भारतीय प्रतिरक्षा योजना का मसौदा तैयार करने वाले कूटनीतिज्ञ डी.पी. धर की अध्यक्षता में सरकार की एपेक्स कमेटी-1 ने लिखा कि ''चीनी नौसेना की हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकने वाली एकमात्र ताकत उसकी पनडुब्बियों की ताकत है.'' मगर तब तक भारतीय सत्ता एसएसबीएन पर अपनी नजरें गड़ा चुकी थी. 1968 में तब प्रधानमंत्री

इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव पी.एन. हक्सर चीन के खिलाफ भयरोधक के तौर पर ''एटमी मिसाइलें ले जाने के लिए सुसज्जित एटमी शक्ति से संचालित पनडुब्बियों'' की जरूरत की रूपरेखा पेश कर चुके थे. एटीवी प्रोजेक्ट ने आधी सदी बाद 2018 में कहीं जाकर ठीक-ठाक समुद्रजन्य एटमी भयरोधक का निर्माण किया, जब आइएनएस अरिहंत पहली भयरोधक गश्त पर निकला.

सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि एसएसएन बेड़ा भारत की समुद्री ताकत में कई फायदे और बढ़त ले आएगा. वहीं, पूर्व परियोजना अफसरों का कहना है कि एसएसएन की योजना दो दशकों से ज्यादा वक्त से मुख्य रूप से इसकी बेहद ऊंची लागत की वजह से धीमे-धीमे आगे बढ़ी है. सामरिक एटीवी एसएसबीएन की लागत केंद्र सरकार ने अलग बजटीय मदों से चुकाई है, लेकिन इसके उलट एसएसएन का खर्च नौसेना उठाएगी. रक्षा बजट का सबसे छोटा हिस्सा—महज 14 फीसद—नौसेना के हिस्से में आता है, लिहाजा उसे नए युद्धपोत, विमान और पनडुब्बियां खरीदने के अपने खर्चों में तर्कसंगत तालमेल बिठाना होगा.

बजट की चिंताएं और विमानवाहक पोतों के प्रति नौसेना अफसरों का पूर्वग्रह बताता है कि प्रोजेक्ट 76 को शुरू होने में इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ी, जबकि सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी उसे 1998 में ही मिल चुकी थी. 2006 में तब प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार आर. चिदंबरम की अध्यक्षता में एक समिति ने उस टेक्नोलॉजी की पहचान की थी जिसकी एटमी पनडुब्बियों की नई पीढ़ी के विकास के लिए जरूरत थी—करीब 13,500 टन वजन की पांच नई 'एस-5' एसएसबीएन. दोनों डिजाइन स्वदेश में ही बने नए एटमी रिएक्टर से ताकत हासिल करते, जिनका डिजाइन बीएआरसी या बार्क (भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र) ने तैयार किया था. अव्वल कार्य प्रदर्शन करने वाला यह रिएक्टर, जिसकी क्षमता लगभग 190 मेगावाट मानी जाती है, अरिहंत वर्ग के 84 मेगावाट के रिएक्टर में बहुत सुधार करके बनाया गया है. नौसेना मुख्यालय के 2007 के एक पेपर ने 15 साल में (2022 तक) मैदान में उतारे जाने के लिए पहली इकाई की छह एसएसएन की औपचारिक जरूरत बताई थी. यह परियोजना अलबत्ता ठंडे बस्ते में पड़ी है, क्योंकि नौसेना की प्राथमिकता में पनडुब्बी के बजाए विमानवाहक पोत और सतह पोत रहे.

इस बीच पीएलए नौसेना से पनडुब्बी का खतरा असलियत बन चुका है. दिसंबर 2013 में चीनी शैंग वर्ग की एसएसएन की पहली सुदूर गश्त से नौसैन्य योजनाकारों को सुध आई कि पीएलए नौसेना उसके पिछवाड़े में कार्यरत है. यह एक कारक था जिसकी वजह से सरकार ने एसएसएन के डिजाइन अध्ययन के लिए फरवरी 2015 में ताबड़तोड़ सैद्धांतिक मंजूरी दी. दिसंबर 2016 में तब नौसैन्य प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने, जो इस परियोजना की बात स्वीकार करने वाले पहले सरकारी अफसर थे, नपे-तुले शब्दों में कहा, ''यह शुरू हो गई है. यह गोपनीय परियोजना है. प्रक्रिया चल पड़ी है.'' प्रोजेक्ट 75 पांच साल बाद भी डिजाइन के चरण में है. समझा जाता है कि नौसेना के पनडुब्बी डिजाइन ग्रुप (एसडीजी) को इसके डिजाइन को अभी अंतिम रूप देना है. इसमें अभी कम से कम दो साल और लगेंगे और तभी पनडुब्बी का ढांचा गढ़ने का काम शुरू हो सकेगा.

रक्षा बजट का सबसे छोटा हिस्सा—महज 14 फीसद—नौसेना को मिलता है. उसे नई पनडुब्बियां आदि खरीदने के लिए खर्चों में तालमेल बिठाना होगा

कलपुर्जों से बनी एकता

एसएसएन परियोजना में विभिन्न विभागों की क्षमताओं का इस्तेमाल होगा

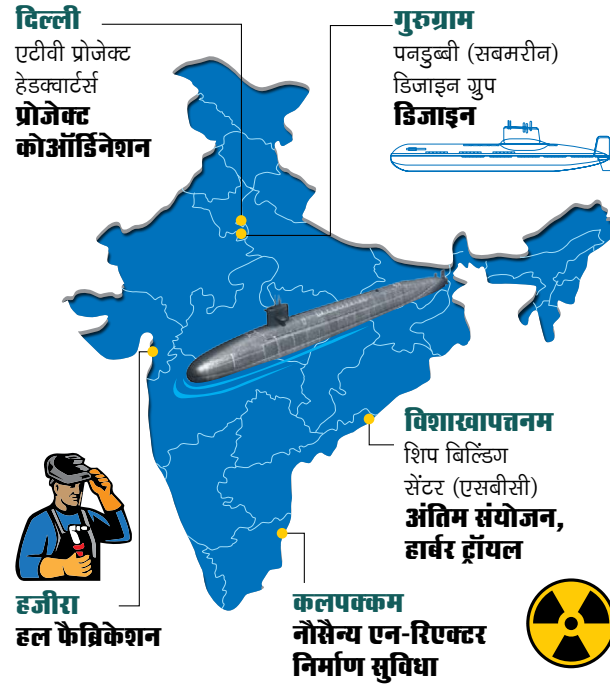

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

अमेरिकी नौसैन्य खुफिया दफ्तर का 2020 का एक आकलन अनुमान जाहिर करता है कि चीन की पनडुब्बी ताकत बढ़कर 2030 में 76 नावों (8 एसएसबीएन, 13 एसएसएन और 55 एसएस) की हो जाएगी. भारत की देरी बजट और नौकरशाही से संबंधित है.

दिसंबर 2020 में *इंडिया टुडे* को दिए एक इंटरव्यू में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था, ''कुछ भी जो सतह पर, यहां तक कि जमीन पर भी, और समुद्र पर चलता हो, चुना जाएगा.'' उन्होंने कहा था, ''आज हमें जमीन पर या समुद्र में कुछ भी मार गिराने की काफी कुछ सटीक प्रणालियां मिल गई हैं. इसलिए विमानवाहक पोत असुरक्षित होने जा रहे हैं. कोई कह सकता है कि वे चलते रहते हैं, पर चलते तो वे (शत्रु) भी रहते हैं...इसमें ताड़ते रहने की क्षमता है और ये इस आधार पर निशाना लगाते हैं कि अगले पल आप कहां होंगे.'' स्वदेशी एसएसएन को अब टेक्नोलॉजी की चुनौतियों से उबरना होगा. इससे पहले कि पनडुब्बी का डिजाइन तय करके इसके निर्माण का काम शुरू किया जा सके, एटमी वैज्ञानिकों को एक नया ताकतवर प्रेशराइज्ड जल रिएक्टर तैयार करना होगा. यह लंबी और कष्टदायक प्रक्रिया है, लेकिन उम्मीद है कि पहला कदम उठा लिया गया है. ■

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

यूपी की धान खरीद व्यवस्था में कई छेद
लालफीताशाही के शिकंजे में कारोबार
सरना: पुराने धर्म पर नई बहस
इंडिया टुडे
कोविड-19 वैक्सीन
कितनी सुरक्षित? कितनी कारगर?
बाजार में आने के लिए तैयार नई वैक्सीन से जुड़े सारे अहम सवालों के जवाब

राम मंदिर को माना गया मोदी की प्रमुख उपलब्धि
अनुच्छेद 370 हटाने को मिला जोरदार समर्थन
बेरोजगारी मानी गई सबसे बड़ी समस्या
इंडिया टुडे
देश का मिजाज सर्वेक्षण
मोदी और हिंदुत्व का बोलबाला
देशव्यापी छमाही सर्वेक्षण से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं और संघ परिवार के एजेंडे को मिली जबरदस्त बढ़त

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 25% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	3 वर्ष	156	~~6240~~	4680	25%
☐	2 वर्ष	104	~~4160~~	3330	20%
☐	1 वर्ष	52	~~2080~~	1770	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....

..... शहर..... राज्य..... पिन.....

मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें 18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें www.indiatoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

पहल पत्रिका/नजरिया

वैचारिक परिवार गढ़ा था *पहल* ने

अखिलेश

पहल जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका का बंद होना सचमुच तकलीफदेह है. सामान्य तौर पर कोई पत्रिका बंद होती है तो लगता है कि कोई दूसरी आकर उसकी जगह ले लेगी, उसमें रिक्ति का बोध उतना नहीं होता. लेकिन *पहल* के बंद होने से महसूस होता है कि साहित्यिक परिदृश्य पर एक बड़ी रिक्ति उपस्थित हो जाएगी. *पहल* के बगैर साहित्यिक दुनिया की बात नहीं हो सकती.

पर मेरा मानना है कि इसका शोक मनाने की बजाय एक ऐसी कोशिश हो कि जो जीवंतता हिंदी साहित्य की है, जो बेहतरीन रचनाशीलता है उसको सामने लाने के लिए अच्छे-अच्छे मंच बनें, अच्छी तैयारी के साथ काम किया जाए. यही *पहल* के साथ उपयुक्त सहभागिता होगी. उसका सम्मान अगर करना है तो इसी तरह किया जाना चाहिए.

पहल के बंद होने के बाद जहां तक उसके आकलन की बात है, उसकी भूमिका की समीक्षा की बात है तो एक यही कि अच्छी पत्रिका के रूप में तो उसकी उपस्थिति सदैव रही. दूसरे, वैचारिक खलबली से भरी हुई जो रचनाशीलता थी, उसको वह समानांतर ढंग से एकजुट भी करती रही. मैं *पहल* के दूसरे दौर की बात नहीं कर रहा, जब यह बंद होकर फिर से शुरू हुई. अगस्त 1973 में *पहल* की शुरुआत से लेकर एक चौथाई सदी तक वह शिखर साहित्यिक पत्रिका के रूप में स्थापित थी, इस अवधि में वैचारिक हलचल भरे समाज में उसने एक परिवार जैसा भाव पैदा किया.

पहल एक ऐसे समय में निकली थी जब हिंदी समाज में एक वैकल्पिक समाजवादी समाज का स्वप्न बड़ा जीवंत था. उसमें सब लोगों ने *पहल* को एक आंदोलन की तरह लिया. कोई उसके मेंबर बना रहा है, कोई कहीं दूरदराज से विज्ञापन ला रहा है. तो यह एक बड़ा सामूहिक प्रयास था *पहल* का.

पत्रिकाएं तो बहुत-से लोग निकालते हैं लेकिन वह ज्ञानरंजन के व्यक्तित्व का ही करिश्मा था जिसने बेहतर समाज का सपना पाले, देश के नए-पुराने ऐसे तमाम लिखने वालों को एक धागे में पिरोकर एक बड़ा परिवार बनाया. हिंदी में प्रतिरोध की जो रचनाशीलता थी, उस धारा के जो लेखक थे, उन सबको मिलाकर उन्होंने एक कुटुंब जैसा बना दिया. *पहल* के अवदान की चर्चा करते वक्त इस पहलू को ध्यान में रखना पड़ेगा. पत्रिकाएं निकलती रहेंगी, बहुत अच्छी भी निकलेंगी, उनका भी अवसान हो जाएगा, लेकिन ज्ञानरंजनजी ने एक दौर में यह जो काम किया वह अविस्मरणीय है, उसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए.

पहल के आकर्षण और उसके प्रति दीवानगी को इससे समझा जा सकता है कि जब हमारी पीढ़ी युवा थी, तब हम बड़े अधैर्य से उसके प्रत्येक अंक की प्रतीक्षा करते थे और उसकी प्रति आते ही उसे सबसे पहले छूने, पढ़ने और उस पर चर्चा करने की होड़ शुरू हो जाती थी. जब हम बड़े हुए तब भी हमारे वैचारिक, संवेदनात्मक जीवन में *पहल* ऊर्जा के स्रोत के रूप में बरकरार रही. अनेक बार मैं इस सवाल से रूबरू हुआ हूं कि मैं भी एक पत्रिका निकालता हूं और कथाकार भी हूं, तो मेरे उनसे कैसे संबंध रहें? बेशक वे मेरे हीरो की तरह रहे हैं. मैं उनकी कहानियों का प्रशंसक रहा हूं तो संपादन के इलाके में जिन उस्तादों ने इस कला के हुनर सिखाए उनमें ज्ञानजी बेहद खास हैं. किसी लेखक की श्रेष्ठ रचना अंततः अपने रचनाकार से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपनी अर्थवत्ता साबित करती है; *पहल* भी ज्ञानरंजन का कई हजार पृष्ठों तक फैला एक कृतित्व है. जो अपने संपादक से विमुक्त होने के बाद भी बहुत वक्त तक अपना महत्व सिद्ध करता रहेगा.

—कथाकार **अखिलेश** *हिंदी की चर्चित साहित्यिक पत्रिका तद्भव के संपादक हैं*

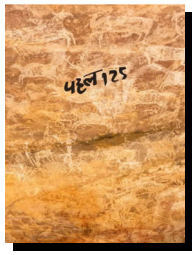

आखिरी अंक

***तथ्यों के आईने में* पहल**

शुरुआत: *1 अगस्त, 1973*

संपादक: *ज्ञानरंजन*

अंतिम अंक: *अप्रैल 2021*

कुल अंक निकले: *125*

व्यवधान: *नब्बे अंक निकलने के बाद 2009 में इसे बंद कर दिया गया था. पर दो-ढाई वर्ष बाद ज्ञानरंजन ने संपादन और दूसरी व्यवस्थाओं में कुछ नए लोगों से निरंतर सहयोग मिलने के भरोसे के बाद उन्हें टीम में जोड़कर इसे फिर शुरू किया. उसके बादी यानी उत्तरार्ध में इसके 35 अंक निकले*

इसने हिंदी के अलावा पंजाबी, मराठी, उर्दू, कश्मीरी और दूसरी भारतीय भाषाओं पर प्रामाणिक विशेषांक निकाले. चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं की उम्दा रचनाओं से इसने हिंदी के पाठकों को समृद्ध किया

पहल और साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में ज्ञानरंजन के शब्द

(साहित्य वार्षिकी 2019-20 को दिए गए एक साक्षात्कार में)

"जब मैंने संपादन की तरफ पैर बढ़ाए तब मैं *ग्रांटा, पेरिस रिव्यू, कल्पना, निकष, एनकाउंटर, पोएट्री* जैसी ऐतिहासिक पत्रिकाओं का सपना देख रहा था...

''*पहल* की भूमिका एक छोटी-सी रौशनी है, जब तक वह हार-थक नहीं जाती.''

''हिंदी में अधिकांश पत्रिकाएं एक-दूसरे जैसी हैं. उनके संपादकीय विचार और छपी सामग्री के बीच कोई साम्य नहीं है. उनमें आंचलिकता और क्षेत्रीयता भी काम करती है. स्थानीयता से भूमंडल की यात्रा ठप है. चूंकि कतार लगी है इसलिए सामग्री का अभाव नहीं रहता. दमदार और इंतजार की जाने वाली पत्रिकाओं का दौर समाप्त है."

***पहल* के बंद होने पर टिप्पणी**

"...*पहल* एक देह की तरह थी, जिसकी आयु भी है. यह आयु आ गई, इसको स्वीकार करते हैं... हम अमर नहीं थे और मर भी नहीं रहे हैं... हमारा ढांचा शिथिल पड़ रहा है क्योंकि यह महामारी जाने से इनकार कर रही है...हमारे कई साथी इसकी चपेट में चले गए. कुछ को वर्तमान अंधी सत्ता ने मौन और निष्क्रिय कर दिया. हम मुखौटे उतारते रहे और अब प्रतिदिन नए मुखौटे तैयार हो रहे हैं. ऐसे वक्त में हम आपसे विदा ले रहे हैं."

अपना सबसे बेहतर

साान्या मल्होत्रा मन लायक चीजें करते हुए बॉलीवुड के हाशिए से अब केंद्र में आ गईं

साान्या मल्होत्रा साथ काम करने वालों पर जबरदस्त छाप छोड़ती हैं. एक विज्ञापन फिल्म में उन्हें निर्देशित करने वाले अनुराग बसु पर भी उन्होंने अच्छी छाप छोड़ी. यह कुश्ती पर बनी ड्रामा फिल्म *दंगल* (2016) से बॉलीवुड में उनके धमाकेदार पदार्पण से पहले की बात है. पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज *लूडो* में उन्हें निर्देशित कर चुके बसु कहते हैं, ''आप कई अभिनेत्रियों से मिलते हैं, पर उनके व्यक्तित्व में विशिष्टता नहीं होती. उनके पास ऐसी शख्सियत है जो आपके साथ रह जाती है.'' रितेश बत्रा ने *फोटोग्राफ* (2019) बनाते वक्त 'बारीकियों पर ध्यान देने वाला' उनका नजरिया पहचाना. वे कहते हैं, ''जब अदाकार ने स्क्रिप्ट 300 बार पढ़ ली हो और उसे अपनी हड्डियों में महसूस करता हो तो अलग से पता चल जाता है. वे हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हैं.''

28 वर्षीया मल्होत्रा के लिए यह इस प्रतिस्पर्धी उद्योग में टिके रहने का अकेला तरीका है. वे कहती हैं, ''मैं हर फिल्म के साथ ऐक्टिंग और फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ न कुछ सीख रही हूं.'' लेकिन वे यह भी जोड़ती हैं कि कारोबारी पहलू के बारे में उन्हें कुछ अता-पता नहीं है. मुख्यधारा की फिल्म हो या स्वतंत्र, ओटीटी हो या सिनेमाघर, 300 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर हो या हैरतअंगेज हिट फिल्म, मल्होत्रा यह सब कर चुकी हैं. वे *डांस इंडिया डांस* टीवी शो के ऑडिशन के लिए 2014 में दिल्ली से पहली बार मुंबई आई थीं. इसमें वे बहुत दूर नहीं जा सकीं, पर अदाकारी की तलाश में उन्होंने टिके रहना तय किया. जल्द ही कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उन्हें दंगल में गीता फोगाट का किरदार निभाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया. आखिरकार उन्हें बबीता का किरदार मिला.

ताजातरीन फिल्म *पगलैट* के साथ मल्होत्रा को अंततः ऐसी फिल्म मिल गई जिसकी कहानी उनके किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है. वे कहती हैं, ''मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी, सोचती थी कि अपने कंधों पर एक फिल्म का भार उठा पाऊंगी या नहीं.'' लेखक-निर्देशक उमेश बिष्ट और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा को ऐसा कोई शक नहीं था. मल्होत्रा ने इस फिल्म में संध्या का किरदार मुकम्मल निभाते हुए अपने संगी-साथियों की वाहवाही जीती. संध्या विधवा है जो अपने पति की मौत पर अपनी मस्तमौला प्रतिक्रिया से परिवार को हैरत में डाल देती है.

इंस्टाग्राम पर गिनती बढ़ाने या बॉक्स ऑफिस की कमाई पर नजर रखने से ज्यादा अपनी भूमिकाओं को प्रमुखता देने वाली मल्होत्रा कहती हैं, ''मैं काफी पगलैट हूं, इस लिहाज से कि खुद अपनी चीजें करती हूं. खुद को प्रेरित करने वाले किरदार खोजना मेरी जिम्मेदारी है, तभी वे दूसरी औरतों को प्रेरित कर सकेंगे.''

—सुहानी सिंह

साान्या मल्होत्रा *पगलैट* में एक बेपरवाह विधवा युवती का किरदार निभाकर काफी वाहवाही बटोरी

महागाथाओं का नया उभार

हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रति भारतीय फिल्म उद्योग का प्रेम अपने पूरे उफान पर

सुहानी सिंह

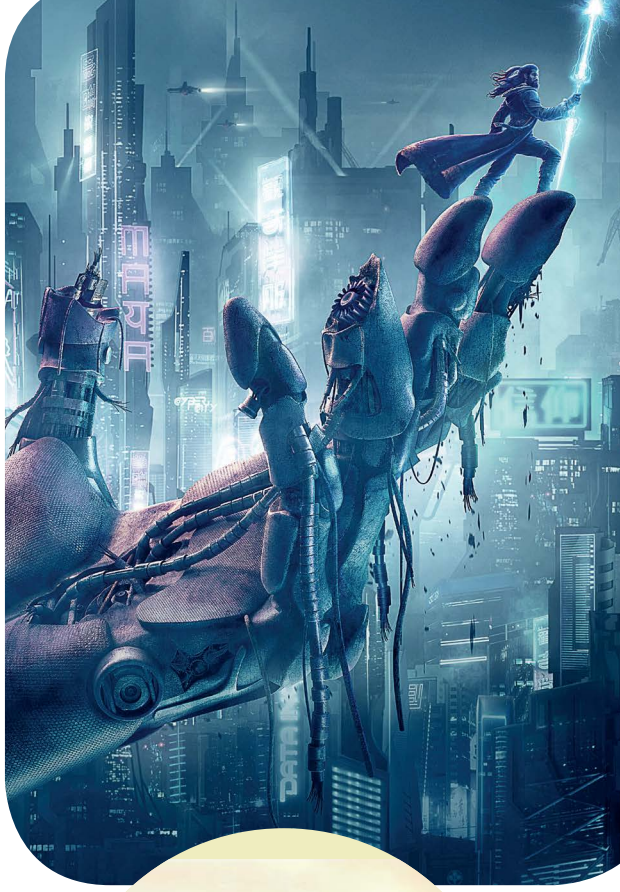

अक्षय कुमार की बिल्कुल नई फिल्म का सफर अयोध्या में रामजन्मभूमि से शुरू हुआ. यह कनाडाई नागरिक साथी अदाकारों नुसरत भड़ूचा और श्रीलंकाई अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस के साथ प्राइवेट जेट में भगवान राम का 'आशीर्वाद लेने' आया. पिछले साल दीवाली पर कुमार ने सोशल मीडिया पर अभिषेक शर्मा (*तेरे बिन लादेन*) के निर्देशन और चंद्रप्रकाश द्विवेदी (टीवी शो *चाणक्य* से जाने जाते रहे) के क्रिएटिव प्रोडक्शन में *राम सेतु* की घोषणा की थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''सच या कल्पना. युगों-युगों तक भारतीय जनमानस में भारत राष्ट्र के महापुरुष और सुपरहीरो भगवान श्री राम की पवित्र स्मृतियों को स्थायी और सुरक्षित करने के लिए इस दीवाली पर आइए एक सेतु का निर्माण करें जो पीढ़ियों को राम से जोड़े रखेगा. *राम सेतु* इस दिशा में हमारा विनम्र प्रयास है.''

फिल्म उन बहुत-से प्रोजेक्ट्स में से है जो हिंदू महाकाव्यों और उनके चरित्रों से उपजी कहानियां पेश करने के भारतीय फिल्म उद्योग के मौजूदा जुनून को सामने लाते हैं. बहुभाषी फिल्म *आदिपुरुष* की शूटिंग चल रही है जिसमें प्रभास राम का, कीर्ति सेनन सीता का और सैफ अली खान रावण का किरदार निभा रहे हैं. ऐसे ही दूसरे घोषित प्रोजेक्ट में 'महाभारत के विस्मृत योद्धाओं की महागाथा' और कवि तथा पूर्व राजनीतिक कुमार विश्वास की लिखी *सूर्यपुत्र महावीर कर्ण* और विकी कौशल की मुख्य भूमिका से सजी *उरी* के निर्देशक आदित्य कुमार की फिल्म *दि इम्मोर्टल अश्वत्थामा* शामिल हैं. नीतेश तिवारी की *रामायण,* कंगना रनौत के निर्देशन में *अपराजित अयोध्या* और दीपिका पादुकोण के निर्माण में उनके अभिनय से सजी *द्रौपदी* भी बन रही हैं. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी और प्रदर्शन का इंतजार कर रही *ब्रह्मास्त्र* भी रिलीज से पहले प्रोमोशन के लिए शिव की तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है.

सूर्यपुत्र महावीर कर्ण यह गाथा महाभारत के ही अहम किरदार कर्ण को केंद्र में रखकर रची गई है

इस शैली की बड़े बजट की फिल्मों का उभार किस चीज से प्रेरित है? *सूर्यपुत्र महावीर कर्ण* के निर्माता जैकी भगनानी के लिए हिंदू महाकाव्य कभी पुराने नहीं पड़ते. उन्हें लगता है कि उनका सदाबहार आकर्षण उनकी कई 'प्रेरक, भावनात्मक और ताकतवर कहानियों' में है. वे कहते हैं, ''मुझे लगता है महाभारत अलग-अलग नजरियों से बयान की जा सकती है क्योंकि इसकी कई सारी परतें अभी खुलनी हैं. पुरानी कहावत है कि ज्यादातर कहानियां महाभारत से प्रेरित हैं.''

विश्वास मानते हैं कि फिल्में हमेशा मौजूदा राजनैतिक निजाम की अभिरुचियों की झलक पेश करती हैं. वे कहते हैं, ''बीते 6-7 सालों के दौरान सार्वजनिक विमर्श बदल गया है. ऐसी पार्टी सत्ता में है जिसके लिए हमारी संस्कृति और धर्म प्राथमिकता है.'' मगर विश्वास मानते हैं कि कोई फरमान नहीं दे रहा कि कैसी फिल्में बनाएं बल्कि राजनैतिक आबोहवा ''ऐसी फिल्मों के लिए अनुकूल माहौल रच रही है.'' वे यह भी कहते हैं, ''जब वामपंथी रुझान वाली सरकार सत्ता में आती है, तो अभिव्यक्ति की आजादी, महिला सशक्तीकरण और एलजीबीटी के अधिकारों सरीखे मुद्दे आगे आ जाते हैं. आजकल आयुर्वेद, योग, धर्म और राम प्रासंगिक हैं.''

हिंदी सिनेमा का आख्यान वाकई हमेशा राजनीति से गुंथा रहा है.

द इम्मोर्टल अश्वत्थामा विकी कौशल की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म महाभारत के इस किरदार के जरिए साइंस-फिक्शन एक्शन ड्रामा पेश करती है

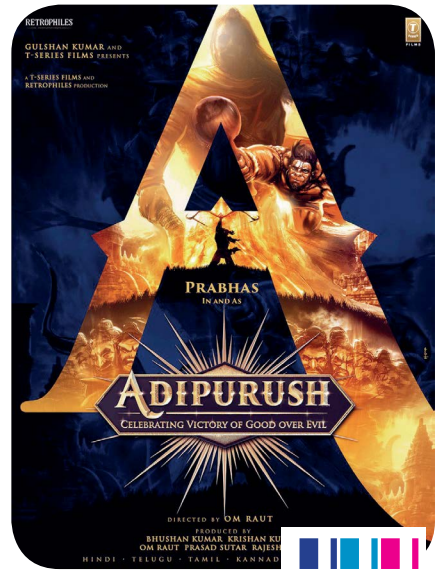

आदि पुरुष बहुभाषी प्रोजेक्ट का पोस्टर. इसमें प्रभाष राम, कृति सैनन सीता और सैफ अली खान रावण बने हैं

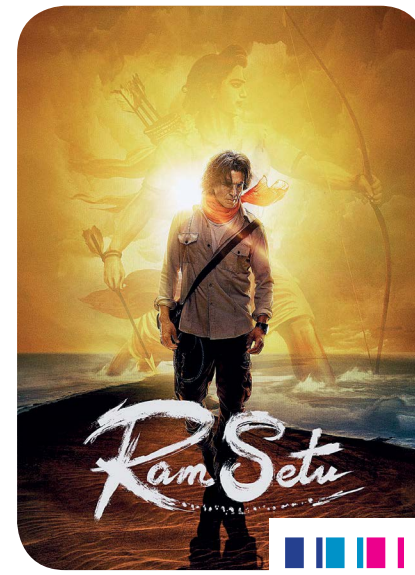

राम सेतु इसमें अक्षय कुमार पुरातत्ववेत्ता बने हैं. यह भारत-श्रीलंका के बीच नौवहन जलमार्ग बनाने को लेकर 2007 में आए कोर्ट के एक फैले पर आधारित है

प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान मनोज कुमार ने *उपकार* बनाई जिसने 'जय जवान, जय किसान' नारे को गुंजाया, तो इंदिरा गांधी के आपातकाल ने *किस्सा कुर्सी का* और *अंकुश* सरीखी फिल्मों के जरिये फिल्मकारों को सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति लोगों का गुस्सा भुनाते देखा. विश्वास इसमें प्रकाश झा की *सत्याग्रह* का जिक्र करते हैं जो उनके और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन पर बनी थी. वे कहते हैं, ''सार्वजनिक विमर्श सत्ता बदलने के साथ बदलता है और मैं नहीं समझता कि यह गलत या बुरा है. राजनीति हम सबको प्रभावित करती है.'' अब फिल्मकारों के भीतर भाजपा का 'जय श्री राम' का नारा गूंज रहा है. विश्वास को कर्ण पर काम करने का मौका उस वक्त मिला जब प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने यूट्यूब पर एक वीडियो में कवि को महाभारत के योद्धाओं की बात करते देखा. खुद को इतिहास का छात्र बताते हुए विश्वास कहते हैं कि उनका इरादा प्रामाणिकता और जिम्मेदारी के साथ कहानी बयां करने का है. वे उन हिस्सों को खारिज करने का दावा करते हैं जो महाभारत से अलग हटकर थे. वे मानते हैं कि दर्शकों का भरोसा कमाने की जिम्मेदारी पूरी तरह फिल्मकारों की है.

2020 की सबसे कामयाब फिल्म *तान्हाजी: दि अनसंग वारियर* के निर्देशक और *आदिपुरुष* पर काम कर रहे ओम राउत भी इस जिम्मेदारी को लेकर सतर्क हैं. वे कहते हैं कि जांच-पड़ताल भले की जाए लेकिन ऐतिहासिक किरदारों और घटनाओं पर आधारित सभी फिल्में जन भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचातीं. राउत कहते हैं, ''कुछ फिल्मों ने आम विश्वासों और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की, इसलिए हम सबको एक खांचे में रखकर यह नहीं कह सकते कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी हरेक फिल्म को तीखी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी. अगर आप चरित्रों की शुचिता बनाए रखते हैं तो गलती की संभावना कम से कम होगी.'' यही वह भरोसा है जिसके चलते राउत भारत के 'इतिहास की विशाल संपदा' से प्रेरणा ले पाते हैं.

कई प्रोड्यूसर महाकाव्यों में पैसा लगा रहे हैं और कई भाषाओं में विकसित और विजुअल इफेक्ट का खुलकर प्रयोग कर रहे हैं. मधु मांटेना ऐसे ही प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम तिवारी की *रामायण* और पादुकोण की *द्रौपदी* दोनों से जुड़ा है. वे कहते हैं कि भारतीय सिनेमा का सफर दादासाहब फाल्के की मूक फिल्म *राजा हरिश्चंद्र* सरीखी हमारे पौराणिक इतिहास से निकली कहानियों से शुरू हुआ था. दशकों बाद डीडी नेशनल पर रामानंद सागर की *रामायण* और बी.आर. चोपड़ा की *महाभारत* ने लाखों दर्शकों को अपने टेलीविजन से बांधे रखा. मंटेना कहते हैं कि आज की पीढ़ी को 'टेक्नोलॉजी के नए औजारों' के जरिए महागाथाएं सुनाने की जरूरत है. वे यह भी कहते हैं कि उनकी *रामायण* भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले भारतीयों के लिए है जिन्हें हमारी कहानियों और हमारे सिनेमा पर नाज है.

धर भी *दि इम्मोर्टल अश्वत्थामा* के जरिए यही करना चाहते हैं, जो रोनी स्क्रूवाला के बैनर आरएसवीपी की सबसे बड़ी फिल्म होगी. धर का इरादा महाभारत के किरदारों को आधुनिक वक्त की पृष्ठभूमि में साइंस-फिक्शन एक्शन ड्रामे में पेश करने का है. इस साल जनवरी में फिल्म का ऐलान करते हुए प्रेस नोट में उन्होंने कहा, 'हम एक ऐसा दृश्य चमत्कार रचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो पूरे भारत के दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा.'

बॉक्स ऑफिस पर भरोसा जगाने वाले बड़े सितारों की रहनुमाई इन फिल्मों की मदद ही करती है. राम के किरदार के लिए राउत की पहली पसंद प्रभास थे जिनकी लोकप्रियता *बाहुबली* के बाद आसमान छूने लगी. *रामायण* में सीता के लिए पादुकोण के नाम पर भी विचार किया जा रहा है. जैकी भगनानी कहते हैं, ''अगर व्यापक पहुंच और जबरदस्त लोकप्रियता वाले जाने-माने अदाकार को लाया जाता है तो निवेश ज्यादा फायदेमंद हो जाता है.''

यही वजह है कि राम सेतु में वास्तुकार का किरदार निभाने के लिए अक्षय कुमार को चुना गया. वे भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार के पसंदीदा के तौर पर देखे जाते हैं और उसकी कई पीएसए पहल का चेहरा हैं. *राम सेतु* की शुरुआत 2007 में हुई जब फिल्मकार को (जैसा कि निर्देशक शर्मा ने एक अग्रणी अखबार को बताया) ''भारत और श्रीलंका के बीच उथले समुद्री मार्ग पर नौवहन नहर के निर्माण की परियोजना और उसके सामने आ रहे मुद्दों से जुड़े'' एक अदालती मामले का पता चला. फिल्म के लिए तथ्यों पर आधारित पटकथा तैयार करने के लिए वास्तुविदों, इतिहासकारों और धर्म तथा विज्ञान के विशेषज्ञों की टीम जुटाई गई. शर्मा यह भी कहते हैं कि यह फिल्म ''भारत की पीढ़ियों को हमारी धरोहर के उस हिस्से से, जिसे समुचित ध्यान नहीं मिल पा रहा है, जोड़ने वाली एक सच्ची कहानी सामने लाने'' की उनकी कोशिश है. जब कुमार इसकी देख-रेख कर रहे हों तो इसे अपना जायज हिस्सा मिलना पक्का है. ■

सवाल + जवाब

बेचैनी और बैंड

शास्त्रीय गायिका **कौशिकी चक्रवर्ती** अपने सखी बैंड, बेटे की संगीत में रुचि, कृत्रिम तानपुरे और पिछला पूरा साल कोरोना की भेंट चढ़ने पर

● आपका नायाब क्रिएशन है सखी बैंड. इसका अब तक का अनुभव कैसा रहा? आरंभ के पीछे जो भावना थी, उसमें कहां तक सफल रहीं?

सखी बैंड आरंभ करने के पीछे किसी भी प्रकार का जेंडर भाव नहीं था. इसे पहले समझिए. मूल उद्देश्य विभिन्न विधाओं के मध्य एक रचनात्मक-संवाद था. इसमें शामिल सभी सोलो पेशकश करने वाले प्रतिभासंपन्न कलाकार हैं. पं. बिरजू महाराज, सुरेश तलवलकर और मेरे पिता की कंपोजीशन इसमें ली गई. देवी मां के स्वरूप को हम सांगीतिक रूपाकार में सेलिब्रेट करना चाहते थे. हमारे पास माध्यम संगीत था. इससे रसिक कनेक्ट होते हैं. प्रत्येक के प्रदर्शन से भी और सामूहिक नतीजे के रूप में भी.

● तकनीक के बढ़ते चलन ने मैनुअल तानपुरे को काफी नुकसान पहुंचाया है! इस बारे में आपकी क्या राय है?

एक समय बच्चों को दादी या नानी किस्से सुना कर सुलाया करती थीं. अब यह सुनाने वाले ऐप फोन पर उपलब्ध हैं. वे कहानी तो सुना देंगे लेकिन दादी की थपकी या उसके हाथों की ऊष्मा कहां से लाएंगे जिससे बच्चा कनेक्ट होता जाता था. तानपुरा टच करने की फीलिंग का कोई विकल्प हो नहीं सकता. उसमें वह बात कहां से पैदा होगी जो हम तानपुरे पर घंटों रियाज के बाद पाते हैं. कुदरती और कृत्रिम साउंड में जो फर्क है वही फर्क है मैनवल तानपुरे और ऐप में.

● एक वीडियो में आपका नन्हा पुत्र तबला संगति करता देखा जा रहा है. यानी उसका रुझान वाद्य की ओर है.

ढाई साल से उसे तबले का शौक लगा. अभी 12 वर्ष का है. गाने की तरफ भी रुझान बढ़ा है. लेकिन बतौर पेरेंट्स हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि कलाकार ही बने. वह खुद से ही रियाज करता है या हमारे साथ बैठ जाता है. ब्लड में तो स्वाभाविक रूप से जनरेशन का असर है, उसकी समझ देखकर भी महसूस होता है. आगे वो जो चाहे सो करे—उसी में हमारी खुशी!

● पिता पं. अजॉय चक्रवर्ती और आपके गाने में बुनियादी फर्क है. जबकि तालीम आपको भी पटियाला घराने की मिली, लेकिन आप सरगम के चमत्कारिक संयोजन से स्वयं की नई छवि गढ़ती हैं! इसके पीछे कोई फिलॉसफी?

बाबा का गाना और मेरा एक होगा—यह विचार बुनियादी रूप से गलत है! तालीम एक चीज होती है, और नकल एक चीज. गुरु संस्कार और रास्ता देते हैं. उस पर शिष्य को खुद की समझ और क्षमता के मुताबिक काम करना पड़ता है. पटियाला घराने में कितने गवैयों ने श्रोताओं को रिझाया—लेकिन सभी का रंग एक-दूसरे से अलग! यही तो सौंदर्य है. कौन जानता है, 20 साल बाद मेरा गाना भी कुछ और हो.

● यह वर्ष भी कोरोना के साए में गुजरता दिख रहा है! पिछला पूरा साल आपने मंच को बेहद मिस किया होगा?

परफॉर्मर का जीवन बड़ी आपाधापी वाला होता है. आज यहां तो कल वहां. अचानक बदली हुई परिस्थितियों ने सब रोक दिया, बेचैनी तो हुई! मंच और श्रोताओं के मध्य रहने की आदत टूट गयी तो इसका असर भी मन पर हुआ. डिस्टर्बिंग था पूरा साल. हमने अपने छोटे-से ट्रस्ट से जरूरतमंद कलाकारों तक सहायता भी पहुंचाई, जितना सामर्थ्य था.

—राजेश गनोदवाले

सुबीर हलदर

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE